भारतीय क्रांति के महान नेता
कामरेड मल्लोझला कोटेश्वरलु (रामजी) अमर रहें!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलिटब्यूरो सदस्य कामरेड कोटेश्वरलु की मृत्यु ने जनता और पार्टी कतारों को गहरे शोक में डुबो दिया। उनकी शहादत का दिन – 24 नवम्बर 2011 भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में एक दुखद दिन के रूप में अंकित होगा। वे एक महान नेता थे जिन्होंने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में विशिष्ट योगदान दिया। इसीलिए वे दुश्मन के लिए आंखों का कांटा बने थे। दुश्मन ने उनका हर पल पीछा किया। हालांकि वे कई बार बच गए थे, आखिरकार वे दुश्मन के जाल में फंस ही गए। कई विफलताओं के बाद दुश्मन ने उनकी हत्या करने में सफलता हासिल की।

देश के शासक वर्गों ने यह भली भांति जानते हुए भी कि मुठभेड़ की कहानियों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, बेशर्मी के साथ 24 नवम्बर को फिर एक बार वही कहानी सुनाई। ''पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कुशबोनी के जंगल में बुरिसोल गांव के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक घण्टे से ज्यादा समय तक चली भीषण गोलीबारी में भाकपा (माओवादी) के अग्रणी नेता कोटेश्वरराव उर्फ किशनजी मारा गया'' – यह था इस मनगढ़ंत कहानी का सारांश। भाकपा (माओवादी) को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कहकर प्रचारित करने वाले देश के शासक वर्ग और उनकी अगुवाई कर रहे सोनिया–मनमोहन सिंह–चिदम्बरम–प्रणब मुखर्जी–जयराम रमेश के फासीवादी शासक गिरोह के मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांठगांठ से की गई एक साजिशाना आपरेशन में कामरेड कोटेश्वरलु को जिंदा पकड़ने के बाद अमानवीय यातनाएं देकर कत्ल कर दिया गया।

दुश्मन ने कामरेड कोटेश्वरलु से इतनी क्रूरता से बदला लिया है कि सिर से लेकर पांव तक उनके पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया। जगित्याल से लेकर जंगलमहल तक अविराम मार्च करने वाले उनके पैरों को दुश्मन ने काट दिया। पांवों को हीटरों पर रखकर जला दिया। हर पल क्रांति का सपना देखने वाली उनकी आंख को बाहर निकाल दिया। ट्रिगर का ही नहीं, कलम का भी बखूबी से इस्तेमाल करने वाली उनकी हाथ की उंगली को काट दिया। शासक वर्गों के फासीवादी स्वभाव का पर्दाफाश करने का हथियार बन चुके उनके स्वर को मसल दिया। उनकी गरदन को शायद इसलिए संगीनों से काट दिया क्योंकि उन्होंने दुश्मन के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। आखिर में उनके मुंह में भी गोली मार दी गई जिससे भेजा बाहर निकल आया। उनके शव को देखने

वर्ष-24

अंक-1

अक्टूबर-दिसम्बर 2011

सहयोग राशि-10 रुपए

प्रभात

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

★ पीएलजीए की 10वीं वर्षगांठ और दण्डकारण्य संघर्ष की 30वीं वर्षगांठ पर विशेषांक ★

कामरेड कोटेश्वरलु की क्रांतिकारी जीवन–यात्रा

1954 26 नवम्बर को जन्म आंध्रप्रदेश, करीमनगर जिला, पेद्दापल्ली कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में। मधुरम्मा व वेंकटय्या की तीसरी संतान।

1969 पृथक तेलंगाना राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका।

1974 छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका। करीमनगर में स्नातक की पढ़ाई।

1974 पार्टी संगठक के रूप में कार्य शुरू।

1977 पार्टी के तेलंगाना क्षेत्रीय अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी।

1978 'जगित्याल विजयी यात्रा' के रूप में सुविख्यात किसानों की क्रांतिकारी उभार में अहम भागीदारी।

1978 पहली बार गठित पार्टी की करीमनगर–आदिलाबाद संयुक्त जिला कमेटी के सचिव के रूप में चुनाव।

1980 सितम्बर में पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के आंध्रप्रदेश अधिवेशन में राज्य कमेटी सदस्य के रूप में और उसके बाद में राज्य कमेटी सचिव के रूप में चुनाव।

1986 दण्डकारण्य आंदोलन में जिम्मेदारियों का निर्वाह।

1987 फरवरी में डीके में पार्टी का पहला अधिवेशन – फारेस्ट कमेटी सदस्य के रूप में चुनाव।

1993 सीओसी सदस्य के रूप में को–ऑप्शन और बंगाल का प्रभार।

1995 पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन में केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुनाव।

2001 पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) की 9वीं कांग्रेस में सीसीएम के रूप में चुनाव। पीबीएम व एनआरबी सचिव के रूप में जिम्मेदारियां।

2004 विलय में प्रमुख भूमिका। नई पार्टी भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद एकीकृत केन्द्रीय कमेटी सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्य और ईआरबी सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां।

2007 एकता कांग्रेस – 9वीं कांग्रेस में केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में दोबारा चुनाव। पोलिटब्यूरो व ईआरबी में सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां।

1993–11 18 सालों तक केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में काम।

2001–11 11 सालों तक पोलिटब्यूरो सदस्य के रूप में काम।

2011 24 नवम्बर को शहादत – पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के बुरिशोल जंगलों में कुशबोनी के पास हुई एक फर्जी मुठभेड़ में।

के बाद क्रांतिकारी लेखक संघ के नेता कामरेड वरवरराव ने कहा कि उन्होंने पिछले पैंतालीस सालों में, जबसे वे 'मुठभेड़' में मारे जाने वालों की लाशें देखते आ रहे हैं, ऐसा शव नहीं देखा जिस पर इतनी ज्यादा यातनाओं के निशान हों। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कामरेड कोटेश्वरलु को किस हद तक यातनाएं दी गई होंगी।

दुश्मन द्वारा की गई इस जघन्य हत्या के खिलाफ हर तरफ तीखा विरोध उठ खड़ा हुआ। जनता, जनवादी, बुद्धिजीवी, प्रगतिशील लेखक – सभी ने इस हत्या का पुरजोर खण्डन किया। देश भर में कई मानवाधिकार संगठनों, जनवादी संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और अन्य संगठनों ने इसकी निंदा की। कई संगठनों ने घटनास्थल पर जाकर तथ्यान्वेषण करके इस मुठभेड़ को फर्जी घोषित किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई क्रांतिकारी पार्टियों ने इस हत्या का विरोध करते हुए हमारी पार्टी के नाम शोक संदेश भेजे। और यहां की जनता और पार्टी कतारों के दुख को बांट लिया।

कई व्यक्तियों और संगठनों ने कामरेड कोटेश्वरलु के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उनके दुख में हिस्सा लिया। क्रांतिकारी संगठनों के प्रतिनिधि और परिवारजन उनके शव को पश्चिम बंगाल से उनके गृहनगर पेद्दापल्ली लेकर आए थ। दुश्मन ने हमेशा की तरह जनता को बड़ी संख्या में उनकी अंतिम यात्रा में भाग लेने से रोकने का नाकाम प्रयास किया। हालांकि हजारों जनता दुश्मन की घेराबंदी को तोड़कर चली आई और एक गमगीन पर उत्तेजनापूर्ण माहौल में 27 नवम्बर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें गगनचुम्बी नारों से अश्रुपूर्ण विदाई दे दी गई। जनता ने उनके अधूरे लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया। कामरेड कोटेश्वरलु की मां मधुरम्मा ने देशवासियों का यह आह्वान कर प्रेरित किया कि उनके बेटे की राह पर आगे बढ़ा जाए।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी की ओर से प्रवक्ता अभय ने कामरेड कोटेश्वरलु की हत्या की निंदा करते हुए 25 नवम्बर को एक बयान जारी किया जिसमें समूची जनता, जनवादियों और जन संगठनों का आह्वान

किया गया कि इस क्रूर हत्या का खण्डन किया जाए। उस बयान में क्रांतिकारी आंदोलन को कामरेड कोटेश्वरलु द्वारा दी गई सेवाओं की प्रशंसा की गई। 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक विरोध सप्ताह और दिसम्बर 4–5 तारीखों में भारत बंद की घोषणा की गई। उनकी हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल में नवम्बर 26 व 27 को दो दिनी प्रदेश बंद रखा गया।

देश भर में आंदोलन वाले इलाकों और गुरिल्ला जोनों में कामरेड कोटेश्वरलु की याद में कई सभाएं आयोजित की गईं। उन्हें याद करते हुए कई बुद्धिजीवियों, जनवादियों, लेखकों और कार्यकर्ताओं ने कई लेख, कविताएं, गीत आदि लिखे। विभिन्न भाषाओं में उनकी जीवनी का प्रकाशन किया गया।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे न सिर्फ पार्टी कतारों में, बल्कि व्यापक जनता, जनवादियों और बुद्धिजीवियों में भी काफी लोकप्रिय हैं। यह पहचान उन्हें यूं ही नहीं मिली। क्रांतिकारी आंदोलन में उनके योगदान का नतीजा था यह। आइए, इस योगदान पर नजर डाली जाए।

बचपन में ही पड़े देशभक्ति के बीज

वे जनता और पार्टी कतारों में कोटि, प्रह्लाद, बिमल, किशनजी आदि नामों से सुपरिचित थे। हालांकि मीडिया में उनका नाम कोटेश्वरराव के रूप में प्रचारित हुआ, लेकिन माता–पिता ने उनका नाम 'कोटेश्वरलु' रखा था। उत्तर तेलंगाना (आंध्रप्रदेश) के करीमनगर जिले में 26 नवम्बर 1954 को उनका जन्म हुआ था। मां मधुरम्मा और पिता वेंकटैया की वे दूसरी संतान थे। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उनकी मां ने अपने पति के आदर्शों का सम्मान किया। कोटेश्वरलु के बड़े भाई आंजनेयुलु नौकरी करके अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके छोटे भाई फिलहाल हमारी पार्टी में केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनका परिवार निचले मध्यम वर्ग का है। चूंकि पिता एक छोटे से मुलाज़िम थे, इसलिए मां ने खेतों का चक्कर काटते हुए घास काट लाकर गाय–भैंस को पोसती थीं जिससे होने वाली आय से घर चलाया करती थीं।

कामरेड कोटेश्वरलु की हाई स्कूल तक की पढ़ाई और बचपन पेद्दापल्ली में ही बीता। पिता के प्रभाव से बचपन में ही उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं पैदा हुई थीं। वे देश की रक्षा करने के लिए एक सैनिक बनना चाहते थे। इस चाहत के चलते उन्होंने कुछ समय तक आर.एस.एस. की शाखा में भाग लिया था। लेकिन कुछ ही समय में उसकी धर्मोन्मादी राजनीति व ढोंगी देशभक्ति को समझकर उन्होंने उसे छोड़ दिया।

पिता से मिली प्रगतिशील साहित्य को पढ़ने की आदत के चलते कामरेड कोटेश्वरलु के अंदर प्रगतिशील विचार पैदा हुए थे। वे पढ़ाई में अव्वल रहते थे। हेचएससी में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। उन्हीं दिनों में वे टाइफाइड का शिकार हुए थे जिससे उनका एक कान हमेशा के लिए जवाब दे गया।

1969 में पृथक तेलंगाना का संघर्ष शुरू हुआ था। छात्र जगत ने इस संघर्ष में जुझारू भूमिका निभाई। कामरेड कोटेश्वरलु ने भी उस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। दरअसल इसी संघर्ष ने उनकी जिंदगी में एक मोड़ लाया था। उसके बाद वे धीरे–धीरे क्रांतिकारी राजनीति की ओर चले आए। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद कामरेड कोटेश्वरलु ने करीमनगर के एसआरआर कालेज में पी.यू.सी. में दाखिला लिया था। तब तक उस कालेज में नक्सलबाड़ी का पैगाम पहुंच चुका था। उसकी राजनीति से आकर्षित होने वालों में कामरेड कोटेश्वरलु भी शामिल थे। वे युवा क्रांतिकारियों की एक टोली में शरीक हो गए। पी.यू.सी. के बाद उन्होंने बी.एससी. (गणित) में दाखिला लिया। हालांकि स्नातक के बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में वकालत के कोर्स में दाखिला लिया था, लेकिन क्रांतिकारी क्रियाकलापों के चलते उसे अधूरा छोड़ दिया।

नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम के संघर्षों की अस्थाई पराजय के बाद पार्टी में कई फूटें पड़ी थीं। आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी ने वामपंथी व दक्षिणपंथी भटकावों के खिलाफ सैद्धांतिक संघर्ष छेड़कर 'अतीत का मूल्यांकन कर सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाएं' के नाम से एक आत्मालोचना रिपोर्ट तैयार की। इसके आधार पर क्रांतिकारी शक्तियों को दोबारा एकजुट करने के प्रयास किए गए। जनाधार को बढ़ाने के लिए जन संगठनों का निर्माण शुरू हुआ। राज्य भर में तथा विभिन्न जिलों में कई साहित्यक संगठन पनप गए। कामरेड कोटेश्वरलु का पार्टी व साहित्यक संगठनों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। 1973 में 15 अगस्त के दिन कालेज में झूठी आजादी की जश्न का बहिष्कार करते हुए तिरंगा जलाने की जो सनसनीखेज घटना घटी थी, उसमें उनकी भागीदारी थी। इस तरह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते समय कामरेड कोटेश्वरलु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह उनकी जिंदगी में पहली गिरफ्तारी थी। लेकिन इस गिरफ्तारी से उनके लम्बे क्रांतिकारी प्रस्थान में कोई बाधा नहीं आई। उनके

प्रभाव से उनका घर भी धीरे–धीरे एक क्रांतिकारी केन्द्र में तब्दील हो गया।

1974 में उनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई। अक्टूबर 1974 में रैडिकल छात्र संगठन का निर्माण हुआ जिसका पहला अधिवेशन 23–24 फरवरी 1975 में आयोजित किया गया। कामरेड कोटेश्वरलु ने इस अधिवेशन के लिए अपने जिले से छात्रों को बड़े पैमाने पर गोलबंद किया।

26 जून 1975 से 1977 तक लगभग 20 महीने तक देश में आपातकाल लागू था। पूरा देश ही जेल में तब्दील हो चुका था। सभी क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे। जो पुलिस के हत्थे चढ़े थे, उन्हें यातनाओं और जेल की सजाओं का सामना करना पड़ा था। कामरेड्स सूरपनेनी जनार्दन, मुरलीमोहन, आनंदराव और सुधाकर को इसी दौर में सरकार ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला जिन्हें गिरायपल्ली शहीद के रूप में जाना जाता है। हर तरफ से उठे विरोध की परवाह न करते हुए भूमैया और किष्टागौड़ को फांसी दी।

उस दौरान भूमिगत होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए वह एक परीक्षा की घड़ी थी। दमन के चलते पार्टी के साथ सही सम्पर्क नहीं रह पाता था जिससे उन्हें आर्थिक रूप से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने जनता से जुड़े रहते हुए आग उगलने वाले दमन के बीचोबीच भी जनाधार को बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे कामरेडों में कामरेड कोटेश्वरलु एक थे। दमन के उस दौर में जनवरी 1977 में पार्टी नेतृत्व ने नागपुर शहर में अत्यंत गोपनीय तरीके से 'तेलंगाना रीजनल अधिवेशन' का आयोजन किया। उस अधिवेशन में (1974–75 में सी.ओ.सी. द्वारा तैयार किए गए) 'क्रांति का रास्ता' नामक दस्तावेज को पारित किया। इस अधिवेशन में कामरेड कोटेश्वरलु ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वामपंथी दुस्साहसवादी कार्यनीति की समीक्षा कर उससे उबरकर जनदिशा पर निर्भर करते हुए सही कार्यनीति के साथ व्यवहार में उतरने में यह अधिवेशन अहम महत्व रखता है। इस अधिवेशन की रोशनी में आपातकाल के अंधेरे दिनों के दौरान ही कई कार्यकर्ता संगठक बनकर गांवों में चले गए थे। इसके अंतर्गत कामरेड कोटेश्वरलु ने सिरिसिल्ला तहसील के मरिमड्ला क्षेत्र में संगठन की जिम्मेदारी उठाई।

जनता के दिलों में अमिट छाप

सिरिसिल्ला इलाके में जिम्मेदारी उठाने के कुछ ही दिनों बाद कामरेड कोटेश्वरलु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इत्तेफाक से यह गिरफ्तारी तब हुई थी जिस दिन आपातकाल को उठाना था, अतः उनकी जान बच गई। तीन माह के अंदर ही कामरेड कोटेश्वरलु जमानत पर जेल से रिहा हो गए और अपना कामकाज जारी रखा।

आपातकाल के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा गोपनीय तरीके से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आपातकाल के बाद प्रदेश में कई जन उभार और जनवादी आंदोलन सामने आए। इसके तहत यह मांग काफी जोर से उठी थी कि गिरायपल्ली फर्जी मुठभेड़ पर जांच की जाए। इस पर जांच के लिए भार्गव कमिशन का गठन किया गया। तार्कुंडे कमेटी का भी गठन हुआ। इन कमेटियों के सामने सच्चाई को पेश करने में कामरेड कोटेश्वरलु का भी योगदान रहा।

नक्सलबाड़ी से प्राप्त शिक्षा की रोशनी में अगस्त 1977 में आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी (ए.पी.एस.सी.) ने उस समय की परिस्थिति के मुताबिक नई कार्यनीति तय की जिसके आलोक में क्रांतिकारी गतिविधियों ने पूरे राज्य में जोर पकड़ लिया। पूरे प्रदेश में रैडिकल छात्र संगठन मजबूत होने लगा। जिला व तहसील मुख्यालयों में मौजूद सभी शिक्षा संस्थाओं में रैडिकल छात्र संगठन (आर.एस.यू.) एक नई शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया।

फरवरी 1978 में आर.एस.यू. का दूसरा राज्य अधिवेशन वरंगल में उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। एक वक्ता के रूप में उसमें भाग लेते हुए कामरेड कोटेश्वरलु ने वर्तमान राजनीतिक हालात में छात्रों के कर्तव्यों और ढोंगी चुनावों के बहिष्कार पर जोरदार भाषण दिया। अधिवेशन के आह्वान को पाकर सैकड़ों छात्र–नौजवानों ने गर्मियों में 'चलो गांवों की ओर' अभियान जोशोखरोश के साथ चलाकर 'जमीन उसकी हो जो उसे जोते' के नारे को गांव–गांव में पहुंचाया। तबसे हर साल 'चलों गांवों की ओर' अभियान चलाना एक क्रांतिकारी परम्परा ही बन गया। छात्र–नौजवानों के लिए कक्षाएं चलाकर राजनीतिक शिक्षा देकर उन्हें गांवों में भेजने के लिए कामरेड कोटेश्वरलु ने खासा प्रयास किया। उस समय के हालात, जो खुले तौर पर काम करने के लिए अनुकूल थे, का फायदा उठाकर क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण में वे सरगर्मी से जुट गए।

1979 में रैडिकल युवा संगठन, उसके बाद 1981 में आंध्रप्रदेश किसान मजदूर संगठन अस्तित्व में आए थे। गांव–गांव में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई। सदियों से सामंतों की कोठियों में कमरतोड़ मेहनत करके तंग आ चुके किसानों ने खुद को क्रांतिकारी राजनीति से संगठित करना शुरू किया। नौकरों के वेतनों में बढ़ोतरी, बंजर जमीनों, तालाब जमीन और जमींदारों की जमीनों पर कब्जा आदि संघर्ष सामने आए। प्रदेश के जनवादियों, क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों, वकीलों, प्रगतिशील विचारों वाले शिक्षकों और कर्मचारियों ने इन संघर्षों के प्रति समर्थन जताया। शिक्षकों और कर्मचारियों के संगठनों ने अपनी जायज समस्याओं को लेकर सक्रिय रूप से आंदोलन की राह पकड़ ली। कामरेड कोटेश्वरलु सभी खुले कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर नेतृत्व प्रदान किया करते थे। कुछ ही समय बाद उनके नेतृत्व में काम करते हुए साइनी प्रभाकर, दग्गु राजलिंगु, बय्यपु देवेंदर रेड्डी जैसे दूसरी श्रेणी के नेतृत्वकारी कामरेड्स उभरकर सामने आए थे जो बाद में अलग–अलग समय में शहीद हो गए। कोटेश्वरलु और अन्य कामरेडों द्वारा किए गए इन प्रयासों से 'जगित्याल जैत्रयात्रा' की नींव पड़ी।

'जगित्याल विजयी यात्रा' का नेतृत्व

7 सितम्बर 1978। जगित्याल कस्बा हजारों किसानों से भर चुका था। वहां का कालेज ग्राउण्ड खचाखच भरा हुआ था। दर्जनों गांवों के किसान इस सभा में शामिल होने आए थे। 'जमीन उसकी हो जो उसे जोते' के नारे ने उन्हें वहां खींच लाया। जमींदारों के अत्याचारों ने उन्हें संघर्ष के रास्ते पर लाया। उस सभा को सम्बोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में कामरेड कोटेश्वरलु भी एक थे। हजारों किसानों की यह सभा इतिहास में 'जगित्याल जैत्रयात्रा' यानी 'जगित्याल विजयी यात्रा' के रूप में दर्ज हो गई। शहीद कोटेश्वरलु उस जन सैलाब के दिलों में हमेशा के लिए बस गए।

जगित्याल विजयी यात्रा से उत्पन्न क्रांतिकारी राजनीतिक माहौल में कई कट्टर जमींदार गांव छोड़कर शहरों में भाग गए। कई जमींदारों ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए। जो नहीं झुके उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जमींदारों के सैकड़ों एकड़ के खेतों में जोताई रुक जाने से बंजर बन गए।

फौरन ही राजसत्ता उतर आई। सिरिसिल्ला और जगित्याल तहसीलों को 'आशांत क्षेत्र' घोषित किया गया। जमींदारों की हवेलियों की सुरक्षा के लिए विशेष सशस्त्र पुलिस बलों को गांवों में तैनात किया गया। इससे सरकारी हिंसा का मुकाबला करना किसानों के लिए अनिवार्य हो गया।

पेद्दापल्ली तहसील के रागानेडु गांव के किसानों ने अपनी मांगें न मानने पर जमींदारों को गिरफ्तार किया। उन दिनों यह कार्रवाई 'रागानेडु किड्नैप' के नाम से काफी चर्चित हुई थी। इस सनसनीखेज घटना ने जमींदारों के दिलों में हड़कम्प मचाई। इसका नेतृत्व कामरेड कोटेश्वरलु ने किया था। जब जिले को खाकी छावनी में बदलकर गांवों को संगीनों से दबाया जा रहा था, तब कामरेड कोटेश्वरलु फिर से भूमिगत हो गए। कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर उसी तहसील के रच्चापल्ली गांव में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद वे फिर से जमानत पर रिहा होकर भूमिगत हो गए। पुलिस की घेराबंदी को चतुराई से तोड़कर निकल जाने की कई घटनाएं उनकी क्रांतिकारी जिंदगी में घटी हैं।

आंध्रप्रदेश आंदोलन की कमान

करीमनगर जिले में किसान आंदोलन संगठित होने लगा। धीरे–धीरे गांवों में किसान पुलिस बलों के जुल्म व अत्याचारों का मुकाबला करने लग गए। 1977 में नई कार्यनीति से पार्टी ने जब जनता में कामकाज शुरू किया, उस समय करीमनगर और आदिलाबाद जिलों को मिलाकर संयुक्त जिला पार्टी कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के सचिव कामरेड श्याम (नल्ला आदिरेड्डी) थे जबकि कामरेड कोटेश्वरलु को सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। 1979 तक दोनों जिलों के लिए अलग–अलग कमेटियों का गठन किया गया। उस समय कामरेड कोटेश्वरलु को करीमनगर जिला कमेटी सचिव चुन लिया गया। उसके बाद सितम्बर 1980 में आयोजित आंध्रप्रदेश राज्य के 12वें पार्टी अधिवेशन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस अधिवेशन में उन्हें राज्य कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। तीन महीने बाद वे राज्य कमेटी के सचिव चुन लिए गए। तब वे सिर्फ 26 साल के थे। तबसे उन्होंने 'कामरेड प्रह्लाद' के नाम से आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन की कमान संभाल ली।

आंध्रप्रदेश पार्टी के 12वें अधिवेशन में लिए गए अहम फैसलों में करीमनगर व आदिलाबाद जिलों के किसान संघर्ष को गुरिल्ला जोन के स्तर में विकसित करना; आधार इलाकों की स्थापना के लक्ष्य से जन मुक्ति सेना के भ्रूण रूप में गुरिल्ला दस्तों का निर्माण करने हेतु पार्टी के एक तिहाई कैडरों को दण्डकारण्य भेजना; खम्मम, निजामाबाद जिलों समेत पूरे उत्तर तेलंगाना और राज्य

के दूसरे इलाकों में आंदोलन को फैलाना आदि प्रमुख थे। इन पर अमल करने के लिए पार्टी ने युद्ध स्तर पर कमर कस ली। जून–जुलाई 1980 तक राज्य कमेटी ने कुछ गुरिल्ला दस्तों का गठन कर दण्डकारण्य भेज दिया था। राज्य कमेटी सचिव के रूप में कामरेड प्रह्लाद ने इन फैसलों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

फासीवादी सरकारी हिंसा का मुकाबला

1970 के दशक में पार्टी को दोबारा संगठित करने में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन नेता कोण्डापल्ली सीतारामय्या (के.एस.) को 1982 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए राज्य कमेटी ने एक कार्रवाई की योजना बनाई। उन दिनों यह कार्रवाई 'ग्रेट एस्केप' के नाम से क्रांतिकारी खेमे में मशहूर हुई थी। इस साहसिक गुरिल्ला कार्रवाई की योजना बनाने वालों में कामरेड प्रह्लाद प्रमुख थे।

पार्टी की अगुवाई में आगे बढ़ रहे क्रांतिकारी आंदोलन से दुश्मन की नींदें उड़ने लगी थीं। दुश्मन ने कई होनहार पार्टी कार्यकर्ताओं को कत्ल करना शुरू किया। फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम देकर इनाम–इकराम पाने वाले क्रूर पुलिस अधिकारियों ने आंध्रप्रदेश की राजधानी हैदराबाद में कामरेड प्रह्लाद का पता लगाकर जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने पिस्तौल से उनका मुकाबला कर बड़ी आसानी से शहर की भीड़ में ओझल हो गए। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ खड़े होकर फर्जी मुठभेड़ों में क्रांतिकारियों की हत्या करने वाले क्रूर पुलिस अधिकारियों को सबक सिखाने का पार्टी ने फैसला लिया था। जब वर्ग संघर्ष तेज होने लगा था, ऐसे समय जनयुद्ध की राजनीति से प्रेरित हो रहे किसान व छात्र गुरिल्लों ने यादगिरी रेड्डी (काज़ीपेट एसआई), बुच्चिरेड्डी (पेद्दापल्ली डीएसपी), कोमल रेड्डी (हवलदार), लक्ष्मण राव (कागजनगर एसआई) जैसे क्रूर पुलिस अफसरों को अपने देशी हथियारों से ही मार गिराया। राजसत्ता द्वारा जारी हत्याओं के सिलसिले से क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार नहीं थमा। वह और ज्यादा संगठित होने लगा। 1985 में 'अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संघ' की स्थापना हुई। कई राज्यों में गठित होकर काम करने वाले क्रांतिकारी छात्र संगठनों ने एकजुट होकर एक देशव्यापी संघ का निर्माण किया जिससे मजबूत छात्र आंदोलन की नींव डाली गई। कामरेड प्रह्लाद ने इस संघ के निर्माण और प्रथम अधिवेशन के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई।

'दुश्मन के अघोषित युद्ध को आत्मरक्षात्मक युद्ध के जरिए हरा दें...' के नाम से आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी ने एक सरकुलर जारी किया जिसकी रोशनी में कुछ अहम फैसले लिए गए। दुश्मन के भारी दमनचक्र को देखते हुए राज्य कमेटी की संख्या को घटाकर पांच रखना, आत्मगत शक्तियों की रक्षा करते हुए उल्लेखनीय संख्या में कार्यकर्ताओं को दण्डकारण्य भेजना, देश के दूसरे राज्यों में, खासकर औद्योगिक शहरों में नई क्रांतिकारी ताकतों को तैनात करना आदि उन फैसलों में प्रमुख थे। उस समय पार्टी के फैसले के मुताबिक कामरेड प्रह्लाद दण्डकारण्य आंदोलन का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी उठाकर जंगल में आ गए। निज़ाम के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासी वीर योद्धा 'रामजी गोण्ड' के नाम को अपनाते हुए उन्होंने अपना नाम 'रामजी' रखा। तबसे दण्डकारण्य की जनता और कैडरों में वे 'रामजी दादा' के नाम से लोकप्रिय हो गए और उनके दिलों में सदा के लिए बस गए।

जनयुद्ध के सेनानी

कामरेड कोटेश्वरलु ने जनयुद्ध के नियमों, गुरिल्ला युद्ध नीति, जनसेना के निर्माण की आवश्यकता पर; चीन, वियत्नाम और रूस की क्रांतियों के अनुभवों; लाल सेना के अनुभवों, विश्व युद्धों के अनुभवों; सुन–जू व क्लासविट्ज़ आदि सैनिक विशेषज्ञों की रचनाओं; विभिन्न देशों के सैन्य मैनुअलों का गहराई से व ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। खुद पढ़ने के साथ–साथ पार्टी कैडरों से पढ़वाने पर भी उनका ध्यान रहता था। भारत के इतिहास में हुए कई युद्धों, सिखों के लड़ाकू अनुभवों और तमिल चीतों के गुरिल्ला युद्ध के अनुभवों का उन्होंने गहरी समझ के साथ अध्ययन किया। उन अनुभवों की माओवादी सैनिक सिद्धांतों की रोशनी में समीक्षा करते हुए लेख लिखकर कैडरों तक पहुंचाने में उनका खासा योगदान रहा। अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने निरंतर अभ्यास किया।

1981 से 1989 तक दण्डकारण्य में आयोजित तमाम फौजी प्रशिक्षण शिविरों में कामरेड रामजी ने एक छात्र के रूप में भाग लेकर सैन्य मोर्चे में निपुणता हासिल की। 1983 में आयोजित केन्द्रीय सैनिक प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने एक छात्र के अलावा शिक्षक के रूप में भी भाग लिया जहां उन्होंने राज्य कमेटी सचिव के रूप में गुरिल्ला बलों को बेहतर प्रशिक्षण देने की कोशिश की। उसके बाद आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी और दण्डकारण्य फारेस्ट कमेटी की पहलकदमी पर 1987 और 1989 में आयोजित सैनिक प्रशिक्षण शिविर जन सेना के विकासक्रम में अहम बिंदु थे। माओवादी बन चुके श्रीलंका के तमिल लड़ाकों ने सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद की उच्च भावना से

इन शिविरों में प्रशिक्षकों के रूप में भाग लेकर उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया। गुरिल्लों के लिए आवश्यक सैन्य तकनीक सिखाई। कामरेड रामजी ने इन सभी को दृढ़ संकल्प के साथ सीख लिया। इस अनुभव के आधार पर उन्होंने जंगल महल में एक नेता व प्रशिक्षक के रूप में गुरिल्लों को प्रशिक्षित किया जिससे शत्रु बलों पर साहसिक हमले कर कामयाबियां हासिल करने में मदद मिली। 15 फरवरी 2010 को सिल्दा में हमला कर ईस्टर्न फ्रांटियर रायफल्स के 24 जवानों को मार गिराने की कार्रवाई को उनकी सैन्य प्रतिभा का परिचायक कहा जा सकता है। सैन्य अनुशासन का पालन करने में कामरेड रामजी आगे रहते थे। अपनी शारीरक दृढ़ता को बढ़ाने में वे जितना महत्व देते थे, उतना ही जोर अनुशासन के पालन पर। गुरिल्ला दस्तों के अनुभवों का विश्लेषण कर उनके लिए स्थाई आदेश (स्टैंडिंग आर्डर्स) तैयार करने में कामरेड रामजी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1999 में गुरिल्ला सेना के निर्माण के बारे में पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने व्यापक रूप से विचार–विमर्श किया। 1980 से 1999 तक निर्मित हुए गुरिल्ला दस्तों व प्लाटूनों के अनुभवों की समीक्षा की। जनयुद्ध में हासिल प्रगति और आधार इलाके के लक्ष्य के बारे में केन्द्रीय कमेटी ने गहराई से चर्चा की। इसके फलस्वरूप ही था कामरेड्स श्याम, महेश और मुरली की शहादत की स्फूर्तिभावना से उनकी पहली बरसी के दिन, यानी 2 दिसम्बर 2000 को जन गुरिल्ला सेना (अब पीएलजीए) का आविर्भाव हुआ। इसमें कामरेड रामजी ने मुख्य भूमिका अदा की।

मेरे बेटे ने जनता के लिए अपनी जान दी...
सभी मेरे बेटे के रास्ते पर चलें...
– शहीद की मां मधुरम्मा

दण्डकारण्य आंदोलन के विकास में

कामरेड रामजी, जोकि 1986 से दण्डकारण्य आंदोलन का मार्गदर्शन कर रहे थे, को फरवरी 1987 में आयोजित दण्डकारण्य के पहले अधिवेशन में फारेस्ट कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। 1987–93 के बीच उन्होंने फारेस्ट कमेटी सदस्य और सचिवालय सदस्य रहते हुए दण्डकारण्य आंदोलन के विकास में भरपूर योगदान दिया। मुख्य रूप से गढ़चिरोली डिवीजन में अपने काम को केन्द्रित करते हुए उन्होंने आदिलाबाद से 'मन्यम' की पर्वतमाला तक फैले हुए सभी डिवीजनों के आंदोलनों से अपना रिश्ता जोड़े रखा। 1989 में मध्य भारत में बालाघाट डिवीजन के विकास के लिए विशेष प्रयास किया। जरूरतों के हिसाब से दूरगामी नजरिए से आंदोलन का विस्तार करने पर हमेशा उनका जोर रहता था। 1993 के आखिर में वे केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी (सी.ओ.सी.) के सदस्य की हैसियत से उत्तर भारत के राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार की जिम्मेदारी लेकर चले जाने के बाद भी दण्डकारण्य के आंदोलन से जीवंत संपर्क में बने रहे। वहां पर घटने वाली युद्ध की हर कार्रवाई पर तथा राजनीतिक व सांगठनिक बदलावों पर लगातार नजर रखते हुए उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे।

दण्डकारण्य में आंदोलन की स्थिति के अनुसार कमेटियों में चर्चा कर सही कार्यनीतियों को अपनाने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। वहां पर शहरी मोर्चे में कामकाज को बढ़ाने के लिए संगठक पद्धति को लागू करने पर कमेटियों में चर्चा करके अमल करने पर उन्होंने जोर दिया। फारेस्ट कमेटी के फैसले के अनुसार जन संगठनों को शक्तिशाली ढंग से चलाने के लिए संगठक पद्धति लागू की गई थी जिसमें रामजी की पहलकदमी अहम थी। जंगलों और मैदानी/शहरी इलाकों के आंदोलनों के बीच तालमेल बैठाने के लिए समुचित सांगठनिक स्वरूपों को पेश करने में भी उनका प्रयास रहा। सैनिक मोर्चे को विशेष रूप से विकसित करने की दृष्टि से 1993 में विशेष मिलिटरी दस्तों तथा 1995 में प्लाटून का निर्माण कर जनसेना की नींव रखने में कामरेड रामजी ने पहले एफसी सदस्य और बाद में सीओसी सदस्य के रूप में पहलकदमी दिखाई। 1994 में ग्राम राज्य कमेटी (अब क्रांतिकारी जन कमेटी/जनताना सरकार) के निर्माण के बारे में केन्द्रीय कमेटी द्वारा लिए गए प्रस्तावों के पीछे तथा उसे दण्डकारण्य में लागू करने में कामरेड रामजी ने महत्वपूर्ण सैद्धांतिक व राजनीतिक योगदान दिया।

दण्डकारण्य के आंदोलन के अनुभवों का सीसी और एसजेडसी ने विश्लेषण और संश्लेषण कर वहां गुरिल्ला युद्ध को आगे बढ़ाने और दुश्मन पर कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण

तेज करने का फैसला लिया। दुश्मन के बलों का बड़े पैमाने पर सफाया कर हथियार छीनने तथा पीएलजीए व जन मिलिशिया को हथियारबंद करने पर जोर दिया गया। जनयुद्ध को सभी पहलुओं में विकसित कर आधार इलाके के निर्माण के लक्ष्य से आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसमें कामरेड रामजी का सक्रिय योगदान रहा। वे इस बारे में हमेशा सोचते थे और पार्टी कमेटियों व नेतृत्वकारी कैडरों को निरंतर सोचने व समुचित निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित करते थे। गुरिल्ला जोनों में जनयुद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों की तैयारी की विशेष यूनिटें बनाने पर उन्होंने शुरू से ही खासा ध्यान दिया।

पिछले 30 सालों में दण्डकारण्य के आंदोलन में आए हरेक मोड़ पर कामरेड रामजी अपनी छाप छोड़ गए। वहां के आंदोलन के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय था।

पूर्व और उत्तर भारत में योगदान

1993 के आखिर से कामरेड कोटेश्वरलु की क्रांतिकारी जिंदगी मुख्य रूप से पूर्व व उत्तर भारत के राज्यों के साथ, खासकर पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास व विस्तार के साथ जुड़ी रही। 1994 की शुरूआत से बंगाल को अपना प्रधान कार्यक्षेत्र बनाकर उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में भी आंदोलन के विकास हेतु प्रयास किया। 1998 में पार्टी यूनिटी के साथ विलय हो जाने के बाद उन्होंने बिहार–झारखण्ड में भी क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में अपना योगदान दिया। वहां पर पार्टी यूनिटी की अगुवाई में पुराने समय से जारी सशस्त्र किसान आंदोलन का गहराई से अध्ययन करते हुए उसे उन्नत स्तर में विकसित करने की कोशिश की। बिहार–झारखण्ड राज्य कमेटी की बैठकों में उपस्थित होकर तथा आंदोलन के इलाकों का दौरा कर वर्ग संघर्ष को तेज करने और गुरिल्ला युद्ध को विकसित करने हेतु अपना योगदान दिया। पार्टी सदस्यों को पेशेवर कार्यकर्ताओं में बदलने तथा उन्हें हमेशा जनता व आंदोलन के साथ जुड़े रहने हेतु प्रोत्साहित करने में उन्होंने विशेष ध्यान दिया। 2004 में एमसीसीआई और भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) पार्टियों के विलय के बाद कामरेड कोटेश्वरलु ने पोलिटब्यूरो सदस्य व नव गठित पूर्वी रीजनल ब्यूरो सदस्य के रूप में रहकर मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में अपने काम को केन्द्रित किया। 2004 में दो पार्टियों के विलय के बाद पश्चिम बंगाल में पुरानी दो पर्टियों से आए पार्टी कतारों के बीच मजबूत एकता कायम करने में उन्होंने खासा योगदान दिया।

पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा द्वारा प्रस्तावित नैनो कार उद्योग और नंदिग्राम में इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप द्वारा प्रस्तावित केमिकल हब का जनता ने विरोध किया। हमारी पार्टी ने सिंगूर व नंदिग्राम में संघर्षरत किसानों का साथ दिया। कामरेड कोटेश्वरलु ने पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटी को इन आंदोलनों का नेतृत्व करने हेतु मार्गदर्शन दिया। संयुक्त मोर्चे के तहत निर्मित जमीन अधिग्रहण प्रतिरोध समिति (बीयूपीसी) में शामिल जन संगठनों का सक्रिय मार्गदर्शन करते हुए किसानों को जुझारू संघर्षों में उतारने में पार्टी सफल रही। जनता, खासकर नौजवानों ने सशस्त्र प्रतिरोध का झण्डा गाड़कर सामाजिक फासीवादी गुण्डों का जमकर मुकाबला किया। हमारी पार्टी ने सिंगूर व नंदिग्राम में संघर्षरत किसानों का साथ दिया। कामरेड कोटेश्वरलु ने अपने अपार अनुभव के आधार पर पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटी को इन आंदोलनों का नेतृत्व करने हेतु मार्गदर्शन दिया। संयुक्त मोर्चे के तहत निर्मित जमीन अधिग्रहण प्रतिरोध समिति (बीयूपीसी) में शामिल जन संगठनों का सक्रिय मार्गदर्शन करते हुए किसानों को जुझारू संघर्षों में उतारने में पार्टी सफल रही। दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और उनके आका साम्राज्यवादियों की सेवा में समर्पित 'मार्क्सवादी' चंद हजार करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी के एवज में पूरे नंदिग्राम को कब्रगाह में तब्दील करने पर उतारू हो गए थे। उनके अत्याचार हदों से पार हो गए थे। सीपीएम के गुण्डों ने आधुनिक राइफलें लेकर संघर्षरत जन समूहों पर अंधाधुंध हमले किए। फिर भी जनता ने घुटने नहीं टेके। जनता, खासकर नौजवानों ने सशस्त्र प्रतिरोध का रास्ता चुनकर सामाजिक फासीवादी गुण्डों को करारा जवाब दिया। इससे वामपंथी सरकार को इस संघर्ष के सामने घुटने टेकने ही पड़े। नंदिग्राम से केमिकल हब हट गया। टाटा का नैनो सिंगूर से गुजरात भाग गया। जनता की जीत हुई। इस जीत के पीछे सर्वहारा के अगुवा दस्ते का योगदान था जिसकी अगुवाई कर रहे थे कामरेड कोटेश्वरलु।

ऐतिहासिक लालगढ़ विद्रोह का नेतृत्व

नंदिग्राम में जनता की जीत की बरसी से पहले ही लालगढ़ में भी जन संघर्ष अपनी विशिष्टताओं के साथ फूट पड़ा। लालगढ़ क्षेत्र में जिंदल ने एक स्टील कारखाना खोलने के लिए जनता को जमीन से बेदखल करने की साजिश रची। बुद्धदेब और रामविलास पासवान ने लाल कालीन बिछाकर जिंदल का स्वागत किया। जंगल महल इलाके में मौजूद खनिज संपदा को लूटने–खसोटने के

लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने अपनी पूरी राजमशीनरी उतार दी। लेकिन जंगल महल क्षेत्र की जनता ने इसका विरोध किया। विदेशी और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक बुद्धदेब और रामविलास का काफिला जब जिंदल द्वारा प्रस्तावित स्टील प्लांट का शिलान्यास कर वापस जा रहा था, उसे निशाना बनाकर पीएलजीए ने बारूदी सुरंग का विस्फोट किया। उसके बाद पुलिस बलों ने जनता पर पाशविक हमला छेड़ दिया जिसके खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा। और इस तरह 13 नवम्बर को एक ऐतिहासिक जन विद्रोह छिड़ गया लालगढ़ में।

जनता की संगठित ताकत के सामने उस इलाके में शोषक राज मशीनरी कुछ महीनों तक ठप्प हो गई। मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा जिलों का समूचा सरहदी इलाका, जोकि जंगल महल कहलाता है, युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। हजारों संख्या में जनता परम्परागत हथियारों से लैस हो गई। पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे–धीरे शोषित जनता की तमाम न्यायपूर्ण समस्याओं पर एक व्यापक संघर्ष के रूप में विकसित हुआ। महंगाई के खिलाफ, किसानों की फसलों को पर्याप्त दाम देने, विद्यालयों से पुलिस कैम्पों को हटाने, फर्जी मुठभेड़ों को बंद करने, ग्रीनहंट को रोकने, सेजों के निर्माण को बंद करने आदि मांगों को लेकर जनता ने कई संघर्ष किए। जिनके हाथों में पिछले तीस बरसों से जुल्म व अत्याचार सहती रही, उन फासीवादी गुण्डों को जनता ने घसीटकर सड़कों पर लाया। गांव–गांव में कुख्यात गुण्डों को जन अदालतों में दण्डित किया। गुण्डों के अड्डे और जनता के लिए यातना के केन्द्र बन चुके सीपीएम के दफ्तरों को जनता ने तोड़ डाला। वहां से कई औजारों और हथियारों को जनता ने जब्त किया। साथ ही, अपनी जरूरतें खुद के बल पर पूरी करने के लिए भी जनता ने पहलकदमी की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जन वितरण प्रणाली आदि सुविधाओं की जिम्मेदारी जन संगठनों ने खुद उठाई। जिस 'जन सत्ता' का ढिंढ़ोरा पिछले तीस सालों से सामाजिक फासीवादियों ने पीट रखा था, उसे नकारकर जनता ने क्रांतिकारी रास्ते से अपना शासन खुद ही चलाना शुरू किया। अपनी साहसिक संघर्षों और अनुपम कुरबानियों से नया इतिहास रचना शुरू किया। इसका मार्गदर्शन करते हुए कामरेड कोटेश्वरलु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लालगढ़ में उभरे संघर्ष को कुछ ही समय के अंदर सुवर्णमुखी नदी के किनारे तक और गोपिबल्लभपुर जिले की सरहद तक फैलाया गया जोकि 1970 के दशक में क्रांतिकारी संघर्ष के गढ़ हुआ करते थे। न सिर्फ कोलकाता में, बल्कि दिल्ली, मुम्बई, बंगलूरु, हैदराबाद समेत कई शहरों में छात्रों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, लेखकों, कवियों, जनवादियों और आदिवासियों के तमाम हितैषियों की गोलबंदी हुई। पूर्वोत्तर के राज्यों की संग्रामी जनता भी लालगढ़ से प्रेरित हुई। लालगढ़ जन संघर्ष के समर्थन में देश भर में जन कमेटियों का निर्माण हुआ। इस पूरे क्रम में कामरेड कोटेश्वरलु ने अपने हिस्से का योगदान दिया।

आंतरिक संघर्षों में दृढ़ता से डटे रहे

पार्टी में विभिन्न मौकों पर उत्पन्न अंदरूनी संघर्षों में कामरेड कोटेश्वरलु ने क्रांतिकारी लाइन को दृढ़ता से थामे रखकर दक्षिण व वामपंथी अवसरवादियों और विघटनकारियों का मजबूती से विरोध किया। पार्टी की लाइन पर रंग–बिरंगे संशोधनवादियों और अवसरवादियों के हमलों का उन्होंने एक सैद्धांतिक योद्धा की तरह मुकाबला किया। 1985 में पुरानी पीपुल्सवार पार्टी में के. जी. सत्यमूर्ति आदि अवसरवादियों द्वारा पैदा किए गए आंतरिक संकट का सामना करने और समूची पार्टी को क्रांतिकारी लाइन पर एकजुट रखने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। 1991 में पार्टी के तत्कालीन सचिव कोण्डापल्ली सीतारामैया जब खुद ही अवसरवाद का शिकार होकर एक बार फिर संकट का कारण बने थे, तब भी कामरेड कोटेश्वरलु क्रांतिकारी पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहे। 1980 के दशक में आंध्रप्रदेश में दक्षिणपंथी अवसरवादियों और पश्चिम बंगाल में नव संशोधनवादियों के खिलाफ हुए सैद्धांतिक–राजनीतिक संघर्षों में तथा 2002 में पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के तत्कालीन सचिव माणिक द्वारा सामने लाई गई अवसरवादी राजनीति को हराने में कामरेड कोटेश्वरलु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर प्लेनमों का आयोजन कर उन्हें हल करने का प्रयास किया। इन सैद्धांतिक संघर्षों के दौरान दस्तावेज और किताबें लिखने में तथा विभिन्न पत्रिकाओं में बहसें चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुल मिलाकर कहा जाए, तो विचारधारा, सिद्धांत और राजनीति से सम्बन्धित मामलों में मजबूत पकड़ रखते हुए, निरंतर अध्ययन जारी रखते हुए पार्टी की लाइन को विकसित करने और उसकी रक्षा करने में कामरेड कोटेश्वरलु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रम में पार्टी के तमाम दस्तावेजों, खासकर 'भारतीय क्रांति की रणनीति–कार्यनीति'

को समृद्ध बनाने में उनका विशेष योगदान रहा।

कामरेड कोटेश्वरलु भूलसुधार अभियान में अपनी गलतियां सुधारने में भी एक आदर्शवान कामरेड थे। 1984 में पार्टी की आंध्रप्रदेश शाखा में उत्पन्न छह बुराइयों को सुधारने के दौरान उन्होंने राज्य कमेटी के सचिव के रूप में अपनी ओर से हुई विफलताओं को चिन्हित कर ईमानदारी से आत्मालोचना पेश करते हुए अपना पद त्याग दिया था। उसके बाद राज्य कमेटी सचिवालय सदस्य के रूप में रहकर अपनी गलतियों से बाहर आकर उन्होंने फिर से सभी का विश्वास जीत लिया। पार्टी कमेटी की बैठकों में साथियों द्वारा जो भी आलोचना या सुझाव दिया जाता था वे उसे गहराई से समझकर सुधार लेते थे।

क्रांतिकारियों की एकता के प्रयास

नक्सलबाड़ी आंदोलन की अस्थाई पराजय के बाद विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों व तबकों में तथा रणनीतिक महत्व के इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन का दोबारा निर्माण करने के दौरान सच्चे क्रांतिकारियों के बीच एकता के प्रयास तेज हो गए। 1990 के दशक में इसके सकारात्मक नतीजे आने लगे। कामरेड कोटेश्वरलु ने भी पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में रणनीति–कार्यनीति, एससीआर–1980 और नीतिगत दस्तावेजों के आधार पर देश के बिरादराना क्रांतिकारियों और संगठनों के साथ एकता के प्रयासों में भाग लिया। खासकर पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) और भाकपा (मा–ले) (पार्टी यूनिटी) के बीच 1998 में सम्पन्न विलय में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) की 2001 में आयोजित कांग्रेस में सैद्धांतिक, राजनीतिक, सैनिक, सांगठनिक व कार्यनीतिगत पहलुओं में की गई समीक्षा के चलते मा–ले की धारा से तथा तब तक एमसीसीआई द्वारा हासिल नतीजों से उस धारा से एकता के लिए आवश्यक आधार निर्मित हो गया। 21 सितम्बर 2004 को इन दोनों धाराओं के बीच सम्पन्न विलय और एक महाधारा के रूप में भाकपा (माओवादी) के आविर्भाव की प्रक्रिया में कामरेड कोटेश्वरलु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो पार्टियों के बीच कई दफे हुई द्विपक्षीय वार्ता की बैठकों में कामरेड कोटेश्वरलु ने भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में भाग लिया। इस मौके पर दस्तावेजों के आदान–प्रदान में, अध्ययन में, संयम के साथ बहसें चलाने में तथा दो पार्टियों के व्यवहार से सकारात्मक पहलुओं का संश्लेषण कर उसका निचोड़ एकीकृत पार्टी के नए दस्तावेजों में सम्मिलित करने में कामरेड कोटेश्वरलु का योगदान महत्वपूर्ण रहा।

बिरादराना सम्बन्धों की प्रगति में

भारत के विभिन्न इलाकों में बढ़ रहे क्रांतिकारी आंदोलन और नेपाल में तेजी से उभरे जनयुद्ध के आधार पर दक्षिण एशिया में एक क्रांतिकारी समन्वय केन्द्र का गठन करने की दिशा में पार्टी ने पहलकदमी ली। तीसरे इंटरनेशनल के रद्द किए जाने के बाद, कामरेड माओ की मृत्यु के बाद दुनिया में क्रांति का कोई केन्द्र नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में दुनिया की कुछ सर्वहारा पार्टियों की पहल पर रिम (रिवल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूवमेंट) के साथ सम्बन्ध जारी रखते हुए ही हमारी पार्टी ने दक्षिण एशिया की माओवादी पार्टियों और ग्रुपों के साथ बिरादराना सम्बन्ध कायम कर लिए। 1996 में दिल्ली में राष्ट्रीयता के सवाल पर आयोजित सेमिनार में एमसीसी, पीपुल्सवार और पार्टी यूनिटी ने भाग लिया जहां उन्होंने अपना–अपना रुख स्पष्ट किया। साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद और आंदोलनों पर जारी राजकीय हिंसा के खिलाफ गठित सीकम्पोसा में इन पार्टियों ने सक्रियता से भाग लिया। इन तमाम प्रयासों में कामरेड कोटेश्वरलु ने अहम भूमिका निभाई।

साथ ही, देश के कई लड़ाकू संगठनों के साथ कामरेड कोटेश्वरलु ने दोस्ताना सम्बन्ध कायम किए। असम, नगालैण्ड, मणिपुर आदि क्षेत्रों में अलग होने के अधिकार समेत आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्षरत राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के संगठनों से क्रांतिकारी रिश्ते कायम रखते हुए भारत के लुटेरे शासक वर्गों के विस्तारवाद के खिलाफ सांझी समझदारी बढ़ाने में उन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई। कश्मीर के संघर्षरत संगठनों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने की दिशा में भी उन्होंने काम किया। दशकों से संशोधनवाद में डूबे हुए तथाकथित कम्युनिस्टों पर भरोसा खो चुके राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों के साथ हमारी पार्टी की नीतियों के आधार पर बेहतर सम्बन्ध कायम कर उनके साथ सांझी समझदारी बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पार्टी के अधिवेशनों व कांग्रेस में

कामरेड कोटेश्वरलु ने पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न अधिवेशनों और कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1995 में सम्पन्न पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) की अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन और 2001 में आयोजित 9वीं कांग्रेस में उन्होंने सैद्धांतिक व राजनीतिक बहसों में भाग लेकर पार्टी की लाइन और बुनियादी दस्तावेजों को

समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई। विभिन्न मौकों पर सामने आए वाम व दक्षिणपंथी रुझानों का उन्होंने विरोध किया। 2007 में आयोजित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की एकता कांग्रेस – 9वीं कांग्रेस को सफल बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

एक स्नेहिल व प्रेमपूर्ण साथी

कामरेड रामजी पार्टी कतारों के लिए न सिर्फ एक नेता थे, बल्कि स्नेह व प्यार बांटने वाले साथी भी थे। वे हर उम्र और हर किस्म की सामाजिक पृष्ठभूमि वाले साथियों से, महिला–पुरुष सभी से आसानी से घुलमिल जाते थे। कैडरों की जरूरतों को वे न सिर्फ समझते थे, बल्कि याद से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते थे। जब भी मौका मिले तो कामरेडों से मुलाकात जरूर करते थे। साथियों को आवश्यक विषयों की जानकारी देने के साथ–साथ उनकी खामियों को दूर करने और उनकी खूबियों को नजर में रखते हुए प्रोत्साहित करने में वे ध्यान दिया करते थे।

पार्टी में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपने कई करीबियों को भी क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदार बनाने के लिए विशेष प्रयास किया। अपने साथ अपने भाई को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल कर उन्हें एक कार्यकर्ता व नेता के रूप में विकसित करने में कामरेड रामजी ने जिस तरह प्रोत्साहित किया और सहयोग दिया, वह एक आदर्श मिसाल है। 1984 में पार्टी में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली एक साथी के साथ उनका विवाह हुआ। कामरेड रामजी ने उनकी काफी मदद की और प्रोत्साहन दिया ताकि वे क्रांतिकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर सकें। अपनी–अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार वे एक दूसरे से दूर रहते थे और दुश्मन के क्रूर हमलों के बीच उन्हें सालों तक मिलने का मौका नहीं मिलता था। इन दोनों की आदर्शपूर्ण जोड़ी ने क्रांति के हितों को ही हमेशा सर्वोपरि रखा। अपनी मां को उन्होंने अखबारों के माध्यम से जो चिट्ठियां लिखीं उससे उन्होंने ऐसी तमाम माताओं को क्रांति का पैगाम भेजने की कोशिश की। यह उनके अंदर मानवीय स्पर्श का परिचायक था।

महिला कामरेडों की पक्षधरता

पार्टी में महिला कामरेडों के विकास और उनकी समस्याओं के प्रति कामरेड कोटेश्वरलु खास तौर पर ध्यान रखा करते थे। पार्टी में महिला कामरेडों को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था, उन पर दण्डकारण्य फारेस्ट कमेटी द्वारा तैयार किए गए परिपत्र का प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। पितृसत्तात्मक उत्पीड़न का शिकार होकर, शारीरक रूप से अल्परक्तता से ग्रस्त होकर, गुरिल्ला जीवन में अक्सर मलेरिया का शिकार होने से कमजोर पड़ने वाली गुरिल्ला महिलाओं को 'विशेष आहार' देने का प्रस्ताव उन्होंने कमेटी में रखा था। वे अक्सर कहा करते थे कि क्रांतिकारी व्यवहार में पदोन्नति से लेकर मैदान में किए जाने वाले सैनिक कवायद तक हर मामले में महिलाओं को पुरुषों के साथ होड़ में न रखकर अलग से ही प्रोत्साहित करना चाहिए।

कामरेड रामजी ने क्रांतिकारी आंदोलन में लम्बे समय से काम करने वाली महिला कामरेडों के साथ विभिन्न मुद्दों पर भेंटवार्ता कर उसे पार्टी की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। इससे संघर्ष में उनके अनुभवों को पाठकों तक ले जाने में तथा पार्टी में कार्यरत तमाम महिलाओं को प्रेरित करने में मदद मिली।

कलम व गले से भी जारी रखी जंग

कामरेड कोटेश्वरलु एक अच्छे लेखक, कवि, आलोचक और वक्ता थे। हालांकि उन्होंने कई छद्म नामों से रचनाएं कीं, लेकिन आखिर में 'असिधारा' नाम को स्थाई बना लिया। पार्टी की ओर से की गई रचनाओं में भी उनका खासा योगदान रहा। विभिन्न मुद्दों पर तुरत–फुरत रचनाएं करना उनकी खासियत थी। पार्टी पत्रिकाओं के अलावा पूंजीवादी प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए भी वे अपनी रचनाएं भेजा करते थे। पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ नकली क्रांतिकारियों और दुश्मन द्वारा किए जाने वाले हमले का वे मार्क्सवादी तर्क से परास्त करते थे। क्रांतिकारी पत्रिकाओं के संचालन में वे गंभीरता से शामिल होते थे।

क्रांति, रैडिकल मार्च, कार्मिक पथम्, प्रभात, वैनगॉर्ड, अवामी जंग आदि पत्रिकाओं को चलाने में उन्होंने सराहनीय योगदान दिया। सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांगठनिक, सैनिक, सांस्कृतिक व सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने अध्ययन कर कई लेख लिखे थे। दण्डकारण्य में इलाके वार जनता की भाषाओं में पत्रिकाओं के संचालन पर वे जोर दिया करते थे। दण्डकारण्य की साहित्यक पत्रिका 'झंकार' को उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया। किताबों के प्रकाशन पर वे खासा ध्यान दिया करते थे।

खतों में भी उनकी कवितात्मकता साफ झलकती थी। खुद तो वे लिखते ही थे, साथ ही, साथियों से लिखवाना और उनकी रचनाओं की खामियों को दर्शाना उनकी एक और खासियत थी। खासतौर पर महिला कामरेडों को लेखकों के रूप में विकसित करने हेतु

प्रोत्साहन देने के साथ–साथ उनकी रचनाओं पर अपने सुझाव वे जरूर देते थे।

1984 में आंध्रप्रदेश में क्रांतिकारी लेखक संघ (विरसम्) द्वारा जन कलाओं पर आयोजित कार्यशाला के लिए उन्होंने जो सुझाव व विचार भेजे थे, उससे क्रांतिकारी लेखकों की जिम्मेदारियों पर उनकी समझदारी स्पष्ट होती है।

कामरेड कोटेश्वरलु एक अच्छे वक्ता भी थे। किसी भी मुद्दे पर वे बेबाकी से अपनी बात रखा करते थे। वे जहां भी होते वहां की भाषा में बोलने की कोशिश करते थे। आंदोलन की जरूरतों के मुताबिक उन्होंने कोया, हिंदी, अंग्रेजी और बंग्ला भाषाएं सीख लीं। उनका भाषण श्रोताओं की समझदारी बढ़ाता था और उनके अंदर उत्साह का संचार करता था।

कामरेड कोटेश्वरलु ने 2007 से पार्टी की पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद लालगढ़ आंदोलन की उभार के समय मीडिया के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहकर उन्होंने कई मुद्दों पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। पत्रकारों के साथ वे दोस्ताना सम्बन्ध रखा करते थे।

एक मार्क्सवादी शिक्षक

कामरेड कोटेश्वरलु की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक थी कैडरों को शिक्षित करना। शुरूआती दिनों से लेकर कैडरों को मार्क्सवादी शिक्षा देने के लिए राजनीतिक कक्षाएं चलाने में उनका खासा योगदान रहा। 1996 में केन्द्रीय राजनीतिक स्कूल व स्कोप का गठन किया गया था। शहीद कामरेड आजाद के नेतृत्व में बनी इस इकाई में वे भी शामिल थे। स्कोप की ओर से विशेष योजनाएं बनाई गईं ताकि नेतृत्वकारी कैडरों को सैद्धांतिक शिक्षा दी जा सके। कामरेड कोटेश्वरलु जहां भी जाते थे तो चुने हुए विषयों पर नोट्स की तैयारी और कक्षाओं के आयोजन पर आवश्यक सुझाव दिया करते थे।

... हजारों निकलेंगे उनकी राह पर!

अब कामरेड कोटेश्वरलु नहीं रहे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी मृत्यु से हम एक अनुभवी व वरिष्ठ साथी खो दिया। वे कैडरों के लिए एक स्नेहिल साथी थे। सैद्धांतिक, राजनीतिक व सांगठनिक क्षेत्रों में अपार अनुभव प्राप्त साथी थे। वे एक क्रांतिकारी कवि और लेखक थे। वे माओवादी जनयुद्ध के सैनिक व कमाण्डर थे जिन्होंने उठाई हुई बंदूक को कभी नीचे नहीं रखी। लगातार 38 सालों तक क्रांति की राह पर चलते हुए जन आंदोलनों और जनयुद्ध में उन्होंने कई मिसालें कायम कीं। वे एक ऐसे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि एक चिनगारी दावानल को पैदा कर सकती है। वे क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक चमकते तारा बनकर रहेंगे और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।

वे एक जननेता थे जिन्होंने क्रांति के लक्ष्यों को हासिल करने की राह में अपनी जान दांव पर लगाई। सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से निश्चयपूर्वक लड़कर उन्हें कब्र में पहुंचाना ही इस वीर योद्धा के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। उनकी यादों से ऊर्जा हासिल करते हुए दुगुने उत्साह व बोल्शेविक संकल्प के साथ जनयुद्ध को तेज करेंगे। उनकी मौत से हमारी पार्टी व भारतीय क्रांति को हुई अपार क्षति की भरपाई करने के लिए जन आंदोलनों को तेज करेंगे और अनगिनत 'कोटेश्वरलु' पैदा करेंगे। जनता और जन आंदोलनों ने ही कोटेश्वरलु को पैदा किया था। आगे भी जनता और जन आंदोलन ही उन्हें बार–बार पैदा करते रहेंगे। शोषित जनता के दिलों में वे सदा के लिए अमर रहेंगे। ★

पेद्दापल्ली की गलियों में गूंजता 'कोटन्ना अमर रहें' का नारा!

दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के तीस बरस!

आधार इलाके के लक्ष्य से जनता की राजसत्ता की स्थापना करते हुए, ऑपरेशन ग्रीन हंट का सामना करते हुए आगे बढ़ रही दण्डकारण्य जनता के समर्थन में खड़े हो!

दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के 30 बरस पूरे हुए हैं। तीस साल पहले कुछ गुरिल्ला दस्तों के रूप में शुरू होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां आज महाराष्ट्र के गड़चिरोली, चंद्रपुर व गोंदिया जिलों तक तथा छत्तीसगढ़ के अविभाजित बस्तर के पांच जिलों के अलावा राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, रायपुर व महासमुंद तक फैल गईं और फैल रही हैं। मुट्ठी भर लोगों से शुरू होने वाला दण्डकारण्य संघर्ष आज एक संगठित क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है जिसके अंदर दसियों हजार सदस्यता प्राप्त विभिन्न जन संगठन तथा कुछ हजार संख्या के पीएलजीए बल मुख्य शक्ति हैं।

2 नवम्बर 1980 को हुई कॉमरेड पेद्दि शंकर की शहादत से शुरू कर इन तीस सालों में विभिन्न स्तर के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता - करीब दो हजार साथियों ने अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर किया जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण व विकास में अपना योगदान दिया था। इन सबकी कुरबानियों की बदौलत ही आज दण्डकारण्य में 'सभी अधिकार जनताना सरकार को' के नारे के साथ प्राथमिक स्तर पर जनता की राज्यसत्ता की स्थापना की जा रही है। इनकी कुरबानियों की बदौलत ही इस जायज आंदोलन के खिलाफ लुटेरे शासक वर्गों द्वारा चलाए गए जन-जागरण दमन अभियानों और फासीवादी सलवा जुडूम को पराजित करने में हमें कामयाबी मिली। इनके बलिदानों के फलस्वरूप ही आज दण्डकारण्य में जन सेना (पीएलजीए) और जन आंदोलनों का विकास हुआ है जिससे उन कॉर्पोरेट संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की साजिशें विफल कर दी जा रही हैं जो यहां की प्राकृतिक संपदाओं को हड़पने के फिराक में हैं। इन तमाम वीर शहीदों को दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि पेश करती है।

तीस साल में जनयुद्ध की बदौलत दण्डकारण्य जनता द्वारा हासिल कामयाबियों का संक्षिप्त लेखा-जोखा :

1. ग्राम और क्षेत्रीय स्तर पर लुटेरे वर्गों की राजसत्ता को ध्वस्त कर जनता की राजनीतिक सत्ता की स्थापना की गई। जनताना सरकार के नाम से गठित हो रही नई जन राजसत्ता के अंगों के नेतृत्व में जनता ने कृषि विकास, शिक्षा, चिकित्सा, वन सुरक्षा, संस्कृति, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में पहलकदमी ली ताकि अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए जनयुद्ध को आगे बढ़ाया जा सके। सहकारिता और सामूहिकता के आधार पर तालाबों का निर्माण, फलदार वृक्ष लगाना, साग-सब्जियों की खेती, मछली पालन, सामूहिक बीज बैंकों का संचालन आदि कार्यों में जनता बढ़-चढ़कर भाग ले रही है। शासक वर्गों के 'विकास' के नमूने के उलट जोकि वर्गीय शोषण व वर्ग-भेदों को बढ़ाने वाला और पराधीनता पर आधारित है, दण्डकारण्य जनता द्वारा सामने लाया जा रहा विकास का यह नमूना, जोकि चौमुखी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता पर आधारित है, आने वाले दिनों में निर्मित की जाने वाली नई जनवादी अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा।
2. यहां की जनता तीन लाख एकड़ से ज्यादा वन भूमि और सामंती वर्गों की जमीन पर कब्जा कर उसमें खेती कर रही है। तीस बरसों से जारी वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप आज दण्डकारण्य के संघर्ष-क्षेत्रों में कोई भूमिहीन किसान नहीं रह गया। देश के अन्य इलाकों की तुलना में यहां पर भुखमरियां नहीं हैं। और किसानों की आत्महत्या का एक भी मामला नहीं है।
3. पुलिस, वन विभाग, राजस्व विभाग, माइनिंग माफिया, व्यापारी, तेंदुपत्ता ठेकेदार, पेपरमिल प्रबंधन आदि सभी के जुल्मों, रिश्वतखोरी और महिलाओं पर यौन हिंसा को खत्म किया गया। यहां जनता तेंदुपत्ता और बांस कटाई की जो मजदूरी दर हासिल कर रही है, उतनी देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। मजदूरी दरों में 'समान काम के लिए समान वेतन' लागू हो रहा है।
4. अंधविश्वासों और अशिक्षा को दूर करते हुए यहां की जनता शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा सुविधाओं व सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति हासिल कर रही है। अपनी मातृभाषा गोण्डी (कोया) में पाठ्यपुस्तकों को तैयार कर सौ से ज्यादा गांवों में जनताना सरकार की अगुवाई में पाठशालाओं का संचालन करते हुए नई शिक्षा प्रणाली की नींव रख

रही है। यहां पर जनता की जनवादी संस्कृति का विकास हो रहा है जो सड़ी-गली सामंती व साम्राज्यवादी संस्कृति से पूरी तरह भिन्न है।

5. विभिन्न आदिवासी कबीलों में लागू पितृसत्ता, पुरुष-प्रधानता के अलावा सरकारी हिंसा और अपमान के खिलाफ लड़कर दण्डकारण्य की महिलाओं ने कई कामयाबियां दर्ज कीं। जबरिया शादियां खत्म हो चुकी हैं। स्त्री-पुरुषों के बीच जनवादी सम्बन्ध कायम हो रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी आधे हिस्से तक बढ़ी है। देश के अन्य इलाकों की तरह यहां महिलाओं पर प्रताड़नाएं और अत्याचार नहीं हैं। करीब एक लाख सदस्यता के साथ 'क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन' सरकार के खिलाफ संघर्षरत महिला संगठनों में देश के सबसे बड़े संगठन के रूप में उभरा है।
6. दण्डकारण्य में छिपी हुई अपार प्राकृतिक संपदाओं को लूटने की टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, निको, टेक्सास पावर कार्पोरेशन, वेदांता आदि कॉर्पोरेट व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तमाम कोशिशें नाकाम कर दी गईं। 'विकास' के नाम पर आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित करने वाली सरकार की ढोंगी योजनाओं का प्रतिरोध किया गया। 'जल-जंगल-जमीन पर अधिकार हमारा है' का नारा देकर पुलिस व अर्धसैनिक बलों के हमलों का मुकाबला कर जनता ने कई कामयाबियां हासिल कीं, जिसके फलस्वरूप कई इलाकों से माइनिंग माफिया को दुम दबाकर भागना पड़ा।
7. 'अगर जनता के पास जन सेना नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है' - माओ के इस कथन के मुताबिक जनता खुद को सशस्त्र कर रही है। जन मुक्ति गुरिल्ला सेना (पीएलजीए) के समर्थन से जनता ने दुश्मन की कई दमनात्मक मुहिमों को पराजित कर दिया। जनता ने इस सेना की अगुवाई में अपना खून बहाकर फासीवादी सलवा जुडूम को परास्त कर एक नया अध्याय रच दिया।

उपरोक्त प्रधान कामयाबियों को दण्डकारण्य की जनता ने दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते पर चलकर हासिल किया। कई उतार-चढ़ावों और जीत-हार-जीत के सिलसिले में ही इन कामयाबियों को हासिल किया। ये पिछले 45 सालों से देश के विभिन्न हिस्सों में जारी माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन की कामयाबियों का हिस्सा ही हैं। कई दमनकारी अभियानों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने वाला दण्डकारण्य आंदोलन आज एक क्रूरतम सरकारी हमले का सामना कर रहा है, जोकि अभूतपूर्व है। 2005 से सलवा जुडूम के नाम से तथा 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से लगातार जारी फासीवादी हमले में पिछले साढ़े पांच सालों के दौरान सरकारी बलों ने 1500 से ज्यादा लोगों की जानें लीं। सैकड़ों लोगों को घायल किया। सैकड़ों महिलाओं के साथ पुलिस, एसपीओ और अर्धसैनिक बलों ने सामूहिक बलात्कार किया। 650 से ज्यादा गांवों को जलाकर राख कर दिया। सम्पत्तियों और फसलों को तबाह कर दिया। फसलों की रखवाली करने वाले नौजवानों को गोली मारकर 'मुठभेड़' की घोषणाएं कीं। अगर किसी ने इसका जरा भी विरोध किया, ऐसे हर शख़्स को सरकारें दुश्मन मानते हुए प्रताड़ित व परेशान कर रही हैं। वे जहां एक तरफ मीडिया को अपने काबू में रखकर जनता के खिलाफ चलाए जा रहे अन्यायपूर्ण युद्ध के तहत जारी अंतहीन हिंसा व जुल्मों पर परदा डाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता और जनसेना द्वारा जारी आत्मरक्षात्मक युद्ध का गलत चित्रण करते हुए जहरीला दुष्प्रचार कर रही हैं।

दरअसल आज देश के तमाम माओवाद-प्रभावित इलाके ऐसे इलाके भी हैं जहां अपार प्राकृतिक संपदाओं का भण्डार है। बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सैकड़ों एमओयू पर दस्तखत कर रखे हैं ताकि इन सारी सम्पदाओं का दोहन किया जा सके। खासकर ऐसी पृष्ठभूमि में, जबकि साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था महामंदी की दलदल में फंसी हुई हो, ये कम्पनियां संसाधनों को लूटने-खसोटने के लिए और ज्यादा आक्रामकता व तेजी से घुसपैठ कर रही हैं ताकि उससे बाहर आ सकें। दण्डकारण्य में घुसने के लिए कई कम्पनियां ताक में बैठी हुई हैं। इन समझौतों पर अमल करने का मतलब है यहां के लाखों लोगों, खासकर आदिवासियों का बेघरबार होकर तितर-बितर हो जाना। यहां के जंगलों, पानी, जमीन और पर्यावरण का विनाश होना। इसीलिए जनता इस मनमानी लूट के खिलाफ दृढ़ता से लड़ रही है। इन संघर्षों का हमारी पार्टी समर्थन कर रही है और कुछ जगहों में नेतृत्व कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम शासक गिरोह माओवादी पार्टी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कहकर तथा माओवादी आंदोलन को आतंकवाद बताते हुए वाहियात दुष्प्रचार कर रहा है। जहां कॉर्पोरेट वर्गों का बदनाम दलाल चिदम्बरम इस ऑपरेशन ग्रीन हंट का 'सीईओ' के रूप में नेतृत्व कर रहा है, वहीं दण्डकारण्य में रमनसिंह, विश्वरंजन, आरआर पाटिल आदि इसे आक्रामकता से चला रहे हैं। इस फासीवादी हमले का मुकाबला कर परास्त करना दण्डकारण्य जनता का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पिछले 30 सालों में हासिल कामयाबियों को

बनाए रखने तथा उच्च स्तर की कामयाबियां हासिल करने के लिए दण्डकारण्य जनता को चाहिए कि वह और ज्यादा एकजुटता व दृढ़ संकल्प के साथ तथा संगठित रूप से अपने आत्मरक्षात्मक युद्ध को जारी रखे। इस जीवन-मरण युद्ध में प्राप्त होने वाली जीत-हार पर ही दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन का भविष्य और कुल मिलाकर दण्डकारण्य जनता का अस्तित्व मुख्य रूप से निर्भर रहेंगे। देश भर में बढ़ने वाले माओवादी जनयुद्ध और जन आंदोलनों की प्रगति पर भी वे निर्भर होंगे। हम देश के समूचे उत्पीड़ित जन समुदायों का आह्वान करते हैं कि वे सरकारों की तमाम जन विरोधी, साम्राज्यवाद-परस्त व दमनकारी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन तेज करें तथा माओवादी जनयुद्ध में भागीदार बनें।

इस मौके पर बुद्धिजीवियों, लेखकों, चिकित्सकों, पत्रकारों, मीडियाकर्मियों, छात्र-नौजवानों, अध्यापकों तथा देश के तमाम मजदूर-किसानों से हम दण्डकारण्य जनता की ओर से यह अपील करते हैं:

यूपीए की केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तालमेल के साथ जारी देशव्यापी पाशविक हमले के बीचोबीच ही दण्डकारण्य जनता अपनी राजसत्ता के अंगों और जन संगठनों को संगठित कर रही है। वह प्राथमिक स्तर पर ही सही, अपने वास्तविक विकास से जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों में शिरकत कर रही है। इस काम में आपके सहयोग व समर्थन की बेहद जरूरत है। **आइए! इस आंदोलन पर जारी फासीवादी दमन और कत्लेआमों के खिलाफ निर्भय होकर आवाज बुलंद करें। यहां पर राजसत्ता द्वारा बरती जा रही अमानवीयता और दरिंदगी को, जिसके बारे में बाहरी दुनिया बेखबर है, खुद अपनी आंखों से देखने और समझने के लिए इन इलाकों का दौरा करें। यह समझने की कोशिश करें कि यहां पर सच लिखने वाले पत्रकारों, बोलने वाले बुद्धिजीवियों और हर उस इंसान को जो असुविधा-जनक सवाल उठाता है, राजसत्ता क्यों प्रताड़ित कर रही है, क्यों उन्हें हिंसा का शिकार बना रही है और जेलों में कैद कर रही है। और राजकीय हिंसा का खण्डन करें। यहां पर जनता द्वारा सामने लाए जा रहे विकास के वैकल्पिक नमूने का हाथ उठाकर स्वागत करें। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण, संस्कृति आदि क्षेत्रों में आप अपने अनमोल सुझाव व सलाह दें, आलोचना करें ताकि विकास के इस नमूने को हृष्ट-पुष्ट किया जा सके। अपना निर्माणात्मक सहयोग दें। यहां पर आकार ले रही जनता की नई राजसत्ता अपनी नीतियों को बेहतर बना सके, इसमें आप अपने हिस्से का सहयोग दें। निर्माणात्मक प्रस्ताव पेश करें। आप सभी का स्वागत है।**

हमारी स्पेशल जोनल कमेटी दण्डकारण्य की जनता और पार्टी के कतारों का आह्वान करती है कि दण्डकारण्य क्रांतिकारी संघर्ष के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 10 फरवरी से, जोकि महान भूमकाल की बरसी है, 28 तारीख तक गांव-गांव में प्रचार अभियान, सभाओं, सम्मेलनों, जुलूसों, मशाल जुलूसों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का पूरे जोशोखरोश के साथ आयोजन किया जाए। इस मौके पर 'बंद' नहीं रहेगा।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

(... पेज 22 का शेष)

को हमें एक चुनौती के रूप में लेकर पूरा करने की जरूरत है। इसके लिए वस्तुगत परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं। परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि देश के कई बुद्धिजीवी, जनवादी, देशभक्त, प्रगतिशील लेखक, कलाकार और मीडियाकर्मी संघर्षरत जनता के पक्ष में खड़े होकर सरकारी हिंसा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को आतंकित करने के लिए सरकारें कई हथकण्डे अपना रही हैं जिसकी मिसाल के रूप में डॉ. बिनायक सेन को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बताया जा सकता है। ऐसे हालात में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार एक कठिन चुनौती ही होगी। हालांकि ऐसे तमाम लोगों पर दण्डकारण्य समेत देश के अनेक हिस्सों में जनयुद्ध द्वारा हासिल कामयाबियों का सकारात्मक प्रभाव है।

उपरोक्त चुनौतियों का हमें सामना करना चाहिए। दण्डकारण्य में दुश्मन द्वारा चलाए जा रहे फासीवादी सैन्य हमलों के बीचोबीच ही, उन्हें हराने के लक्ष्य से ही उपरोक्त चुनौतियों से हम निपट सकेंगे। दुश्मन आज जिस तीव्र संकट में फंसा हुआ है, उसके चलते कई ऐसे हालात सामने आ सकते हैं जिनका हम फायदा उठाकर जनयुद्ध को आगे बढ़ा सकेंगे। इस तरह फायदा उठाना एक कला है जिसमें हम सभी को पारंगत होना होगा। क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ सामने आ रहे कई प्रतिगामी और गलत सिद्धांतों का खण्डन करते हुए क्रांतिकारी सिद्धांत को समृद्ध बनाना भी एक कला है जिसमें हमें महारत हासिल करना चाहिए। यह भी एक चुनौती के रूप में दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के समक्ष है जो अब अपना तीसवां बरस पूरा करके इकतीसवां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ★

पीएलजीए के दस बरस के मौके केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन का आह्वान

जन मुक्ति गुरिल्ला सेना की 10वीं वर्षगांठ जोशोखरोश के साथ मनाओ!

जनता के खिलाफ भारतीय शासक वर्गों द्वारा जारी पाशविक 'ग्रीन हंट' हमले को जनयुद्ध के जरिए हरा दो!

प्यारे कॉमरेडो, दोस्तो व देशवासियों!

2 दिसम्बर 1999 को लुटेरे शासक वर्गों ने भारत के क्रांतिकारी नेता कॉमरेड्स श्याम, महेश और मुरली की हत्या की थी। हमारे इन प्यारे नेताओं की शहादत की प्रेरणा से ही वर्ष 2000 में इसी दिन जन मुक्ति गुरिल्ला सेना (पीएलजीए) का निर्माण हुआ था जिसका नेतृत्व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कर रही है। 2 दिसम्बर 2010 को पीएलजीए के दस बरस पूरे हो जाएंगे। भारत के इतिहास में शोषित जनता ने अपनी मुक्ति के लिए खुद की माओवादी जन सेना का निर्माण कर इस एक दशक में जबर्दस्त इतिहास रचा है। इस जन सेना ने उत्पीड़ित जनता के हितों को ही अपना हित मानकर, उनकी सेवक के रूप में तथा साम्राज्यवादी-दलाल नौकरशाह पूंजीवादी-सामंती वर्गों के खिलाफ जारी मुक्ति संग्राम में उनके हाथ में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में जनता के दिलों में खास जगह हासिल की। इस अवधि में हमारी जन सेना ने पुलिस, अर्ध-सैनिक, स्पेशल कमाण्डो (नगा, मिजो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएएफ, ग्रेहाउण्ड्स, एसओजी, बीएमपी, एसएपी, ईएफआर, कोबरा, सी-60 वगैरह) के भाड़े के बलों पर कोरापुट, सरंडा, गिरिडीह, जहानाबाद, रानिबोदली, उरपलमेट्टा, बलिमेला, नयागढ़, लाहेरी, सिल्दा, मुकरम (ताड़िमेट्ला), कोंगेरा, लखिसराय जैसे कई साहसिक कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण किए। हमारे बहादुर पीएलजीए बलों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों का सफाया करते हुए जिस ऐतिहासिक ताड़िमेट्ला ऑपरेशन को सफल बनाया, उसने भारत के शासक वर्गों की चूलें हिला दीं। इस एक दशक के दौरान हमारी जन सेना ने कुल दो हजार पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों का सफाया कर, करीब-करीब इतनी ही संख्या में घायल कर 2500 हथियार उनसे छीनकर जनता को हथियारबंद किया। अपने व्यवहार से उसने साबित किया है कि 'हमारा हथियारों का प्रधान स्रोत खुद दुश्मन ही है।' हमारी जन सेना रणनीतिक इलाकों में पनप रही क्रांतिकारी जन राजसत्ता की रक्षा में मजबूती से खड़ी रही। इन कामयाबियों ने भारत के उत्पीड़ित जनता, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और उत्पीड़ित तबकों में पीएलजीए पर विश्वास दुगुना कर दिया। आइए, हमारी जन सेना द्वारा हासिल कामयाबियों की प्रशंसा करते हुए, देश भर में जनता को जागृत करते हुए पीएलजीए की दशाब्दि समारोहों को जोशोखरोश के साथ मनाएं। व्यापक जन समुदायों को बड़े पैमाने पर हथियारबंद और भर्ती करते हुए पीएलजीए को और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करें।

इस एक दशक के दरमियान जनयुद्ध में दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए सैकड़ों जांबाज गुरिल्ला कमाण्डरों, कमिस्सारों और जन सैनिकों ने अपना गर्म लहू बहा दिया। इन सभी को नाम-नाम पर सलामी देते हुए सिर झुकाकर श्रद्धांजलि पेश करेंगे! हजारों जनता, जन कार्यकर्ता, पीएलजीए के जन सैनिक और पार्टी नेता दुश्मन के हत्थे चढ़कर जेलों में बंद हुए हैं। दुश्मन के शिविर में भी वे समझौताहीन संघर्ष जारी रखते हुए जेलों को क्रांति के केन्द्रों में तब्दील कर रहे हैं। उनकी बोल्शेविक चेतना का अभिनंदन करते हुए उन्हें फिर से क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदार बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

साम्राज्यवादी और भारत में उनके ताबेदार दलाल नौकरशाह पूंजीपति व जमींदार वर्ग हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अपना शिकंजा कसकर लाखों करोड़ रुपए लूटकर इस काले धन से देश में समानांतर सत्ता चला रहे हैं। इनकी सम्पदा जहां 1984 में स्विस बैंकों में सिर्फ 1300 करोड़ रुपए थी, जबकि यह 2006 तक 72,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यह जगजाहिर है कि विकास के नाम पर आवंटित राशि में आधी से ज्यादा भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों, पुलिस-प्रशासनिक महकमों के पेट में ही चली जाती है। इस पृष्ठभूमि में माओवादी प्रभावित इलाकों में देश के शासक वर्ग विकास का कौन सा नमूना लागू करना चाहते हैं? देश में 77 प्रतिशत से ज्यादा जनता रोजाना 20 रुपए से कम आमदनी से; बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के विशाल जंगली इलाकों में आदिवासी और दलित फटेहाल कपड़ों और भीषण गरीबी से जिंदा लाशों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक इन इलाकों की गरीबी से ही क्रांतिकारी आंदोलन जुड़ा हुआ है। रोज-रोज गहरा हो रहे संकट से उबरने के लिए साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (वेदांता, पोस्को, आर्सेल्लार

मित्तल, टाटा, एस्सार, जिंदल, रस अलखैमा वगैरह) ने भारत में, खासकर मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी इलाकों में अनमोल प्राकृतिक सम्पदाओं और लोहा, बाक्साइट, कोयला, यूरेनियम, ग्रानाईट, ग्राफाइट, चांदी, सोना आदि खनिजों को सस्ते में लूटकर ले जाने के लिए गिद्ध नजर फैलाई है। बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध प्रदेश, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की सरकारों के साथ हजारों समझौते (एमओयू) करके लाखों एकड़ जमीनों में सैकड़ों एसईजेड, खदानें, भारी बांध आदि परियोजनाएं शुरू कर देने से करोड़ों लोगों के अस्तित्व पर संकट की ऐसी स्थिति आई है कि वे जिस जल-जंगल-जमीन पर पीढ़ियों से निर्भर थे उसे छोड़कर पलायन करने को मजबूर किए जा रहे हैं।

क्रांतिकारी आंदोलन के उन्मूलन के लिए साम्राज्यवाद-निर्देशित एलआईसी रणनीति में दीर्घकालीन योजना के तहत कार्पेट सेक्यूरिटी का निर्माण एक मुख्य दावपेंच है। इसके तहत हर 3-5 किलोमीटर की दूरी पर एक बेसकैम्प खोलकर उसे मजबूत किया जा रहा है। क्रांतिकारी जनता, जन संगठनों, क्रांतिकारी जन सरकारों (आरपीसी), पार्टी नेताओं और जन सैनिकों का कत्लेआम करने के लिए इन बेसकैम्पों से स्पेशल बलों (स्कॉर्पियन, कोबरा, ग्रेहाउण्ड्स वगैरह) और प्रति-क्रांतिकारी हत्यारे गिरोहों (दण्डकारण्य में सलवा जुडूम, कोया कमाण्डो; बिहार-झारखण्ड में सेंदेरा, टीपीसी, जेपीसी, लोरिक सेना, पीएलएफआई, जेएलटी, एसपीएम, ग्राम रक्षा दल, शांति सेना आदि तरह-तरह की प्रति-क्रांतिकारी सेनाओं; पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी हर्मद बाहिनी व नागरिक सुरक्षा समिति; ओड़िशा के नारायणपटना इलाके में शांति सेना आदि) को तैयार कर उकसाया जा रहा है। इन राज्यों की आदिवासी व गैर-आदिवासी क्रांतिकारी जनता पर इन बलों ने अनगिनत व अकथनीय अत्याचार किए हैं। 'घेराव करो, पकड़कर गोली मार दो' वाले उन्मूलनात्मक अभियानों के तहत घरों को जलाना, फसलों व अनाज को जलाना, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट वगैरह रोजमर्रा की बातें हो गईं। नवजात बच्चे, गर्भवती महिलाएं, नव विवाहित जोड़े - सभी इनकी क्रूरता का शिकार बन रहे हैं। चाकुओं से कोख को चीरकर भ्रूण को बाहर निकालकर फेंक देने की घटनाओं से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी पाशविकता किस हद तक पहुंच चुकी होगी।

आज दुनिया भर में साम्राज्यवाद तीखे संकट में फंसा हुआ है, जबकि भारत में भी इस संकट का तीव्र प्रभाव दिखाई दे रहा है। यूपीए के दोबारा सत्ता में आने के बाद जनता के आंदोलनों की परवाह किए बगैर वह दूसरी पीढ़ी के सुधारों को आक्रामकता से लागू करने लगी है। विनिवेशीकरण, रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाना, बीमा आदि संस्थाओं में साम्राज्यवादी पूंजी को 70 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाना, खुदरा और शिक्षा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजीनिवेश बढ़ रहे हैं। परमाणु समझौता करके सरकार ने देश को ज्वालामुखी के मुहाने पर ला दिया है। भारत में पैठ कर रही विदेशी संस्थागत पूंजी (एफआईआई) और विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी (एफडीआई) के जरिए देश की अर्थव्यवस्था पर साम्राज्यवाद अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। इन नीतियों के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के गठन के लिए तथा जनता के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इजाजत देने से देश में लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। पर्यावरण को गंभीर खतरा पहुंच रहा है। औद्योगिक, मैनुफैक्चर व सेवा के क्षेत्रों में विदेशी पूंजी तेजी से आ रही है। निर्यात के क्षेत्र में तीव्र प्रभाव पड़ने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। देश में महंगाई अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ी है जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों का आर्थिक जीवन अत्यंत दुर्भर बन गया है।

आदिवासियों के संघर्षों की बदौलत लाए गए 5वीं व 6वीं अनुसूची के कानूनों की भी धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासियों को बड़े पैमाने पर जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। इससे आदिवासियों के साथ-साथ समूची जनता ने साम्राज्यवादियों और उनके दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के खिलाफ देश भर में विद्रोह शुरू किए हैं। कलिंगनगर, सिंगूर, नंदिग्राम से शुरू करके लालगढ़, नारायणपटना जमीन संघर्ष तक के कई संघर्षों के परिणामस्वरूप कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को संघर्ष के इलाकों से पीछे हटना पड़ा। ओड़िशा में माली, देवमाली, नियमगिरी, काशीपुर, बोलांगिर, बरगढ़, कियोंझर, सुंदरगढ़ व फूलबनि में; आंध्रप्रदेश में विशाखा बाक्साइट खदानों, पोलावरम बांध, श्रीकाकुलम के सोम्पेटा में थर्मल बिजली संयंत्र के खिलाफ; बिहार में गया और पलामू; झारखण्ड में गिरिडीह, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, लोहरदग्गा व छतरा में लोहा व कोयला खदानों के खिलाफ; दण्डकारण्य में लोहण्डीगुड़ा, रावघाट, पल्लामाड़, बोधघाट में विस्थापन की समस्या को लेकर; उत्तर तेलंगाना में सिंगरेनी ओपनकॉस्ट खदानों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 'यमुना एक्सप्रेस वे' के खिलाफ जन आंदोलन तेजी से उभरे हैं। देश में कुछ और विद्रोहों के लिए जमीन तैयार हो रही है।

पृथक तेलंगाना, गोरखालैण्ड जैसे जुझारू पृथक राज्य आंदोलन शासक वर्गों को झकझोर रहे हैं। कश्मीर, मणिपुर आदि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के शोले कभी बुझ ही नहीं रहे हैं। हाल ही में कश्मीर में जून से लेकर सितम्बर तक 100 से ज्यादा लोग सरकारी हिंसा का शिकार बन गए हैं। सरकार द्वारा बनाई जा रही नई खनिज नीति व नई शिक्षा नीति से साम्राज्यवाद व देश की जनता के खिलाफ अंतरविरोध और भी तीखा होने वाला है। इस संकट के प्रभाव से सरकार-विरोधी संघर्षों में देश भर में कई नई ताकतें सामने आ रही हैं। मजदूरों, किसानों जैसे बुनियादी वर्गों के अलावा निम्न पूंजीवादी ताकतें भी आंदोलनों में जुझारू भूमिका निभा रही हैं। जहां एक तरफ लुटेरे शासक वर्ग जनता से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ माओवादी पार्टी जनता के सच्चे नेतृत्व के रूप में उभरकर आ रही है। देश के राजनीतिक मोर्चे पर माओवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में जनता का विश्वास हासिल कर रही है। यह शासक वर्गों के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' है। इसी पृष्ठभूमि में माओवादी आंदोलन का सफाया करने की मंशा से ग्रीन हंट ऑपरेशन के नाम से भारी सैन्य आक्रमण शुरू किया गया है। दूसरे शब्दों में यह भारत की व्यापक जनता के खिलाफ युद्ध है।

केन्द्रीय सैन्य कमिशन (सीएमसी) का आह्वान:

प्यारे लोगो! देश में, खासकर आदिवासी इलाकों में अनमोल खनिज संपदाओं व जमीनों को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश के तहत, इस राह में रुकावटें डालने वाली ताकतों का सफाया करने के लिए तथा पुष्पित हो रही वैकल्पिक जन राजसत्ता को नोच डालने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी ऑपरेशन ग्रीन हंट दरअसल 'जनता के खिलाफ युद्ध' है। इस अन्यायपूर्ण युद्ध को पराजित करें! संघर्षरत आदिवासी क्रांतिकारी जनता का समर्थन करें! तमाम आदिवासियों पर आतंकवादी का ठप्पा लगाकर पागल भेड़ियों की तरह गांव पर हमले करके सैकड़ों आदिवासियों का कत्लेआम करते हुए, उनका सब कुछ लूटने व तबाह करने वाले पुलिस बलों के पाशविक हमलों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से आगे आएं! क्रांतिकारी आंदोलन पर जहर उगलने वाले पूंजीवादी प्रचार माध्यमों के दुष्प्रचार को ठुकरा दें! माओवादी गुरिल्ले इसी मिट्टी से पैदा हुए हमारे अपने लाड़ले ही हैं। जनता के हितों को अपना हित मानकर इस धरती मां को लुटेरे वर्गों के शिकंजे से आजाद कराने के लिए भाड़े के बलों से लड़ने को निकले जन मुक्ति की ताकतें हैं। इसलिए आप क्रांतिकारी आंदोलन का पक्ष लीजिए! अगर हम इस शत्रु हमले को पराजित नहीं करते हैं, अगर क्रांतिकारी आंदोलन को, माओवादी पार्टी को, जन मुक्ति गुरिल्ला सेना को, वैकल्पिक जन राजसत्ता के अंगों व जन संगठनों को खत्म करने की दुश्मन की साजिशों को पराजित नहीं करते हैं तो क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा हासिल सारी अनमोल उपलब्धियां पलट दी जाएंगी। इसलिए दुश्मन को अलग-थलग कर पराजित करने में आप अपनी भूमिका अदा करें! पीएलजीए में बड़े पैमाने पर शामिल होकर जन सेना के बलों को कई गुना बढ़ाकर उसे मजबूत बनाएं! जमीन, राजनीतिक हुकूमत, जनतंत्र, जन सेना का निर्माण व आत्मनिर्भरता के नारों से आज देश के कई इलाकों में उमड़ रहे जन आंदोलनों के साथ अपना हाथ मिलाएं। पीएलजीए के सशस्त्र प्रतिरोधी संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाएं! लुटेरे वर्गों का जड़ से नाश किए बिना कोई बुनियादी बदलाव नहीं आने वाला है। जूठन के टुकड़ों की तरह फेंके जाने वाले सुधारों से जनता की जिंदगियां और भी बर्बाद ही हो जाएंगी, न कि सुधर जाएंगी। जनता की एकता को तोड़ने की साजिश ही है सुधार कार्यक्रम। इन्हें ठुकराते हुए वैकल्पिक नई जनवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए कदम बढ़ाएं! आइए, लड़ने का साहस करते हैं तो अंतिम जीत जनता की ही है!

★ **जल-जंगल-जमीन पर अधिकार के लिए हथियारबंद जन आंदोलनों का निर्माण करो - उन्हें आगे बढ़ाओ!**

★ **जमीन-राजनीतिक हुकूमत-जनतंत्र-जन सेना का निर्माण-आत्मनिर्भरता के नारों से संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ो!**

★ **हर गांव को एक फौलादी किले में, हर घर को एक लड़ाई के मोर्चे में और तमाम जनता को हथियारबंद जन सैनिकों के रूप में विकसित करना चाहिए!**

★ **जन मुक्ति गुरिल्ला सैनिकों व जनता की एकजुटता से दुश्मन का पाशविक हमला 'ग्रीन हंट' को पराजित करो!**

★ **जन सेना के बिना जनता के पास कुछ नहीं होगा!**

★ **जनता ही इतिहास का निर्माता है!**

★ **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जिंदाबाद!**

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ,

केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी)

19 सितम्बर 2010 **भाकपा (माओवादी)**

दण्डकारण्य आंदोलन के सामने मौजूद चुनौतियां - हमारे कार्यभार

- कामरेड सोनू, सीसी सदस्य

दण्डकारण्य में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू हुए तीस बरस पूरे हो गए। 1980 के जून-जुलाई महीनों में तत्कालीन भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) के नेतृत्व में चंद गुरिल्ला दस्तों ने दण्डकारण्य के विशाल जंगलों में प्रवेश किया। आंध्रप्रदेश के आदिलाबाद, खम्मम, पूर्वी गोदावरी और विशाखापटनम जिलों के वन क्षेत्र के अलावा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला और छत्तीसगढ़ के पुराने बस्तर जिले में पहुंचकर पार्टी ने जनता को गोलबंद किया। शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाकर एक व्यापक आंदोलन की नींव डाली। पिछले 30 सालों से इस व्यापक वन क्षेत्र में, प्रधान रूप से आदिवासी जनता के बीच क्रांतिकारी आंदोलन न सिर्फ मजबूत हुआ, बल्कि आज आधार इलाके के लक्ष्य से कठिन चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रहा है। पिछले 30 बरसों में इस आंदोलन के दौरान जो प्रमुख उपलब्धियां हासिल की गईं, वो इस प्रकार हैं:

1) 'जमीन जोतने वालों को ही' के नारे के आधार पर 8 डिवीजनों में मौजूद करीब पांच हजार गांवों के कम से कम एक लाख परिवार 3 लाख से ज्यादा एकड़ वन भूमि और सामंती मुखियाओं की जमीन पर कब्जा बनाकर खेती कर रहे हैं। तीन दशकों से जारी सशस्त्र कृषि क्रांति की यह सबसे बड़ी कामयाबी है।

2) तीस सालों से जारी जनयुद्ध के फलस्वरूप दण्डकारण्य में कई सौ पंचायतों में क्रांतिकारी जन कमेटी - जनताना सरकार - की सत्ता कायम हो गई। जनता ने करीब सैकड़ों गांवों में शोषक-लुटेरों की सत्ता को ध्वस्त कर या निष्क्रिय कर जनताना सरकारों का चुनाव कर जनता के जनवाद की स्थापना की जो उसकी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कामयाबी है।

3) 'जंगल पर सभी अधिकार आदिवासियों को' - इस क्रांतिकारी लक्ष्य के साथ लड़कर उत्पीड़ित जनता ने जंगल पर सरकार के आधिपत्य को खत्म कर दिया। भारत के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ को रोककर अनमोल प्राकृतिक संपदाओं को बचाना और उनका इस्तेमाल अपने और देश के विकास के लिए हो, इस दिशा में कदम बढ़ाना - इसे राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में जनता द्वारा हासिल एक और बुनियादी कामयाबी के रूप में बताया जा सकता है।

4) कबीलाई पितृसत्ता, पुरुष-प्रधानता, सरकारी हिंसा, अपमान, अत्याचार, दमन आदि के खिलाफ विद्रोह का झण्डा उठाने वाली दण्डकारण्य की आदिवासी और शोषित महिलाओं ने खेती के कामों के साथ-साथ राजनीतिक आसमान में, जन राजनीतिक सत्ता में तथा सामाजिक जीवन में आधा हिस्सा हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह एक और उल्लेखनीय कामयाबी है।

5) अंध-विश्वासों से भरी, उत्पादन की ताकतों के विकास के रास्ते में अवरोध बनी और सड़ी-गली हो चुकी कबीलाई रूढ़िवादी संस्कृति, हिंदू ध र्मोन्मादी हमलों और हिंदू व ईसाई धर्मों की षड़यंत्रकारी घुसपैठ को रोकते हुए शिक्षा, विज्ञान, जन संस्कृति तथा प्रगतिशील व जनवादी विचारों का प्रचार-प्रसार करना अधिरचना के क्षेत्र में नएपन की ओर आगे कदम है।

उपरोक्त उपलब्धियों को हासिल करने के दौरान दण्डकारण्य में पिछले 30 सालों में करीब दो हजार जनता, क्रांतिकारी जन संगठनों के कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आगे बढ़ने से पहले, आइए, इन सभी को पूरी विनम्रता से क्रांतिकारी जोहार पेश करें और पिछले 30 सालों की कामयाबियों की रक्षा करते हुए, उनकी नींव पर दृढ़ता से खड़े होकर अंतिम विजय हासिल करने की शपथ लें।

भारत में जारी क्रांतिकारी आंदोलन और उसके अंतर्गत जारी दण्डकारण्य आंदोलन हाल के दिनों में देशवासियों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जो दुनिया में लम्बे समय से लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक है, कुछ उल्लेखनीय राजनीतिक व सैनिक कामयाबियां हासिल करते हुए आज देश के उल्लेखनीय हिस्से में अपने आंदोलन का विस्तार कर चुकी है। भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में एक है जहां दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते पर चलते हुए इलाकेवार राजसत्ता कायम करने के लक्ष्य

से गुरिल्ला जोनों में गुरिल्ला आधार-क्षेत्रों का निर्माण करते हुए क्रांतिकारी जन कमेटियों को मजबूत किया जा रहा है। विश्व सर्वहारा के आखिरी आधार-क्षेत्र चीन में पूंजीवाद की पुनरस्थापना के बाद के इन तीन दशकों में दुनिया भर में घटी घटनाओं में भारत जैसे एक विशाल और भारी जनसंख्या वाले देश में इस तरह का विकासक्रम जो उभरकर आ रहा है वह अपने आपमें महत्वपूर्ण है। साथ ही, 'मार्क्सवाद का सफाया', 'इतिहास का अंत' आदि जहरीला दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर छेड़ने वाला साम्राज्यवाद आज खुद ही तीव्र वित्तीय व आर्थिक संकट में फंसकर छटपटा रहा है। 21वीं सदी के पहले दशक के इस घटनाचक्र की पृष्ठभूमि में भारत में जो नया उजाला दिखाई दे रहा है वह खासतौर पर उल्लेखनीय है।

उपरोक्त दो कारण ही साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों और भारत के लुटेरे शासक वर्गों के गले नहीं उतर रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार 2006 से लगातार यह कहती आ रही है कि माओवादी आंदोलन ही देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जून 2009 में केन्द्र सरकार ने यूएपीए (गैर-कानूनी गतिविधियों का निरोधक विधेयक) के तहत इस पार्टी के साथ-साथ कुछ क्रांतिकारी जन संगठनों और क्रांतिकारी जन कमेटियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक उसी समय लालगढ़ में सैन्य अभियान चलाया गया जिसके बारे में केन्द्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लै ने यह घोषणा की थी यह कुछ महीनों बाद शुरू किए जाने वाले 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' का पूर्वाभ्यास है। उसके तुरंत बाद, अगस्त माह में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ। देश भर में माओवादी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन का जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से 'होल्ड-कंट्रोल-बिल्ड' (यानी कब्जा करना-काबू करना-निर्माण करना) की नीति से यह ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके लिए रणनीतिक नजरिए से पांच से सात साल की समयावधि निर्धारित की गई। इसके लिए तीन लाख से ज्यादा केन्द्रीय व राज्यों के सशस्त्र बलों को तैनात किया गया। इसके 16 महीनों बाद देश के 60 आदिवासी जिलों के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई जो दरअसल साम्राज्यवाद-प्रायोजित सुधार कार्यक्रम के अलावा कुछ नहीं है। उसके एक माह बाद दण्डकारण्य में भारतीय सेना की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई। तथाकथित आजादी के बाद माड़ इलाके में सेना पहली बार कदम रखने जा रही है। आज से सौ साल पहले 1910 के महान भूमकाल जन विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रितानी उपनिवेशवादियों की सेना माड़ में उतारी गई थी। माड़वासी आज फिर एक बार सेना का सामना करने जा रहे हैं। उस समय सिर्फ एक साम्राज्यवाद का उनको सामना करना पड़ा था, लेकिन आज कई साम्राज्यवादी ताकतों का समर्थन इस सेना को प्राप्त है। इन सभी पहलुओं को एक क्रम में और उनके बीच के आपसी संबन्धों समेत समझने पर ही हम 30वें साल में दण्डकारण्य आंदोलन के सामने मौजूद चुनौतियों का आकलन कर सकेंगे।

निश्चित रूप से आज दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के सामने सबसे बड़ा व चुनौतीपूर्ण कार्यभार भारतीय अर्धसैनिक व सैनिक बलों से लोहा लेना ही है। लुटेरे शासक वर्गों द्वारा इन अर्धसैनिक व सैनिक बलों को जो कर्तव्य निर्देशित किया गया, जिसकी वे खुलेआम घोषणा कर रहे हैं वह है 'अपार प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपूर दण्डकारण्य को माओवाद-रहित इलाके में बदलना।' ऐसे में दण्डकारण्य की जनता को अर्धसैनिक व सैन्य बलों का मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) उनका किस तरह नेतृत्व करेगी? ये काफी दिलचस्प सवाल हैं जिनके साथ भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। आइए, इस पर सरसरी नजर डाली जाए।

(1) दण्डकारण्य की जनता पिछले तीस बरसों से भाकपा (माओवादी) की अगुवाई में लड़ती आ रही है। 1984, 1991, 1997, 2005 और 2009 में दण्डकारण्य की जनता ने सरकारी दमनात्मक अभियानों का सामना किया। उस समय वे ही बहुत बड़े दमनात्मक अभियान थे। पिछले 30 सालों में पांच बड़े दमन अभियानों का मुकाबला करते हुए दण्डकारण्य की जनता ने खासा अनुभव हासिल किया है। इस दौरान जनता ने कई कुरबानियां दीं। कई मुसीबतों का सामना किया। इस दौरान कई उल्लेखनीय कामयाबियां भी हासिल कीं। हालांकि अभी तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ ही यह लड़ाई चलती रही। अभी से सेना का उन्हें सामना करना पड़ेगा जो एक नया पहलू है। यह पुरानी चीजों से बुनियादी रूप से ही भिन्न है। हालांकि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बार-बार कह रहा है कि माओवादियों के खिलाफ थलसेना और वायुसेना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे या वाइरस के रूप में पेश करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने हाल के दिनों में नया राग आलापना शुरू किया है कि 'वे भी अपने ही बच्चे हैं जो गरीबी व अन्य समस्याओं के कारण गलत राह पर चल पड़े हैं, अत: उनके साथ संवेदनशीलता के

साथ पेश आना चाहिए'। हालांकि पिछले 63 सालों से बढ़ रही गरीबी का इस डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। सच यह है कि यह बयानबाजी उनके मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। जनता की लड़ाकू चेतना को कुंद बनाने के लिए वे सेना की तैनाती को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए यह जरूरी हो गया ताकि सेना के खिलाफ व्यापक जन समुदायों की गोलबंदी न हो। ग्रीन हंट को शरू करने के बाद वे ऐसा नहीं कर पाए थे। उनकी कोशिश यह थी कि ऑपरेशन ग्रीन हंट को 'वॉर ऑन टेर्रर' (आतंक पर युद्ध) के रूप में चित्रित किया जाए। लेकिन देश के व्यापक जनवादी व देशभक्त समुदाय ने उसका पर्दाफाश करते हुए यह साबित किया कि वह 'वॉर ऑन पीपुल' (जनता के खिलाफ युद्ध) है। इसलिए अब वे शुरू से ही सेना की तैनाती को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसका पूरी तरह पर्दाफाश करना चाहिए। विश्व सर्वहारा का समर्थन जुटाते हुए देश के व्यापक जन समुदायों के सक्रिय समर्थन से दण्डकारण्य की जनता को सेना के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीतिक, मानसिक, सैनिक व पादार्थिक सभी प्रकार से तैयार होना चाहिए। जनता को यह समझ लेना चाहिए कि शासक वर्गों ने कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद, यहां जनता के खिलाफ सेना उतारकर अब एक और मोर्चा खोला जा रहा है। दण्डकारण्य के इन तीस सालों के संघर्ष की बदौलत जनता द्वारा हासिल कामयाबियों को ऊंचा उठाते हुए आज के इस अहम और चुनौतिपूर्ण कार्यभार को एकजुटता के साथ पूरा करना चाहिए। अब यह देखें कि इसके लिए और क्या-क्या करना होगा।

(2) सेना का मुकाबला करने के लिए हमारा प्रधान हथियार क्या है? दण्डकारण्य में कदम रख रही भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए जनता के हाथों में सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी सेना - जन मुक्ति गुरिल्ला सेना है। इसे कई गुना ताकतवर बनाना चाहिए। इसकी उम्र अब सिर्फ दस साल है और इसका अनुभव भी कम है। लेकिन इसका मुकाबला अब एक भारी ताकत से है जिसे दुनिया की आधुनिक व भारी-भरकम सेनाओं में चौथी कहा जाता है।

दण्डकारण्य में पीएलजीए में कमाण्डर और सैनिक आमतौर पर स्थानीय आदिवासियों के बेटे और बेटियां ही हैं। वे फौजी पोशाक पहनकर सैन्य संगठनों में संगठित होकर प्रशिक्षित हो रहे हैं। पीएलजीए के अत्यधिक सैनिक 2005 और 2009 में दुश्मन के दमन अभियानों का प्रतिरोध करने के दौरान भर्ती हुए हैं। ये सभी अपने घरों के लिए, अपने खेतों के लिए, जंगलों और प्राकृतिक सम्पदाओं के बचाव के लिए जिस पर वे सदियों से निर्भर हैं, अपने अस्तित्व के लिए, एक शब्द में कहें तो अपने आपके लिए वे लड़ रहे हैं जिसके लिए वे अपने पूर्वजों से प्रेरणा पा रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना किसके लिए लड़ रही है? हालांकि वे भी मजदूर-किसानों और मध्यम वर्ग की संतानें हैं। सच यह है कि वे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वे अपना पेट पालने के लिए, तनख्वाहों के लिए और झूठी देशभक्ति से भड़का दिए जाने के कारण सैनिक बनकर इन इलाकों में आए हुए हैं। उनमें से एक बड़े तबके को हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। उन्हें समय-समय पर सच्चाई से अवगत करवाते रहना चाहिए। अहम बात तो यह है कि यहां की समूची जनता को दृढ़तापूर्वक संगठित करते हुए सशस्त्र बनाना चाहिए। आज पीएलजीए में शामिल नौजवानों की तुलना में कई गुना लोग उससे बाहर हैं। उन्हें हमें अपनी तरफ जीत लेना चाहिए। भारत के दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की पूंजी विशाल वन क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों को एक भारी तबाही की ओर तेजी से धकेल रही है, इस सच्चाई से हमें उन तमाम लोगों को विस्तारपूर्वक अवगत कराना चाहिए। जनसेना की ताकत और सरकारी सेनाओं की कमजोरियों के बारे में बताना चाहिए। पीएलजीए को राजनीतिक व सैनिक रूप से विकसित करना चाहिए। सैन्य शिक्षण में उन्हें निपुण बनाना चाहिए। जन सेना को क्रांतिकारी राजनीति के तहत फौलादी अनुशासन से प्रशिक्षित करना और जनता के सच्चे सेवकों के रूप में समर्पित होकर काम करने लायक विकसित करना एक रणनीतिक कार्यभार है। इसे दण्डकारण्य के पिछले 30 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होकर दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करना चाहिए। 'अगर जनसेना नहीं है तो जनता के पास कुछ भी नहीं है' इस सच्चाई को जनता के जीवन के साथ जोड़कर पीएलजीए को मजबूत करना चाहिए।

(3) 2005 के सलवा जुडूम से लेकर आज तक सभी प्रतिक्रियावादी दमनकारी अभियानों द्वारा की जा रही भारी तबाही के बीचोबीच ही जनता पीएलजीए के सहारे अपने आपको बचाते हुए खेती-किसानी कर रही है और वनोपजों का संग्रहण कर रही है। लेकिन अब चूंकि मुकाबला सेना से है, इसलिए जनता के कृषि कार्यों में गुणात्मक बदलाव लाने की जरूरत है ताकि जनता के जीवनस्तर को सुधारा जा सके और जनसेना की जरूरतें पूरी की जा सकें। यह एक चुनौतिपूर्ण कोशिश होगी।

दण्डकारण्य में खेती-किसानी काफी पुराने तौर-तरीकों

में की जाती है। बेहतर और विकसित कृषि पद्धतियों को सीखने की खास जरूरत अभी तक सामने नहीं आई है। लोग अपनी जरूरतों और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर होने के साथ-साथ कृषि की जो भी पद्धति वे जानते हैं उसी तक सीमित हो रहे हैं। लुटेरे शासक वर्गों ने उन्हें हमेशा 'सभ्यता' से दूर ही रखा। वही लुटेरे शासक उन पर अभूतपूर्व तबाही और बर्बरता लाद रहे हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर नई-नई जरूरतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे हालात में उनकी खेती-किसानी में बुनियादी बदलाव के बिना उनके लिए खुद का पालन-पोषण और नई जरूरतों (पीएलजीए का पोषण और युद्ध से हो रही तबाही को किसी न किसी हद तक पाटना) की पूर्ति संभव नहीं होगी। यहां पर खेती के लिए आवश्यक उर्वरा जमीन की कोई कमी नहीं है। सिंचाई की सुविधाएं बनाने के लिए तमाम आवश्यक स्रोत मौजूद हैं। अपनी श्रमशक्ति को खर्च करने को तैयार मानव संसाधन भी मौजूद हैं। उत्पादन के कार्यों में स्थानीय जनता के साथ-साथ पीएलजीए भी भाग ले ही रही है। इसलिए अब औसत उत्पादान को बढ़ाना ही हमारा काम है। वर्तमान में औसत उत्पादन बेहद कम है। 4 या 5 क्विंटल प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं है। परिणामस्वरूप जनता गरीबी में जीने को मजबूर है। उनकी आजीविका का आधा हिस्सा वनोपजों का संग्रहण है। गरीबी के कारण वे कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जिसमें प्रमुख है खून की कमी। इससे मुख्य रूप से बच्चे और महिलाएं प्रभावित हैं। औसत उम्र भी 54-55 से ज्यादा नहीं है। ये सभी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं जिन्हें जनयुद्ध के दौरान ही हल करना होगा। इन समस्याओं के हल के लिए खेती-किसानी के तौर-तरीकों में सुधार लाकर औसत उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है ताकि जनता का जीवनस्तर सुधारा जा सके। लुटेरे शासक वर्गों द्वारा थोपे गए गृहयुद्ध जैसे हालात के बीचोबीच ही जनता को इसके लिए तैयार करना होगा। विभिन्न तबकों की जनता का समर्थन जुटाए बिना इस दिशा में उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिलना मुश्किल है।

(4) दण्डकारण्य में सेना का मुकाबला करने के लिए समूचे देशवासियों का सम्पूर्ण समर्थन के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा की ओर से भाईचारा हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके बिना क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान हालात इसके लिए काफी अनुकूल हैं।

दण्डकारण्य का क्रांतिकारी आंदोलन अभी भी व्यापक जंगली इलाके तक सीमित है। पिछले तीस सालों के दौरान बाहर मैदानों में विस्तार नहीं हो पाया। वन इलाकों में भी यह आंदोलन खासकर आदिवासियों तक सीमित है। सेना का मुकाबला करने के लिए यह ताकत/जनाधार काफी नहीं होगा। सेना की ज्यादतियां और उसके अत्याचारों का दायरा तो व्यापक क्षेत्र में फैलेगा। जगदलपुर, नारायणपुर, यहां तक कि राजधानी रायपुर में भी अर्धसैनिक बलों के जुल्मों के बारे में हम सुन चुके हैं। ये तमाम लोग भारतीय राज्यसत्ता द्वारा उत्पीड़ित और प्रताड़ित ही हैं। इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में जोड़ने की जरूरत है क्योंकि वे भी क्रांति की चालक शक्तियों में शुमार हैं। चार शोषित वर्गों के बीच एकता कायम करने की जरूरत है। दूसरी ओर, देश भर में शोषित जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है। रोज-रोज बढ़ती महंगाई के कारण वे खासकर पिछले चार सालों से काफी परेशान हैं। बेरोजगारी की मार से देश के नौजवान त्रस्त हैं और महात्मा गांधी नरेगा या कोई और योजना उन्हें राहत नहीं दे पा रही है। हजारों करोड़ से लाखों करोड़ रुपए के घपले-घोटाले उजागर होने लगे हैं। ग्रामीण और शहरी जनता के लिए विस्थापन एक भारी समस्या बनी है। देश की जनता का प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ आए दिन बढ़ ही रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, आवास आदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित होकर करोड़ों जनता फटेहाल जिंदगी जी रही है। पिछले 60 सालों के अनुभव से जनता ने यह जान लिया है कि लुटेरे शासक वर्गों के पास इन समस्याओं का हल नहीं है। देश के कई हिस्सों में जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर आ रही है। पुलिस की लाठीचार्ज और गोलीबारियों की परवाह न करते हुए वह अपनी समस्याओं के हल के लिए लड़ रही है। जनता हमारी पार्टी से नेतृत्व की कितनी आस लगा रही है इसकी मिसाल हमारी पीएलजीए को तब मिली जब वह छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाकों में विस्तार के लक्ष्य से गई थी। जनता से हमें अपार प्यार मिल रहा है। वहीं पड़कीपाली की घटना हमें यह बताती है कि विस्तार का काम कितनी मुश्किलों से भरा है। शासक वर्ग हमारे विस्तार को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात की स्पष्ट घोषणा भी की। विस्तार वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर पुलिस बलों को तैनात किया गया। इसलिए उनका मुकाबला करते हुए ही हमें विस्तार करना होगा। अपनी समस्याओं को लेकर संगठित रूप से लड़ रही जनता और उसके नेतृत्व के साथ हमें एकजुट हो जाना चाहिए। अपने सांझे दुश्मन का एकजुटता से मुकाबला करना चाहिए। पार्टी को नेतृत्व के स्तर पर हुए भारी नुकसानों और दुश्मन द्वारा किए जा रहे दमनात्मक हमलों के बीचोबीच इस कार्यभार

(शेष पेज 15 में...)

दण्डकारण्य को आधार इलाके में विकसित करने के कार्यभार के अमल की दिशा में जनयुद्ध व जनसेना द्वारा हासिल प्रगति!

– कामरेड देवजी, सीएमसी सदस्य

2 दिसम्बर 2010 को हमारी पीएलजीए के दस बरस पूरे हो रहे हैं। एक दशक पहले भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की वस्तुगत व आत्मगत परिस्थितियों का जायज़ा लेकर हमारी पार्टी ने जनसेना – पीएलजीए का निर्माण करने का फैसला लिया ताकि उसे आगे बढ़ाया जा सके। यह भारतीय क्रांति के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। जनयुद्ध की प्रगति में यह एक छलांग है। उस फैसले के मुताबिक 2 दिसम्बर 2000 को हर्ष और उल्लास के माहौल में पीएलजीए की स्थापना हुई।

दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाने के स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य के साथ पीएलजीए पिछले दस बरसों के दौरान गुरिल्ला युद्ध – जनयुद्ध को संचालित करती आ रही है। 'युद्ध करते हुए ही युद्ध को सीखते हुए', युद्ध के दौरान, युद्ध को ही एक साधन बनाकर सभी संसाधनों को जुटाते हुए वह संगठित होकर आगे बढ़ रही है।

आज भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में दण्डकारण्य एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति के प्रति भारत की शोषित जनता के अंदर यह विश्वास का प्रतीक बन गया है। यह भारत के शासक वर्गों को भयभीत कर रहा है। अब जबकि दुनिया में क्रांतिकारी आंदोलन सेटबैक (अस्थाई पराजय) की स्थिति में है, भारतीय क्रांति विश्व सर्वहारा, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और जनता के लिए आशा की किरण के रूप में विकसित हो रही है। नेपाल में सीपीएन (माओवादी) की दक्षिणपंथी अवसरवादी लाइन के चलते वहां का क्रांतिकारी आंदोलन जब गतिरोध की स्थिति में फंसा हुआ हो, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। इस तरह दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में दण्डकारण्य और बिहार–झारखण्ड के आंदोलन अहम स्थान रखते हैं। इन दो जोनों के आंदोलन भारतीय क्रांति के भविष्य को प्रभावित करेंगे। इस तरह वे विश्व क्रांति पर भी प्रभाव डालेंगे। इसीलिए आज भारतीय क्रांति में दण्डकारण्य और बिहार–झारखण्ड के आंदोलन रणनीतिक महत्व रखते हैं। भारतीय क्रांति में दण्डकारण्य को रणनीतिक महत्व हासिल होने का कारण है दण्डकारण्य में विकसित हो रही जनता की राजसत्ता। दण्डकारण्य में जनता की राजसत्ता का निर्माण एरिया और डिवीजन स्तर पर हो चुका है। दिनोंदिन विकसित हो रही इस नई सत्ता के संबल के रूप में खड़ा है जनयुद्ध। और इस जनयुद्ध का संचालन कर रही है जनसेना।

1980 से 1988 तक हमारी पार्टी दण्डकारण्य के अंदर जनता की दैनंदिन और बुनियादी समस्याओं को लेकर सरकार, जमींदारों, विभिन्न किस्म के ठेकेदारों, कबीलाई मुखियाओं, कार्पोरेट संस्थाओं और सूदखोरों से लड़कर कई कामयाबियां हासिल कीं। 1980 से 1988 तक दण्डकारण्य लाल प्रतिरोधी इलाके (गुरिल्ला जोन की तैयारियों वाला चरण) के रूप में रहा। इन आठ वर्षों में किए गए वर्ग संघर्ष का परिणाम ही था 1988 में दण्डकारण्य गुरिल्ला जोन के रूप में विकसित हुआ। 1990 से दण्डकाण्य में जनता, जन संगठनों, मिलिशिया और गुरिल्ला दस्तों को राजसत्ता के सशस्त्र बलों से भिड़ना आवश्यक हो गया। राजसत्ता के सशस्त्र हमलों के जवाब में पार्टी के नेतृत्व में गुरिल्ला दस्तों ने जवाबी हमले शुरू किए। 1990 से 2000 तक दण्डकारण्य गुरिल्ला जोन के अंतर्गत आने वाले महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश (अब छत्तीसगढ़) के राज्य पुलिस बलों से सशस्त्र झड़पें होने लगीं। ऐसी स्थिति में दण्डकारण्य गुरिल्ला जोन के आंदोलन को उन्नत स्तर में कैसे विकसित किया जाए? इलाकावार राजसत्ता पर कब्जाने की लाइन के अंतर्गत दण्डकारण्य को आधार इलाके में कैसे विकसित किया जाए? दण्डकारण्य की मुक्ति की प्रक्रिया किस रास्ता पर चलेगी? जनसेना के बिना दण्डकारण्य गुरिल्ला जोन का आधार इलाके में तब्दील होना क्या संभव है? आदि कई सवाल क्रांतिकारी आंदोलन के सामने आए थे। 2001 में आयोजित पुरानी भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) की 9वीं कांग्रेस ने इन सारे सवालों का जवाब देकर सही दिशा–निर्देशन किया। दरअसल 2001 की कांग्रेस की तैयारियों के तहत 2000 के प्रारम्भ से ही इन सवालों का जवाब देते हुए हमारी पार्टी ने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया।

कांग्रेस ने स्पष्टता दी कि सभी गुरिल्ला बलों को जो

तब तक गुरिल्ला दस्तों के रूप में और इक्के–दुक्के प्लाटूनों के रूप में थे, संगठित कर उन्हें एक कमान तले संचालित करने के लिए जन मुक्ति गुरिल्ला सेना (उस समय जन गुरिल्ला सेना) की स्थापना की जाए; इस जनसेना को चाहिए कि वह युद्ध का संचालन करे ताकि दण्डकारण्य में दुश्मन की सत्ता को ध्वस्त किया जा सके; जनयुद्ध के जरिए लुटेरे वर्गों की राजसत्ता को ध्वस्त करना ही प्रधान पहलू के रूप में रहेगा/रहना चाहिए; और जिस हद तक शोषक वर्गों की सत्ता ध्वस्त की जाएगी, उस हद तक जनता की राजसत्ता की स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि लुटेरे शोषक वर्गों की सत्ता को ध्वस्त कर उसके स्थान पर जनता की राजसत्ता का निर्माण यहां–वहां न करते हुए सुनियोजित तरीके से करने की भी स्पष्टता कांग्रेस से मिली है। इसके अंतर्गत जहां जनाधार मजबूत हो और भौगोलिक धरातल अनुकूल हो, वहां पर सबसे पहले जनता की राजसत्ता का निर्माण ग्राम स्तर (या पंचायत स्तर) से लेकर एरिया व डिवीजन स्तर तक किया जाएगा। इस प्रकार कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि जिन इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से जनता की राजसत्ता का निर्माण किया जाएगा, उन्हें गुरिल्ला आधार क्षेत्र (गुरिल्ला बेस) कहा जाएगा।

तबसे लेकर पीएलजीए ने गुरिल्ला आधार क्षेत्रों के निर्माण के लक्ष्य से गुरिल्ला युद्ध को अविराम जारी रखा है। इन दस सालों से जारी गुरिल्ला युद्ध का नतीजा ही है कि आज दण्डकारण्य में कुछ डिवीजन स्तर पर और कई अन्य जगहों में एरिया स्तर पर जनता की राजसत्ता के अंगों का निर्माण हो चुका है जहां आज जनता की सत्ता चल रही है।

भारत के ठोस हालात में आधार इलाकों की स्थापना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के रूप में गुरिल्ला आधार क्षेत्रों की अवधारणा को कांग्रेस ने सामने लाया था। उसे मूर्त रूप देने के लिए जन मुक्ति सेना द्वारा संचालित जनयुद्ध का नतीजा ही है आज के डिवीजन और एरिया स्तर के गुरिल्ला आधार क्षेत्र। ये गुरिल्ला आधार क्षेत्र गुरिल्ला युद्ध के रणनीतिक कार्यभारों की पूर्ति के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। पीएलजीए के लिए पृष्ठ इलाके के रूप में यही गुरिल्ला आधार क्षेत्र काम कर रहे हैं। इन गुरिल्ला आधार क्षेत्रों के आधार पर पीएलजीए को संगठित करते हुए, उन्नत फॉर्मेशनों का गठन करते हुए, दुश्मन की राजसत्ता का और उसे संबल प्रदान कर रहे दुश्मन के सशस्त्र बलों का बड़े पैमाने पर उन्मूलन करते हुए दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील किया जा सकता है। एरिया और डिवीजन गुरिल्ला आधार क्षेत्रों को संगठित करते हुए, फैलाते हुए, उन्नत स्तर पर विकसित करने की प्रक्रिया के जरिए दण्डकारण्य को आधार इलाके में विकसित किया जा सकता है, यह बात आज सभी को व्यावहारिक रूप से अवगत हो रही है।

गुरिल्ला आधार क्षेत्रों में पीएलजीए के सशस्त्र संबल के आधार पर जनता की राजसत्ता लागू हो रही है और जन अर्थव्यवस्था व जन संस्कृति का निर्माण हो रहा है। सशस्त्र ताकत और क्रांतिकारी हिंसा के जरिए दुश्मन की सत्ता को ध्वस्त करते हुए ही हम जन राजसत्ता का निर्माण कर रहे हैं। दुश्मन के हमलों से इस सत्ता की रक्षा पीएलजीए कर रही है।

गुरिल्ला आधार क्षेत्रों के निर्माण की कुंजी के रूप में काम कर रहे जनयुद्ध और जनसेना की इन दस सालों में हुई प्रगति पर अब नजर डाली जाए।

एक दशक में जनयुद्ध में आई प्रगति

दण्डकारण्य में एक दशक के दौरान जनयुद्ध में आई प्रगति का जायज़ा लेने का मतलब यह देखना है कि यहां पर गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में तब्दील करने की दिशा में किस हद तक प्रगति हासिल हुई है। इसी नजरिए से इसकी प्रगति का आकलन करेंगे।

इस एक दशक के दौरान दण्डकारण्य में पीएलजीए द्वारा संचालित कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण के अभियानों और कार्रवाइयों में हमने 750 से ज्यादा पुलिस, अर्धसैनिक व कमाण्डो बलों का सफाया किया और 800 से ज्यादा को घायल किया। 575 हथियारों और हजारों गोलियों को जब्त कर लिया। इस दौरान जन विरोधी और भ्रष्ट राजनेताओं का दर्जनों की संख्या में उन्मूलन किया। सैकड़ों जन विरोधियों, प्रतिक्रांतिकारी मुखबिरों और सलवा जुडूम के गुण्डों को मार डाला। कुल 54 टन विस्फोटक पदार्थ और हजारों डिटोनेटर जब्त कर लिए।

संख्या के हिसाब से कमजोरी को दृष्टिगत रखते हुए हम 2001 से गुरिल्ला बलों का केन्द्रीकरण और समन्वय करते हुए हर साल कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों (टीसीओसी) के रूप में गुरिल्ला युद्ध का संचालन कर रहे हैं। इन्हें गर्मियों के दौरान और दुश्मन के हमले के हिसाब से दूसरे मौसमों भी चलाया जा रहा है। जब टीसीओसी नहीं रहेगा उस समय कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण की कार्रवाइयां चलती रहती हैं। समय–समय पर कार्यनीतिगत नारों के साथ टीसीओसी का संचालन करने से गुरिल्ला युद्ध को प्रभावी रूप से चलाने में मदद मिल रही है।

पहले टीसीओसी में पीएलजीए के तीन प्रकार के बलों (प्रधान, माध्यमिक और आधार बलों) को समन्वय के साथ उतारने में तथा हर किस्म की युद्ध कार्रवाइयों की समन्वय के साथ योजना बनाने में खामियां हुईं। इन खामियों को 2002 से हम दूर करते आए हैं। फलस्वरूप तबसे हम जनता और पीएलजीए का समन्वय करते हुए; पीएलजीए के प्रधान, माध्यमिक और आधार बलों का समन्वय करते हुए; बड़ी, मध्यम और छोटी किस्म की कार्रवाइयों का तालमेल कर अभियानों और युद्ध कार्रवाइयों को जारी रखते आ रहे हैं।

2005 के आखिर तक टीसीओसी में हम आंशिक नतीजे ही हासिल करते रहे। उन दिनों मुख्य रूप से अपने बलों और नेतृत्व में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने में रही कमजोरी के चलते यह कमी हुई। इसके साथ–साथ योजना बनाने में और अन्य कमियां भी रहीं। जनवरी 2006 से जून तक सलवा जुडूम को परास्त करने के लक्ष्य से चलाए गए अभियान के समय से हम इस कमजोरी से उबर पाए।

डीके गुरिल्ला जोन में शोषक वर्गों और उत्पीड़ित वर्गों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। इस होड़ में शोषक वर्ग अपने सशस्त्र बलों के आधार पर हर साल नई रणनीतियों और नए–नए दावपेंचों से हमला कर रहे हैं। इसे हराने के लिए अपनी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए जवाबी रणनीतियों व जवाबी कार्यनीतियों से प्रत्याक्रमण करते हुए गुरिल्ला युद्ध का संचालन कर रही है। फलस्वरूप अभी तक दुश्मन द्वारा अपनाई गई तमाम कार्यनीतियों को परास्त करते हुए वह आगे बढ़ती रही।

2001 से 2003 तक हमने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस बलों से लोहा लिया। जब हमारे जवाबी हमलों में राज्य पुलिस बल टिक नहीं पा रहे थे, 2003 से बस्तर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई। इन अर्धसैनिक बलों का भी प्रतिरोध करते हुए जब हमारा गुरिल्ला युद्ध हावी हो गया, तब केन्द्र व राज्य सरकारों ने जून 2005 से सलवा जुडूम शुरू किया। सलवा जुडूम शुरू होने के तुरंत बाद पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी खेमे की जनता, मिलिशिया और पीएलजीए ने प्रतिरोधी कार्रवाइयां कीं। 2006 में जनवरी से जून तक चलाए गए विशेष टीसीओसी और हर साल चलाए गए टीसीओसी में लगातार हमलों का सिलसिला छेड़ने के फलस्वरूप 2009 के आखिर तक सलवा जुडूम हार गया। अप्रैल 2010 तक खुद सलवा जुडूम के नेताओं ने ही अपनी पराजय को मान लिया। सलवा जुडूम के दौरान नगा और मिज़ो बटालियनों को उतारा गया था। लेकिन चूंकि उन्हें भी पीएलजीए के हाथों मुंह की खानी पड़ी, इसलिए अगस्त 2009 से कोबरा बटालियन उतार दिया गया। लेकिन सिंगनमडुगू के पास पहली ही बार पीएलजीए के जवाबी हमले में कोबरा बलों की हुई दुर्गति से उन बलों को लेकर केन्द्र व राज्य सरकारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इससे 2009 के आखिर से बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी बलों को उतार दिया गया। 2010 में अगस्त और अक्टूबर महीनों में उत्तर बस्तर और मानपुर–गढ़चिरोली सीमा पर बीएसएफ और आईटीबीपी के बलों पर भी जन मुक्ति छापामार सेना ने सफल हमले कर दिए। संख्या में कम होने के बावजूद चूकि हमारी गुरिल्ला सेना जनता की मदद और सक्रिय सहयोग से युद्ध कार्रवाइयों का संचालन कर रहा है, इसलिए स्थानीय पुलिस बलों के साथ–साथ अर्धसैनिक बलों, आईआरबी और कमाण्डो बल चाहे कोई भी बल यहां आए, पीएलजीए की प्रतिरोधी कार्रवाइयों में उनके पैर उखड़ रहे हैं। संख्या में कमतरी तथा हथियारों की कमी और निम्न श्रेणी के बावजूद पीएलजीए की कामयाबियों का राज इस बात में है कि वह जनता पर निर्भर होकर तथा जनता के सक्रिय सहयोग से युद्ध कर रही है। वह जनता से घुलमिलकर तथा जनता की अगुवाई करते हुए युद्ध लड़ रही है।

यह देखकर कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकारें दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन को कुचल नहीं पा रही हैं, 2008 से केन्द्र सरकार इसका प्रत्यक्ष नेतृत्व कर रही है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में एलआईसी और गुरिल्ला–विरोधी युद्ध की रणनीति व कार्यनीति से, सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण और काउंटर इंसर्जेन्सी विशेषज्ञों की मदद से 4–5 किस्म के अर्धसैनिक बलों, राज्यों के पुलिस बलों द्वारा आधुनिक हथियारों, एमपीवी, यूएवी और हेलिकाप्टरों के सहारे जारी हमलों का पीएलजीए हर समय – चाहे वह दिन हो या रात और बारिश में हो या गर्मी में – प्रतिरोध करती रही है, जिससे केन्द्र व राज्य सरकारें भयभीत हो गईं। इसीलिए दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन का उन्मूलन करने के इरादे से सेना और वायुसेना को तैनात करने की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं।

जून 2005 में दक्षिण व पश्चिम बस्तर में शुरू की गई कार्पेट सेक्यूरिटी 'सुरक्षा' व्यवस्था 2009 तक पूरे दण्डकारण्य में फैल गई। परिणामस्वरूप आज दण्डकारण्य के एक बड़े हिस्से में हर 3 से 5 किलोमीटर पर एक पुलिस या अर्धसैनिक कैम्प मौजूद हैं। हर कैम्प में औसतन बटालियन की संख्या में – यानी 500 से 1000

तक – बलों को रखा जा रहा है। कार्पेट सेक्यूरिटी के जरिए पीएलजीए बलों की सीमितताओं में धकेलकर, काबू कर, दमन करने की नीयत से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही कार्यनीति का हम जनयुद्ध के जरिए मुकाबला कर रहे हैं। मोदुकपाल, पामुलवाया, बंडा, आसिरगूडेम, से लेकर ऐतिहासिक मुकरम (ताड़िमेटला) ऐम्बुश तक हमारी पीएलजीए ने कार्पेट सेक्यूरिटी के बीचोबीच ही फौजी कार्रवाइयों को अंजाम देकर उसे कमजोर कर दिया। कार्पेट सेक्यूरिटी के दायरे में ही जन मिलिशिया ने बूबी ट्रैपों, हैरान–परेशान करने वाली कार्रवाइयों, एकल कार्रवाइयों, एसपीओ का सफाया आदि कार्रवाइयों को अंजाम देकर दुश्मन के खेमे को आतंकित कर दिया। हालांकि कार्पेट सेक्यूरिटी को ध्वस्त करने का महत्वपूर्ण कार्यभार आज भी पीएलजीए पर है।

पश्चिम रीजियन में गुरिल्ला युद्ध के संचालन में जारी कमजोरियों से लम्बे अरसे के बाद छुटकारा पाकर दुश्मन पर लगातार हमलों का सिलसिला चलने लगा है। 2008 के आखिर में कोरेपल्ली एम्बुश से लेकर मरकानार, मुगिनेर, टव्वेटोला, लाहेरी, पेरिमिलि, तलवाड़ा, सांवरगांव आदि ऐम्बुशों को अंजाम दिए जाने से जंगे मैदान का दायरा व्यापक हो गया।

2009 में मैनपुर व मानपुर डिवीजनों में बड़े हमलों को अंजाम देकर जंगे मैदान का और ज्यादा विस्तार किया गया जिससे दुश्मन के बलों का विकेन्द्रीकरण करने में मदद मिली।

इस साल 6 अप्रैल को मुकरम (ताड़िमेटला) के पास किया गया भारी ऐम्बुश खास महत्व का है। इस ऐम्बुश में दुश्मन के बलों की एक पूरी कम्पनी का सफाया किया गया। युद्ध में यह हमारी पीएलजीए का उन्नत स्तर का अनुभव है। इस कार्रवाई से दुश्मन इतना भयभीत हो गया कि उसने पूरे जोन में गर्मियों में अपने बलों की सुरक्षा को तवज्जो देकर अपने हमलों को लगभग रोक लिया। इस कार्रवाई के बाद 'कई मुकरम पैदा करेंगे' का नारा देश भर में प्रेरणादायक नारा बन गया। इस कार्रवाई की प्रेरणा से जुलाई में पूर्व बस्तर के कोंगेरा के पास एक और ऐम्बुश किया गया जिसमें एक पूरी प्लाटून का सफाया किया गया।

इस पूरे दशक में पीएलजीए द्वारा फौजी तौर पर हासिल प्रगति पर संक्षेप में बताया जाए तो –

★ दुश्मन के बलों को सेक्शन स्तर पर उन्मूलन करने की स्थिति से प्लाटून की संख्या में उन्मूलन करने के स्तर पर हमारी पीएलजीए की लड़ाकू क्षमता बढ़ गई है। मुकरम ऐम्बुश में दुश्मन की एक कम्पनी का सफाया किया गया।

★ कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों और कार्रवाइयों की सटीक योजनाएं तैयार करने में प्रगति हासिल हुई है। बेहतर योजनाओं के आधार पर सी–4 में (कमान, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और को–आर्डिनेशन) विकास आया है।

★ दुश्मन ही हथियार जुटाने का अहम स्रोत है', इस उसूल को व्यवहार में लागू करते हुए सैकड़ों हथियार, हजारों कारतूस और कई टन विस्फोटक पदार्थ दुश्मन से छीनकर पीएलजीए की शस्त्रास्त्र सम्पत्ति को बढ़ाया और बेहतर बनाया गया।

★ दुश्मन द्वारा अपनाई जा रही गुरिल्ला विरोधी युद्ध की कार्यनीति का हम जनयुद्ध की कार्यनीति से मुकाबला कर रहे हैं। कार्पेट सेक्यूरिटी के बीचोबीच ही गुरिल्ला युद्ध के संचालन में हम अनुभव हासिल कर रहे हैं।

★ दण्डकारण्य के आंदोलन के उन्मूलन के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अब तक लागू की गई तमाम दुष्ट नीतियों (सलवा जुडूम समेत) को नाकाम किया गया।

★ केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की कार्यनीति में प्रगति हासिल करते हुए युद्ध कार्रवाइयों में हम बटालियन के स्तर पर बलों को इकट्ठे कर पा रहे हैं। कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों (टीसीओसी) को हम इस तरह चला रहे हैं कि जब केन्द्रीकृत बल बड़ी व अहम कार्रवाइयों का संचालन करते हैं तब विकेन्द्रीकृत बल छोटी व मध्यम किस्म की कार्रवाइयों को अंजाम देती हैं।

★ जब पीएलजीए का गठन हुआ था तब हिट एण्ड रन की पद्धति में युद्ध कार्रवाइयां हुआ करती थीं, वहीं आज पीएलजीए की लड़ाकू क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि वह दुश्मन की घेराबंदी कर सी.क्यू.बी. की पद्धति से लड़ते हुए दुश्मन का उन्मूलन करने लगी है।

★ पीएलजीए के तीनों बलों का समन्वय कर छोटी, मध्यम व बड़ी किस्म की कार्रवाइयों को अंजाम देने में पीएलजीए का अनुभव बढ़ा है। जनता पर निर्भर होकर युद्ध कार्रवाइयों का संचालन करने में प्रगति हासिल हुई है।

★ जन कार्य व फौजी कार्य को तालमेल के साथ चलाने में विकास आया है।

इस एक दशक में पीएलजीए ने जनयुद्ध के संचालन

में राजनीतिक, फौजी, सांगठनिक और तकनीकी रूप से जो उन्नति हासिल की उसके आधार पर आज डीके में गुरिल्ला युद्ध उन्नत स्तर पर चल रहा है। इसमें कुछ कार्रवाइयां ऐसी हो रही हैं जिसमें चलायमान युद्ध के प्राथमिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

हालांकि इस एक दशक में हमने जो प्रगति हासिल की वह कार्यनीतिक ही है। यानी हमारा जनयुद्ध आज भी रणनीतिक आत्मरक्षा की स्थिति में है। हमारा दुश्मन रणनीतिक आक्रमण की स्थिति में है। हम रणनीतिक दृष्टि से तभी प्रगति हासिल कर सकते हैं जब हम गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित कर दण्डकारण्य के युद्ध के मोर्चे में हमारी और दुश्मन की ताकत में संतुलन को उलट देते हैं। इसलिए हमारी इस प्रगति का ज्यादा करके या कम करके आकलन न करते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचते हुए दृढ़ संकल्प और साहस के साथ लड़ना चाहिए ताकि हमारे उन्नत कार्यभारों की पूर्ति की जा सके।

पिछले दशक के दौरान जनसेना द्वारा हासिल प्रगति

इस दशक भर के समय में पीएलजीए जोकि एक गुरिल्ला सेना है, का एक नियमित सेना के रूप में विकास किस हद तक हुआ है, इसका जायजा लेना ही जनसेना की प्रगति में केन्द्र बिंदु होगा।

2 दिसम्बर 2000 को डीके में जब पीएलजीए की स्थापना हुई, तब दो प्लाटून और कुछ एलजीएस (उस समय वे एसजीएस कहलाते थे) मौजूद थे। दिसम्बर 2000 में सम्पन्न दण्डकारण्य स्पेशल जोन के तीसरे अधिवेशन के बाद नई एसजेडसी का चुनाव हुआ जिसकी जनवरी 2001 में विस्तृत बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दो प्लाटूनों की जगह पर कुल पांच प्लाटूनों का निर्माण किया जाए और कुछ नए एलजीएस का गठन किया जाए। इनका मार्गदर्शन करने के लिए स्टेट मिलिटरी कमिशन का निर्माण किया गया जिसमें तीन सदस्य थे। मई 2001 में उत्तर और दक्षिण सब–जोनल कमानों का गठन किया गया।

मार्च 2003 में आयोजित डीके प्लीनम में आंदोलन की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद संगठित हो रही पार्टी व जन राजसत्ता तथा बढ़ते सैन्य संगठन को देखते हुए सब–जोनल कमान के साथ–साथ डिवीजनल और एरिया कमानों का भी निर्माण करने का फैसला लिया गया। इसके अंतर्गत अप्रैल 2003 तक माड़ डिवीजनल कमान का गठन किया गया। गढ़चिरोली में नवम्बर 2004 में, उत्तर बस्तर में 2004 के आखिर में, दक्षिण बस्तर में अगस्त 2005 में और पश्चिम बस्तर में नवम्बर 2005 में डिवीजनल कमानों का गठन किया गया।

जहां तक एरिया कमानों की बात है, सबसे पहले दक्षिण बस्तर डिवीजन में 2004 के आखिर में इसका निर्माण हुआ। 2005 की शुरूआत में माड़ में भी एरिया कमान का गठन हुआ। उसके बाद उत्तर बस्तर और गढ़चिरोली डिवीजनों में इसका निर्माण हुआ। 2005 के आखिर में पश्चिम बस्तर डिवीजन में एरिया कमान निर्मित हो गई।

एरिया और पंचायत के स्तर पर मिलिशिया कमानों के निर्माण की प्रक्रिया 2006 से प्रारम्भ हो गई ताकि मिलिशिया को बेहतर ढंग से युद्ध कार्रवाइयों में शामिल किया जा सके।

आज हमारी पीएलजीए को स्थानीय स्तर से मार्गदर्शन देने के लिए और उसके तीनों बलों का तालमेल करने के लिए पंचायत और एरिया स्तर पर मिलिशिया कमान से शुरू कर रीजनल स्तर (इसके पहले सब–जोनल स्तर पर मौजूद) तक कमानों का ढांचा मौजूद है। वहीं इन सभी का जोन स्तर पर नेतृत्व करने के लिए स्पेशल जोनल मिलिटरी कमिशन (एसएमसी) मौजूद है।

आइए, इस पर नजर डाली जाए कि इस एक दशक में पीएलजीए का सांगठनिक विकास कैसे रहा –

- ★ दो प्लाटूनों की संख्या से प्लाटूनों का विस्तार कर कम्पनियों का निर्माण कर उन्हें संगठित करते हुए गुरिल्ला बटालियन का निर्माण किया गया।
- ★ प्रधान, माध्यमिक और आधार बलों को संख्या के हिसाब से बढ़ाया गया। मिलिशिया का निर्माण भी पहले से बढ़ गया।
- ★ एसएमसी, सब–जोनल कमान से डिवीजनल कमान, एरिया कमान, मिलिशिया कमान (पंचायत/एरिया) का गठन किया गया। सीमांत के जोनों से सरहदी कमानों का गठन कर दो–दो जोनों के बलों के बीच तालमेल बैठाने में अनुभव हासिल किया जा रहा है।
- ★ डीके के बलों द्वारा दूसरे जोनों के बलों के साथ मिलकर अस्थाई रूप से ज्वाइंट कमान बनाकर ज्वाइंट आपरेशन्स के संचालन में अनुभव हासिल किया जा रहा है।
- ★ बुनियादी तौर पर मिलिटरी इंटेलिजेन्स का निर्माण कर काउंटर इंटेलिजेन्स के जरिए दुश्मन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में कुछ अनुभव मिला है।

★ पहले से मौजूद सहायक विभागों को संगठित करते हुए विस्तारित किया गया। कुछ अन्य सहायक विभागों का बुनियादी स्तर पर गठन किया जा रहा है।

जनसेना के निर्माण की तुलना हम पिरमिड से करते हैं। व्यापक जनाधार पर निर्भर होकर उसका विकास होना चाहिए। अगर वह सिर्फ आड़े में ही विकसित होकर सीधे में विकसित नहीं होगी या सिर्फ सीधे में विकसित होकर आड़े में विकसित नहीं होगी (आड़े का अर्थ है व्यापक जनाधार का होना) तो वह कमजोर सेना ही मानी जाएगी। या फिर सेना के निर्माण में दक्षिणपंथी या वामपंथी अवसरवाद की निशानी होगी। इसलिए चीन और वियत्नाम की क्रांतियों के अनुभव से यह नियम उभरकर आया है कि प्रधान, माध्यमिक और आधार बलों के निर्माण में संतुलन रहना चाहिए तथा प्रधान बलों को धुरी बनाकर माध्यमिक और आधार बलों का विस्तार करना चाहिए। इस नियम के परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकते हैं कि अब तक पीएलजीए के निर्माण में, संगठितीकरण में, विस्तार में और उन्नत स्तर में विकसित करने में हम वामपंथी या दक्षिणपंथी गलती का शिकार हुए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते आ रहे हैं।

अभी तक हमारी समझदारी यह रही कि गुरिल्ला सेना में प्राथमिक यूनिट दस्ता (सेक्शन) और उन्नत यूनिट (फार्मेशन) कम्पनी होगी। बटालियन इसमें अत्युन्नत फार्मेशन के रूप में होगी। नियमित सेना में प्राथमिक यूनिट के रूप में कम्पनी और फील्ड आर्मी अत्युन्नत फार्मेशन के रूप में होगी, ऐसी हमारी समझदारी रही। लेकिन चीन और वियत्नाम के अनुभवों के अलावा बुर्जुवाई सेनाओं के ढांचे को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि नियमित सेनाओं में प्राथमिक यूनिट के रूप में बटालियन ही होती है।

इस स्पष्टता के नजरिए से देखा जाए तो पीएलजीए (गुरिल्ला सेना) को पीएलए (नियमित सेना) के रूप में विकसित करने की दिशा में हम अभी–अभी बुनियादी स्तर पर कदम रख रहे हैं। हम कम्पनियों का व्यापक निर्माण करते हुए गुरिल्ला बटालियन का निर्माण कर पाए हैं। अगर हम और ज्यादा कम्पनियों का निर्माण कर, उन्हें व्यापक बनाकर कुछ और बटालियनों का निर्माण करते हैं तो हम डीके में पीएलजीए को पीएलए के रूप में प्राथमिक स्तर पर विकसित करने में सक्षम हो जाएंगे। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए।

दण्डकारण्य को आधार इलाके में विकसित करने का कार्यभार पूरा करने में, दण्डकारण्य में जनयुद्ध को जारी रखने में तथा जनसेना का निर्माण कर उसे विकसित करने में हमने प्रगति हासिल की। हालांकि यह अपेक्षाकृत ही है। युद्ध की मौजूदा जरूरतों और स्तर के हिसाब से हमें उच्च स्तर पर प्रगति हासिल करनी चाहिए। उसके लिए आज की हमारी प्रगति एक आधारशिला का काम करेगी।

गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में तथा पीएलजीए को पीएलए में विकसित करना है तो हमें पीएलजीए के अंदर चिन्हित की गई विफलताओं, खामियों और कमजोरियों को सुधार लेना चाहिए। उनसे निजात पा लेना चाहिए।

आज आपरेशन ग्रीन हंट के तहत जारी दुश्मन के हमलों से जनता का बचाव करते हुए इस अभियान को हरा देना चाहिए। साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों द्वारा जारी शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। इस तरह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध को जारी रखते हुए ही पीएलजीए में भर्ती बढ़ा लेनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में हो रही भर्ती को हजारों की संख्या में बढ़ा लेना चाहिए। बटालियनों को व्यापक करते हुए ब्रिगेडों और डिवीजनों का निर्माण करना चाहिए। सहायक विभागों को विकसित कर लेना चाहिए ताकि युद्ध की जरूरतों की पूर्ति हो सके। हमारे प्रशिक्षण में विकास लाना चाहिए ताकि भारत सरकार की सेना व वायुसेना के हमलों का मुकाबला किया जा सके। पीएलजीए की लड़ाकू क्षमता में विकास होना चाहिए ताकि एक–एक युद्ध कार्रवाई में दुश्मन के बलों की एक–एक कम्पनी का सफाया किया जा सके। हमारे शस्त्रास्त्रों में बेहतरी आनी चाहिए ताकि दुश्मन की कार्पेट सेक्यूरिटी को ध्वस्त किया जा सके। कमानों और कमिशनों को चाहिए कि वे अपनी क्षमता बढ़ा लें। आज पीएलजीए में अनुशासन का पालन करने में हो रही खामियों को सुधारकर फौलादी अनुशासन लागू करना चाहिए। निरंतर उत्पन्न होने वाले गैर–सर्वहारा रुझानों को राजनीतिक शिक्षा से सुधारते हुए तथा जरूरी संदर्भों में भूलसुधार अभियानों को संचालित करना चाहिए। युद्ध के बढ़ते स्तर के मुताबिक उन्नत स्तर की तकनीक को बढ़ा लेना चाहिए। व्यापक इलाकों को गुरिल्ला क्षेत्रों में बदल देना चाहिए। इन कार्यभारों को पूरा करने के क्रम में ही या पूरा करने पर ही गुरिल्ला युद्ध चलायमान युद्ध में तथा पीएलजीए पीएलए में तब्दील हो जाएंगे। तभी हम दण्डकारण्य को आधार इलाके में विकसित कर पाएंगे। इस महान कार्यभार को पूरा करने के लिए, आइए, हम सब आगे बढ़ें! अंतिम जीत हमारी ही है!

साक्षात्कार

दण्डकारण्य की जनता एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रही है...

– कामरेड सुधाकर
प्रभारी, डीकेएसएमसी, भाकपा (माओवादी)

(पीएलजीए की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर दण्डकारण्य में पीएलजीए की उपलब्धियों और मौजूदा कार्यभारों के बारे में 'प्रभात' ने डीके एसएमसी के प्रभारी कॉमरेड सुधाकर से बातचीत की। उम्मीद है कि इससे पाठकों को दण्डकारण्य में जारी जनयुद्ध के विभिन्न पहलुओं से रू-ब-रू होने में मदद मिलेगी। – सम्पादक)

***प्रभात** – कॉमरेड सुधाकर, पीएलजीए की दसवीं वर्षगांठ के मौके पर 'प्रभात' आपका और समूची पीएलजीए के कतारों, जन मिलिशिया और जनता का क्रांतिकारी अभिनंदन करती है! सबसे पहले, इस मौके पर आप हमें पीएलजीए की स्थापना के बारे में और उसके निर्देशित कार्यभारों के बारे में बताइएगा।*

कॉमरेड सुधाकर – धन्यवाद। 2 दिसम्बर 2000 को हमारे प्यारे नेता व शहीद कॉमरेड्स श्याम, महेश और मुरली की पहली बरसी के दिन, तत्कालीन भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] की अगुवाई में पीजीए (जन गुरिल्ला सेना) की स्थापना हुई। यह भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद 22 अप्रैल 2003 को तत्कालीन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआई) के नेतृत्व में पीएलजीए (जन मुक्ति गुरिल्ला सेना) की स्थापना हुई। बाद में, 21 सितम्बर 2004 को जब हमारी दोनों पार्टियों के ऐतिहासिक विलय से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना हुई। उसके साथ ही हमारी दो जन सेनाओं की भी एकता हुई और इस तरह एकीकृत जन मुक्ति गुरिल्ला सेना का आविर्भाव हुआ जिसके स्थापना-दिवस के रूप में 2 दिसम्बर 2000 को ही स्वीकारा गया।

भारत में नई जनवादी क्रांति को सफल बनाकर समाजवाद के रास्ते से साम्यवाद के मुकाम तक पहुंचना हमारी पीएलजीए का राजनीतिक मकसद है। इसी लक्ष्य से यह काम कर रही है। 'सशस्त्र ताकत के जरिए मसले को हल करना और युद्ध के जरिए सत्ता पर दखल करना' क्रांति के इस बुनियादी उसूल की रोशनी में पीएलजीए काम कर रही है। इसी कार्यभार को पूरा करने के लिए यह आगे बढ़ रही है। यह जनता की सेना है और जनाधार ही इसकी बुनियादी ताकत है। आबादी का 95 फीसदी हिस्सा रखने वाले शोषित-उत्पीड़ित वर्गों की जनता और उनके कल्याण के लिए यह सेना समर्पित है और उन्हीं वर्गों की जनता से वह निरंतरता से नए लोगों को भर्ती कर लेती है। कॉमरेड माओ के इस कथन को कि 'यदि जनता के पास एक जन-सेना नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है' साकार बनाते हुए यह सेना काम करती है।

***प्रभात** – पीएलजीए में मौजूद तीन प्रकार के बलों, उसकी कमानों और जनयुद्ध में इन विभिन्न बलों के कार्यभारों के बारे में हमें बताइए।*

कॉमरेड सुधाकर – पीएलजीए में तीन प्रकार के बल रहते हैं – प्रधान, माध्यमिक और आधार बल। ये तीनों बल जनता की मुक्ति के लिए लड़ते हैं। इसमें प्रधान बल, माध्यमिक बलों में से लड़ाकू बल और आधार बल अलग-अलग स्तर पर युद्ध कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। मुख्य रूप से प्रधान बल निरंतर युद्ध कार्रवाइयों के जरिए दुश्मन की शक्ति का नाश करते हुए उससे हथियार छीन लेते हुए जनसेना को मजबूत बनाने पर खुद को केन्द्रित करता है। 'दुश्मन का शस्त्रागार ही हमारा शस्त्रागार' इस नीति के तहत दुश्मन से निरंतर हथियार छीन लेते हुए अपनी शस्त्रास्त्र सम्पत्ति को समृद्ध बनाने की कोशिश करता रहता है। अपने स्वभाव के अनुसार प्रधान बल देश के किसी भी हिस्से में जाकर लड़ाई में भाग लेता है। माध्यमिक बल का मुख्य रूप से यह कर्तव्य होता है कि जन कार्य में लगे हुए कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देते हुए स्थानीय स्तर पर युद्ध कार्रवाइयों में भाग ले। आधार बल जोकि जन मिलिशिया भी कहलाता है, मुख्य रूप से जनता द्वारा क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए हासिल उपलब्धियों को बचाने के लिए गांव स्तर पर लड़ता है। जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले स्थानीय दुश्मनों से लेकर सरकारी सशस्त्र बलों तक का मुकाबला करता है, दण्डित करता है। प्रधान और माध्यमिक बलों द्वारा दुश्मन के खिलाफ की जाने वाली युद्ध कार्रवाइयों में विभिन्न प्रकार का सहयोग देता है। युद्ध कार्रवाइयों में खुद भी भाग लेता है। जब दुश्मन स्थानीय स्तर पर गुण्डा गिरोहों को तैयार कर जनता के खिलाफ दमन व आतंक का अभियान शुरू करता है या फिर अपने सशस्त्र बलों के जरिए दमन अभियान शुरू

करता है तब आधार बल जनता को गोलबंद कर नेतृत्व प्रदान करता है ताकि ऐसे अभियानों को धूल चटा दी जा सके। जनता की आत्मरक्षा के सभी उपाय वह अपनाता है।

उपरोक्त कार्यभारों के अलावा, पीएलजीए के तीनों बल राजनीतिक प्रचार, जनता का संगठितीकरण के अलावा और जहां मौका हो जनता के साथ मिलकर उत्पादन के कार्यों में भाग लेते हैं।

उपरोक्त सभी कार्यभारों को पूरा करने में सभी बलों का तालमेल करने, उन्हें आवश्यक राजनीतिक व फौजी प्रशिक्षण देने तथा कार्रवाइयों के दौरान नेतृत्व देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कमानों का गठन हुआ है। फिलहाल दण्डकारण्य में प्रधान और माध्यमिक बलों के तालमेल के लिए रीजनल कमानों (जो पहले सब-जोनल कमान के रूप में थे) से लेकर एरिया कमान तक काम कर रहे हैं। जन मिलिशिया का नेतृत्व करने के लिए एरिया और पंचायत स्तर पर कमानें मौजूद हैं। इस तरह पीएलजीए के सभी बलों को हर स्तर पर राजनीतिक, सांगठनिक व सैनिक रूप से संगठित किया जा चुका है।

प्रभात - अपने निर्देशित कार्यभारों को पूरा करने में पीएलजीए को पिछले दस सालों में कितनी कामयाबी मिली है?

कॉमरेड सुधाकर - पीएलजीए के आज दस बरस पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर अगर हम उसके निर्देशित कार्यभारों की रोशनी में उसकी कामयाबियों का जायज़ा लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि इन दस सालों में उसने अच्छी-खासी प्रगति हासिल की है। क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करने की मंशा से, खासकर ग्राम स्तर से उच्च स्तर तक विकसित हो रही जनता की राज्यसत्ता के अंगों का सफाया करने के लिए दुश्मन द्वारा कई सैनिक अभियान और फासीवादी दमनचक्र चलाए जाने के बावजूद पीएलजीए डटी रही। उसका मुकाबला करती रही। हत्या, अत्याचार, जनता की सम्पत्तियों की तबाही, लूटपाट आदि सरकारी सशस्त्र बलों की तमाम करतूतों के खिलाफ संघर्ष करती रही। शत्रु की साजिशों को नाकाम करते हुए पीएलजीए द्वारा किए गए प्रतिरोधी संघर्ष के फलस्वरूप न सिर्फ जनताना सरकार का सफाया करने की उसकी मंशा पर पानी फिर गया, बल्कि उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। पीएलजीए और जनता के प्रतिरोधी संघर्ष में आई तेजी के कारण दुश्मन की आक्रामकता पर कुछ हद तक अंकुश लग गया। साथ ही, जनताना सरकार का विस्तार हुआ और उसे मजबूती भी मिल गई। यह पीएलजीए की एक बड़ी कामयाबी है जो उसने जनता के सहयोग व सक्रिय भागीदारी से और जनता के पक्ष में हासिल किया।

प्रभात - दण्डकारण्य में जारी जनयुद्ध में पीएलजीए के गठन के बाद पिछले दस सालों में हासिल प्रगति के बारे में हमें बताइए।

कॉमरेड सुधाकर - पीएलजीए की स्थापना के बाद दण्डकारण्य में जारी जनयुद्ध में जबर्दस्त बदलाव आया है। फौजी कार्रवाइयों में विकास हुआ है। एक सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाइयों को अभियानों के रूप में चलाना, उनकी समीक्षा करना, समीक्षाओं की रोशनी में फिर से कार्रवाइयों में उतरना और इस तरह कार्रवाइयों के दौरान होने वाली गलतियों और कमजोरियों से खुद को उबारना - इसे एक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया। इसके लिए आवश्यक शिक्षा और प्रेरणा देकर बलों को फिर से कार्रवाइयों में उतारा जाता रहा। इससे कार्रवाइयों के संचालन में बेहतरी और जीत की निश्चितता बढ़ गई। दुश्मन की कार्यनीति का गहराई से अध्ययन कर, उसके खिलाफ जवाबी कार्यनीति तय करके युद्ध कार्रवाइयों का संचालन करके अंततः उसकी योजना को विफल करना, ऐसा एक सिलसिले के तहत प्रगति हासिल की गई।

दस साल पहले पुलिस वालों पर हमले खास तौर पर उसी समय किए जाते थे जब वे वाहनों में बैठकर जा रहे होते थे। मुख्य रूप से बारूदी सुरंगों के जरिए ही हमले किए जाते थे। पुलिस थानों और कैम्पों पर हमले करने में, कस्बों और पुलिस थानों के इर्द-गिर्द एकल कार्रवाइयों को अंजाम देने में सीमिताएं रहा करती थीं। लेकिन इन दस सालों में कई मायनों में जनयुद्ध का विकास हुआ है। कई सीमिताओं से पार पाया गया है। बड़े वाहनों में, मोटारसायकलों और पैदल बड़ी संख्या में आने वाले दुश्मन से भी लोहा लेते हुए, अतिरिक्त बल आने से भी उन्हें रोकते हुए कार्पेट सेक्यूरिटी के बीचोबीच ही दर्जनों की संख्या में शत्रु-बलों का सफाया करने और उनसे हथियार छीन लेने में कई कामयाबियां हासिल की गईं। इस दृष्टि से देखा जाए तो जनयुद्ध के संचालन में यह उल्लेखनीय प्रगति है।

पार्टी की एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस द्वारा निर्देशित कार्यभारों को - पीएलजीए (जन मुक्ति गुरिल्ला सेना) को पीएलए (जन मुक्ति सेना) में तथा गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित करने के कार्यभार को पूरा करने की दिशा में हम कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आज दण्डकारण्य में गुरिल्ला युद्ध उच्च स्तर पर पहुंचा है। यह सब दुश्मन द्वारा जनता के खिलाफ जारी फासीवादी हत्याकाण्डों के बीचोबीच ही, जनता के सक्रिय योगदान के जरिए तथा कई शहादतों की बदौलत हासिल हो पाया।

प्रभात - पीएलजीए के गठन के बाद दण्डकारण्य में किए गए कुछ महत्वपूर्ण हमलों और उनकी

विशिष्टताओं के बारे में बताइए।

कॉमरेड सुधाकर – इन दस सालों में दण्डकारण्य में किए गए मुख्य हमलों में – गीदम थाने पर हमला, एनएमडीसी के बारूद गोदाम पर हमला, मुरकीनार कैम्प पर हमला, पदेड़ा एम्बुश, झाराघाटी ऐम्बुश, कुदुर एम्बुश, रानीबोदली रेड, उरपलमेट्टा एम्बुश, ताड़िमेटला–1, तोंगूडा, भट्टिगुड़ा एम्बुश, मोदुगपाल एम्बुश, मदनवेड़ा एरिया एम्बुश, पालचेलमा, मरकानार, टव्वेटोला, लाहेरी ऐम्बुश, मांदगिरी एम्बुश, ऐतिहासिक ताड़िमेटला एम्बुश, कोंगेरा एम्बुश आदि महत्वपूर्ण हैं।

गीदम थाने पर रेड की कार्रवाई सितम्बर 2003 में की गई थी। गीदम कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग–46 पर स्थित है जहां से जिला मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय काफी करीब था। इसीलिए दुश्मन लापरवाह था और इसी का फायदा उठाकर हमने इस रेड कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इससे दुश्मन की इस धारणा को चकनाचूर कर दिया था कि 'नक्सलवादी शहरी इलाकों में हमला नहीं कर सकते और वे वहां निश्चिंत व सुरक्षित रह सकेंगे'। पीएलजीए के अंदर भी यह विश्वास बढ़ा कि अगर दुश्मन की कमजोरियों का ठीकठाक पता होने से हम कहीं भी जीत हासिल कर सकते हैं। रेड की कार्रवाइयों को लेकर पीएलजीए बलों के अंदर रही गलतफहमियों को भी इस कार्रवाई के जरिए दूर किया गया। इसके बाद इस तरह की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ।

दुश्मन ने 2005 में फासीवादी सलवा जुडूम शुरू कर सब तरफ से घेराबंदी कर पीएलजीए के गुरिल्लों और जनता का सफाया करने की कोशश की। बड़े पैमाने पर नरसंहार करते हुए जनता को 'राहत' शिविरों में घसीटा गया जो दरअसल यातना शिविर थे। हत्या, अत्याचार, लूटपाट और बलात्कार रोजमर्रा की बात बन गए। जनता में आतंक का तांडव मचाकर क्रांतिकारी आंदोलन से अलग करने की साजिशें रची गईं। दूसरी ओर, यह दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर चलाया गया था कि जनता नक्सलवादियों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। दुश्मन के इस वाहियात प्रचार को ध्वस्त करते हुए पीएलजीए ने बैलाडीला में एनएमडीसी के बारूद डिपो पर धावा बोल दिया। इसमें खास बात यह थी कि पीएलजीए की अगुवाई में एक हजार जनता ने हमले में भाग लिया। उस गोदाम की सुरक्षा में मौजूद 8 अर्धसैनिकों का सफाया कर उनके हथियारों के साथ–साथ करीब 20 टन बारूद जब्त कर लिया गया। इसे जनता ने अपने कंधों पर ढोया था। इस हमले ने जनता की लड़ाकू शक्ति का एक नमूना पेश किया।

खासकर सलवा जुडूम के समय से दुश्मन ने कार्पेट सेक्यूरिटी को एक रणनीति के बतौर लागू करना शुरू किया। इसके तहत हर 5–7 किलोमीटर की दूरी में एक थाना/कैम्प बिठाया जा रहा है जो एक बड़े हिस्से में पूरा भी हो गया। लेकिन जनता की ताकत के सामने लोहे का किला भी नहीं टिक सकता, इस बात को साबित करते हुए मुरकीनार रेड और रानीबोदली शार्ट सरप्राइज एटैक आदि हमले किए गए।

झाराघाटी ऐम्बुश की भी अपनी विशेषता है। इसमें बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर मोटरसायकलों और पैदल आ रहे शत्रु–बलों में से एक टुकड़ी को चुनकर उसका सफाया कर हथियार छीन लिए गए और बाकी बलों का मुकाबला करते हुए पीछे धकेल दिया गया। भारी संख्या में आकर हमारे एम्बुश को नाकाम करने की दुश्मन की योजना विफल कर दी गई। झाराघाटी के बाद इस तरह के कई हमले और भी उच्च स्तर पर चलाए गए जिसका उदाहरण है उरपलमेट्टा ऐम्बुश। जब दुश्मन के बल इलाके के अंदर घुसकर गांवों को जला रहे थे, ठीक उसी समय हमारी पीएलजीए ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिए और चौबीस शत्रु–बलों का सफाया कर दिया। कुछ इसी तरह का रहा मदनवेड़ा ऐम्बुश जो एक एरिया ऐम्बुश था। दुश्मन के कई कैम्पों के बीचोबीच उन्हें जहां–तहां रोकते हुए इसे अंजाम दिया गया। दुश्मन के बल मोटरसायकलों, माइनप्रूफ वाहनों पर और पैदल आ रहे थे जिन्हें रोककर और घेरकर एसपी समेत 29 जवानों को पीएलजीए ने मार डाला। इस एरिया ऐम्बुश ने दण्डकारण्य जनयुद्ध के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया।

हाल ही में संपन्न ऐतिहसिक मुकरम (ताड़िमेट्ला) ऐम्बुश जिसमें एक पूरी कम्पनी का सफाया किया गया। यह न सिर्फ दण्डकारण्य में, बल्कि भारत के क्रांतिकारी जनयुद्ध के इतिहास में ही एक अभूतपूर्व घटना थी। इसे उच्च स्तर के गुरिल्ला युद्ध की कार्रवाई कह सकते हैं जिसमें चलायमान युद्ध के प्राथमिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पीएलजीए को पीएलए में तथा गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में बदलने के कार्यभार की पृष्ठभूमि में ऐसी कार्रवाइयों से चलायमान युद्ध की ओर तेजी से कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रभात – जन मिलिशिया द्वारा की जा रही कार्रवाइयों का दण्डकारण्य में जारी जनयुद्ध में खास महत्व रहा है। क्या आप इस विकासक्रम के बारे में बताएंगे?

कॉमरेड सुधाकर – दण्डकारण्य में जारी जनयुद्ध में जन मिलिशिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनता को जन प्रतिरोध के लिए तैयार कर उसका नेतृत्व करने में,

जनताना सरकारों की आंख की पुतली के समान रक्षा करने में, विभिन्न स्तर पर जनता के दुश्मनों को नियंत्रित करने में, जन दुश्मनों को जनताना सरकार द्वारा तय सजाएं देने में तथा दुश्मन के दलालों का पता लगाकर उनका सफाया करने में जन मिलिशिया की सराहनीय भूमिका रही है। जन मिलिशिया न सिर्फ प्रधान बलों और माध्यमिक बलों के साथ मिलकर युद्ध कार्रवाइयों में भाग ले रही है, बल्कि स्वतंत्र रूप से भी युद्ध कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। खासकर दुश्मन को हैरान-परेशान करने की मंशा से विभिन्न किस्म की कई कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। परम्परागत व देशी किस्म के हथियारों से लैस जन मिलिशिया के दस्तों ने दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाकर, ऐसी जगहों पर जहां दुश्मन को जरा भी अंदाजा न हो, हमले कर दर्जनों आधुनिक हथियार छीन लिए जिससे पीएलजीए को मजबूत करने में काफी मदद मिली। पहली बार 2 दिसम्बर 2001 को, पीएलजीए की पहली वर्षगांठ के दिन, दक्षिण बस्तर के बासागुड़ा में जन मिलिशिया की एक छोटी सी टुकड़ी ने एक सशस्त्र पुलिस जवान पर हमला कर उसे घायल कर उसकी एसएलआर छीन ली थी। यह अपनी तरह की पहली कार्रवाई थी जिसने पूरे दण्डकारण्य भर में जन मिलिशिया को एक नया जोश और प्रेरणा दी। और इसके बाद सभी डिवीजनों में इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। हाट बाजारों और अपने कैम्पों के इर्द-गिर्द भी दुश्मन को अब निश्चिंत होकर रहने की स्थिति नहीं रह गई। अंधेरा होने से पहले ही अपने कैम्पों के गेट बंद कर खुद को कैम्पों में कैद करने पर मजबूर होना पड़ा। कुल्हाड़ी, तीन-धनुष जैसे औजारों और परम्परागत हथियारों से लैस किसी किसान को देखने से भी डर से कांपने की स्थिति आ गई। आखिर में दुश्मन को किसानों के परम्परागत औजारों पर भी प्रतिबंध लगाने का बेतुका फैसला लेना पड़ा। लेकिन इन प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए जनता और जन मिलिशिया सृजनशीलता के साथ नए-नए तरीकों में हमले कर ही रही हैं। सलवा जुडूम, ग्रीन हंट जैसे प्रति-क्रांतिकारी दमन अभियान भी जन मिलिशिया की बढ़ती चेतना को कुंद नहीं कर पा रहे हैं। जनता और जन मिलिशिया नए-नए दावपेंचों के साथ दुश्मन के हमलों का प्रतिरोध कर ही रही हैं।

जन मिलिशिया के हाथों में एक और कारगर हथियार है बूबी ट्रैप। इन बूबी ट्रैपों ने दुश्मन के नाक में दम कर रखा है। कब और कहां 'प्रेशर बम' फटेगा, कहां कदम रखने पर गड्ढे में गिरकर बांस के नुकीले कांटों या लोहे की खीलों से घायल होना पड़ेगा, संघर्ष वाले इलाके में कदम रखने और दमन अभियान चलाने से पुलिस और अर्धसैनिक बल इस डर से कांपने लगे हैं। इसे कार्यनीतिक रूप से पीएलजीए की कामयाबी के रूप में बताया जा सकता है।

दुश्मन करोड़ों रुपए खर्च कर कई साल काम करके सड़कों, पुलों और पक्का भवनों का जो निर्माण कर रहा है, जिन्हें पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा जनता के दमन में इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें जनता और जन मिलिशिया एक दिन में या एक पूरी रात में ध्वस्त कर रही हैं। दण्डकारण्य की सम्पदाओं का दोहन करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपतियों द्वारा निर्मित पाइप लाइन, रेलवे ट्रैक और अन्य साधनों को जनता तबाह कर रही है। ऐसी सभी कार्रवाइयों का नेतृत्व जन मिलिशिया कर रही है। ये कार्रवाइयां जनयुद्ध को आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो रही हैं। पुलिस, अर्धसैनिक व विशेष कमाण्डो बलों की आक्रामकता पर अंकुश लगाने में उपयोगी साबित हो रही हैं। जन मिलिशिया की कार्रवाइयों से खौफ खाकर दुश्मन कुछ मार्गों को छोड़कर हवाई रास्ते से हेलिकॉप्टरों के जरिए ही बलों की आवाजाही और सप्लाई भेजने को मजबूर है। जनता में छिपी असीम सृजनशीलता को अगर पूरी तरह बाहर ला सकेंगे तो जन मिलिशिया और भी कई अद्भुत कारनामे कर सकती है।

प्रभात - सलवा जुडूम द्वारा किए गए और किए जा रहे नरसंहारों के बीच जनता का मनोबल बनाए रखने और शत्रु के हमलों का प्रतिरोध करने में पीएलजीए की भूमिका कैसी रही?

कॉमरेड सुधाकर - सलवा जुडूम एक ऐसा बर्बर व फासीवादी हमला था जिसे साम्राज्यवादियों के निर्देश पर भारत के दलाल पूंजीपतियों और बड़े सामंतों की सरकारों ने सुनियोजित तरीके से सभी तैयारियों के साथ छेड़ दिया था। दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन का जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से जनता के खिलाफ स्थानीय प्रतिक्रियावादी कबीलशाहों और जन विरोधियों को एकजुट कर चलाया गया एक क्रूर अभियान था। जनता में आतंक मचाकर उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन से हटने पर मजबूर करना या फिर बलपूर्वक उससे दूर करना इस हमले का मकसद था। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर करना और उसके बाद दण्डकारण्य में मौजूद अपार खनिज संपदाओं का मनमाने ढंग से दोहन करना उसका रणनीतिक मकसद था। इस भयानक हमले के तहत पुलिस, अध सैनिक बलों, एसपीओ और जुडूम के गुण्डों ने सैकड़ों लोगों की हत्या की, गांव जलाए, सब कुछ तबाह किया। फिर भी जनता ने पीएलजीए की अगुवाई में और उसके सहयोग से इस हमले को पराजित कर दिया। 2005,

2006 और 2007 में जब सलवा जुडूम जोरों पर था, पीएलजीए हमेशा जनता के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी रही। इसी दौरान सैकड़ों नौजवान पीएलजीए में शामिल हुए जिससे प्रतिरोध को तेज करने में मदद मिली।

पहले से मौजूद मिलिशिया के अलावा 10 फरवरी 2006 को 'महान भूमकाल' की बरसी पर 'भूमकाल मिलिशिया' का निर्माण किया गया। सलवा जुडूम को हराने के मकसद से युवक-युवतियों के अलावा बड़ी उम्र के लोगों को भी हजारों की संख्या में इस मिलिशिया में गोलबंद किया गया। सलवा जुडूम के पराजित होने के बावजूद भी चूंकि हमेशा किसी न किसी रूप में दुश्मन का हमला जारी ही है, इसलिए जनता अभी भी यही चाहती है कि पीएलजीए की यूनिटें उनके पास ही रहें। जनता यह समझती है कि अगर उनके आसपास पीएलजीए की कोई कम्पनी या प्लाटून रहती है तो दुश्मन आसानी से घुस नहीं सकता और वे अपना कामकाज बिना किसी रुकावट के जारी रख सकेंगे। इस तरह पीएलजीए ने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली। खासकर पाशविक सलवा जुडूम अभियान शुरू होने के बाद से पीएलजीए जनता की चहेती हो गई क्योंकि प्रतिरोध में वह जनता के हाथों में हथियार के रूप में काम कर रही है।

प्रभात - जनता की राजसत्ता की स्थापना और उसके विस्तार में पीएलजीए किस तरह योगदान दे रही है?

कॉमरेड सुधाकर - पीएलजीए का मकसद ही जनता की राजसत्ता की स्थापना और उसका बचाव है। इन दस सालों में वह इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ती रही। निचले स्तर से उच्च स्तर तक गठित हो रही जनताना सरकार (क्रांतिकारी जन कमेटी) की संस्थाओं के निर्माण में पीएलजीए के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जनताना सरकार में रक्षा विभाग का जिम्मा पीएलजीए के प्रतिनिधियों को ही सौम्पा जाता है और इस तरह पीएलजीए भी इस सरकार में शामिल है। जनताना सरकार के सुचारू संचालन के लिए पीएलजीए सुरक्षा मुहैया करवाती है। पीएलजीए की सुरक्षा में ही जनताना सरकार की इकाइयां गठित होकर काम कर रही हैं और उनका विस्तार हो रहा है।

प्रभात - दण्डकारण्य में जनयुद्ध के सामने मुख्य समस्याएं क्या हैं? आप उन्हें कैसे हल कर सकेंगे?

कॉमरेड सुधाकर - आज दण्डकारण्य में जिस स्तर पर जनयुद्ध चल रहा है और जनता की सक्रिय भागीदारी जिस स्तर पर बढ़ चुकी है, उसे देखते हुए जनता को हथियारबंद करने के मामले में हम अभी भी काफी पीछे हैं। हजारों की संख्या में जन मिलिशिया है जो अपने परम्परागत हथियारों से ही लड़ रही है। अगर हम जन मिलिशिया को बेहतर हथियारों से लैस कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनयुद्ध में एक छलांग आ जाएगी। इसलिए जनता और जन मिलिशिया को हथियारबंद करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज।

दुश्मन के भारी घेराव-दमन अभियानों के बीच युद्ध की आज की जरूरतों के हिसाब से हम पीएलजीए के बलों को राजनीतिक व फौजी प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं। इससे जनयुद्ध का उस हद तक विकास नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। भर्ती को और भी बढ़ाने की जरूरत है। भर्ती अभियानों के महत्व को जनता के अंदर बड़े पैमाने पर प्रचारित करने की जरूरत है। जनयुद्ध के लिए जरूरी तमाम शक्तियों व संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

विभिन्न तबकों के बीच, गैर-किसानी जन समुदायों के बीच से पीएलजीए में भर्ती नहीं है। यह एक कमजोरी है जिसे हम तभी दूर कर सकेंगे जब हम व्यापक जन समुदायों के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार करेंगे। इस दिशा में हमें और ज्यादा जोर लगाकर काम करना चाहिए।

प्रभात - पीएलजीए की कुछ कार्रवाइयों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। ऐसी घटनाओं का फायदा उठाकर दुश्मन हमारे आंदोलन के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं? इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एसएमसी क्या कदम उठा रहा है?

कॉमरेड सुधाकर - जनयुद्ध के दरमियान पीएलजीए की कुछ फौजी कार्रवाइयों में कुछेक बार गलतियां हो रही हैं जिससे आम जनता, सामान्य सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हताहत हो रहे हैं जो क्रांतिकारी जनयुद्ध के दुश्मन कतई नहीं हैं। यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। हालांकि पीएलजीए के संविधान में इस बात का साफ उल्लेख है कि ऐसे लोगों को या उनकी सम्पत्तियों को कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए जो क्रांति के दुश्मन नहीं है। फिर भी ऐसी घटनाएं कभी-कभी हो रही हैं। लेकिन ये जानबूझकर की गई कार्रवाइयां नहीं हैं जैसा कि दुश्मन प्रचार कर रहा है। अधिकांश घटनाओं में धोखे से ही ऐसे हादसे हुए थे। हालांकि इक्के-दुक्के वाकिए ऐसे भी हैं जिसमें हमारे कॉमरेडों ने बिना सोचे-समझे ही बूबी ट्रैप लगा दिया जिसका आम लोग शिकार हो गए। जब भी ऐसी गलती हुई, हर बार पार्टी और पीएलजीए के नेतृत्व के द्वारा माफीनामा जारी किया गया और घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

हालांकि दुश्मन के छलपूर्ण दावपेंच भी कुछ मौकों पर ऐसी गलतियों का कारण बन रहे हैं। दुश्मन हमेशा यही चाहेगा कि पीएलजीए के हाथों हमेशा ऐसी गलतियां होती रहें ताकि उस पर जन विरोधी या आतंकवादी का ठप्पा लगाया जा सके। ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एसएमसी और विभिन्न स्तर की कमाण्ड्स समय-समय पर स्पष्ट निर्देश और शिक्षा दे रहे हैं। और जब गंभीर किस्म की गलतियां होती हैं तो सम्बन्धित कॉमरेडों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाइयां भी की जाती हैं। इस मौके पर मैं एसएमसी की ओर से जनता से अपील करता हूं कि इस मामले में सरकार और कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा किए जाने वाले इस दुष्प्रचार को ठुकरा दीजिए कि पीएलजीए आम लोगों पर हमले करती है। पीएलजीए जनता के बेटों और बेटियों से बनी सेना है। पीएलजीए के सैनिक जनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। निर्दोष लोगों को मारने के बारे में वे सपने में भी सोच नहीं सकते। जहां तक गलतियों की बात है, पीएलजीए की हर पल यही कोशिश रहती है कि उसकी कार्रवाइयों से आम जनता को जरा भी नुकसान न हो। फिर भी इस क्रूर और बर्बर युद्ध में, जिसे जनता के खिलाफ शोषक-लुटेरों ने थोपा है, कभी-कभी गलतियां हो सकती हैं। पीएलजीए की ईमानदारी और जन-पक्षधरता की कसौटी यह है कि वह अपनी गलतियों के प्रति क्या रुख अपना रही है।

प्रभात - फिलहाल क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से देशव्यापी आक्रमण चलाया जा रहा है। इसे परास्त करने के लिए पीएलजीए किस तरह काम कर रही है। इस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?

कॉमरेड सुधाकर - दण्डकारण्य की क्रांतिकारी जनता ने पीएलजीए की अगुवाई में काफी खून बहाकर फासीवादी सलवा जुडूम सैन्य अभियान को पराजित किया। इस सैन्य अभियान को पराजित करने के दौरान ही देश-दुनिया में सलवा जुडूम का पर्दाफाश किया गया। उसे न सिर्फ सैनिक रूप से हरा दिया गया, बल्कि राजनीतिक व सामाजिक रूप से नंगा कर दिया गया। इससे दुश्मन को आखिरकार उसकी पराजय कबूल करनी पड़ी। लुटेरे शासक वर्गों की शोषणकारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वे जनता के जीवन व अस्तित्व के लिए और भी घातक बन गई हैं। इसलिए एक अभियान के बाद वे और भी ज्यादा क्रूरता के साथ दूसरे दमन अभियान शुरू करते हैं। दण्डकारण्य में सलवा जुडूम की तरह देश के दूसरे हिस्सों में अलग-अलग प्रति-क्रांतिकारी दमन अभियान - जैसे कि झारखण्ड में सेंदरा और नागरिक सुरक्षा समिति, ओडिशा में शांति सेना, बंगाल में हर्मद बाहिनी आदि-आदि - चलाए गए और चलाए जा रहे हैं। इन सभी का निचोड़ लेकर दुश्मन ने, खासकर यूपीए के दोबारा सत्तारूढ़ होने बाद 2009 के मध्य से एक देशव्यापी फासीवादी दमन अभियान छेड़ दिया जिसे 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से बुलाया जा रहा है। इसके तहत दण्डकारण्य की जनता पर अकथनीय अत्याचार किए जा रहे हैं। यहां की क्रांतिकारी जनता को सलवा जुडूम को पराजित करने का अनुभव है। उस अनुभव की रोशनी में पीएलजीए जनता के सक्रिय सहयोग से पिछले एक साल से ऑपरेशन ग्रीन हंट का मुकाबला कर रही है जैसाकि देश के दूसरे हिस्सों में, खासकर बिहार-झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पीएलजीए ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ लड़ रही है। पीएलजीए के प्रतिरोध से दुश्मन के कई ऑपरेशन विफल कर दिए गए। खासकर सिंगनमडगू, मुकरम और कोंगेरा में दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दुश्मन की क्रूरता का पर्दाफाश करते हुए देश भर में जनता को गोलबंद करने की जरूरत है और जनता की सक्रिय भागीदारी से पीएलजीए को अपनी फौजी कार्रवाइयों में तेजी लाने की जरूरत है ताकि ऑपरेशन ग्रीन हंट को परास्त किया जा सके।

प्रभात - फिलहाल देश के शासक वर्ग क्रांतिकारी संघर्ष के दमन के लिए सेना को उतारने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर सेना तैनात की जाती है तो क्या आप उसका मुकाबला कर पाएंगे? उस स्थिति में आपके सामने क्या-क्या चुनौतियां होंगी?

कॉमरेड सुधाकर - दण्डकारण्य में सेना को उतारने की सारी तैयारियां चल रही हैं। दरअसल 2009 में तैयार की गई ऑपरेशन ग्रीन हंट की योजना में ही राष्ट्रीय रायफल्स की दस बटालियनें तैनात करने की बात शामिल थी। देश की सीमाओं पर देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई सेना को देश के बीचोबीच जनता के खिलाफ मोर्चे में लगाने से देश की जनता यह साफ समझ जाएगी कि यह युद्ध किसके हितों में और किसके खिलाफ लड़ा जा रहा है। इससे शोषक-लुटेरों की राज्यव्यवस्था के खिलाफ भारत की जनता का अंतरविरोध और भी तीखा हो जाएगा। देश भर में जनवादी ताकतें इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगी। पीएलजीए इस युद्ध के स्वभाव को जनता के सामने उजागर करते हुए इसे हराने हेतु जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद करेगी और उसका नेतृत्व करेगी। जनता की सक्रिय भागीदारी से इस अन्यायपूर्ण युद्ध को पराजित करेगी। हालांकि सरकार द्वारा प्रस्तावित सैन्य हमले को पराजित करना उतना आसान नहीं है। कई

कुरबानियां देनी पड़ेंगी और कई नुकसानों को सहना पड़ेगा। लेकिन अंतिम जीत जनता की ही होगी क्योंकि न्याय जनता के पक्ष में है।

प्रभात - पीएलजीए पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह बच्चों (नाबालिगों) को भर्ती कर लेती है। इस पर आपका स्पष्टीकरण क्या है?

कॉमरेड सुधाकर - 16 साल से ऊपर उम्र वालों को ही हम भर्ती कर रहे हैं। किसी भी नाबालिग को हमने पीएलजीए में शामिल नहीं किया। सरकारें, मीडिया का एक तबका और कुछ प्रतिक्रियावादी संस्थाएं हमारे ऊपर जानबूझकर यह आरोप लगा रही हैं ताकि हमारी पीएलजीए की साख पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चोट कर सके। हालांकि जिन इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन तेज है वहां पर बच्चे और किशोर विभिन्न बाल संगठनों और सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो रहे हैं। क्रांतिकारी संस्कृति का प्रचार करने में भाग ले रहे हैं। जहां सरकारी सशस्त्र बलों के आतंक के चलते जनता का जीवन ही अस्तव्यस्त हुआ हो और दुश्मन के द्वारा मचाए जा रहे नरसंहारों के चलते सैकड़ों परिवार बिखर गए हों वहां पर बच्चों के भविष्य पर ही सवालिया निशान लग गया। ऐसे में क्रांतिकारी आंदोलन ही कई मायनों में उनके लिए सहारा बनकर खड़ा है। जब यहां का पूरा समाज ही क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गया, तब बच्चों का इस आंदोलन से जुड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, 16 साल से कम उम्र के किशोरों को हम लड़ाकू बलों में, यानी पीएलजीए में शामिल नहीं करते हैं।

प्रभात - पीएलजीए में महिलाओं की भागीदारी किस स्तर पर है? मैदाने जंग में उनका योगदान और कमान संभालने में उनकी भूमिका किस रूप में है?

कॉमरेड सुधाकर - पीएलजीए में महिलाओं का प्रतिशत 35 से 40 तक है। लड़ाई के मैदान में वे पुरुषों के साथ बराबर जिम्मेदारियां निभा रही हैं। दुश्मन के खिलाफ हमलों में उनकी भागीदारी पुरुषों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ाई के मैदान में कुरबानियां देने में भी वे समान रूप से हिस्सेदारी ले रही हैं। 2005 में डौला पुलिस कैम्प पर किए गए हमले में दुश्मन पर आक्रमण के दौरान सेक्शन कमाण्डर करुणा और सदस्या कॉमरेड सोमारी शहीद हुईं। गंगलूर में सलवा जुडूम गुण्डों के कैम्प पर धावा बोलने के दौरान कॉमरेड येंकी शहीद हुई। तड़िकेल में कॉमरेड शांति शहीद हुई और ऐतिहासिक मुकरम हमले में सेक्शन कमाण्डर कॉमरेड रुकमति शहीद हुई। गड़चिरोली में दुश्मन के साथ लड़कर एक कमाण्डो को मार गिराकर कॉमरेड राधा शहीद हुईं। ये तमाम घटनाएं लड़ाई के मैदान में महिलाओं की भागीदारी की कहानी कहती हैं। आज लड़ाई के मोर्चे पर कई महिला कॉमरेड्स कमाण्डर के रूप में पीएलजीए बलों का नेतृत्व कर रही हैं। हालांकि महिलाओं की संख्या के अनुपात में उन्हें पीएलजीए के अंदर राजनीतिक व फौजी नेतृत्व के रूप में विकसित करने में हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं के लिए विशेष राजनीतिक व फौजी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं।

प्रभात - पीएलजीए की दसवीं वर्षगांठ के इस संदर्भ में दण्डकारण्य के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

कॉमरेड सुधाकर - भारत के दलाल शासक वर्ग ऐसी नीतियां अपना रही हैं ताकि दण्डकारण्य समेत देश के सभी खनिज-समृद्ध इलाकों से प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन किया जा सके। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। इन नीतियों का प्रतिरोध करने के कारण ही दण्डकारण्य समेत देश के विभिन्न आदिवासी इलाकों में जनता के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण युद्ध चलाया जा रहा है। अगर हमारा जल-जंगल-जमीन को बचाना है तो हमें इस अन्यायपूर्ण युद्ध का अंत करना ही होगा। इस युद्ध में जीत हासिल करनी है तो दण्डकारण्य के तमाम युवक-युवतियों को पीएलजीए में भर्ती होकर जनसेना को मजबूत करने की जरूरत है। तभी हम जनता की राजसत्ता की स्थापना कर सकेंगे।

प्रभात - देश की जनता, जनवादियों, प्रगतिशील व देशभक्त ताकतों का आप क्या आह्वान देना चाहेंगे?

कॉमरेड सुधाकर - दण्डकारण्य की जनता एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रही है। देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले दण्डकारण्य के निर्धनतम आदिवासी दुनिया की अधुनिकतम विचारधारा - मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद से लैस होकर जनता की राजसत्ता की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विकास का एक नया और जन-पक्षधर नमूना सामने ला रहे हैं। उनकी इस लड़ाई की अगुवाई पीएलजीए कर रही है। दुश्मन के कत्लेआमों और भीषण आतंक का सामना करते हुए यह संघर्ष जारी है। इस संघर्ष को आप सभी के समर्थन की जरूरत है। हम देश की तमाम जनवादी व प्रगतिशील ताकतों से अपील करते हैं कि वे दण्डकारण्य की जनता पर जारी सरकारी दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ★

दण्डकारण्य के तीस बरस - जनताना सरकार का विकासक्रम

- कामरेड मैना, डीके एसजेडसी सदस्य

हम सभी जानते ही हैं कि 'क्रांति का मतलब ही राजसत्ता को छीन लेना' है। आज जब हम दण्डकारण्य संघर्ष के तीस बरस पूरे होने के उपलक्ष्य में समूचे दण्डकारण्य में उत्सव मना रहे हैं। आइए, इस पहलू पर नजर डालें कि हमने दण्डकारण्य की जनता को 'जल-जंगल-जमीन पर अधिकार कायम करने' के नारे से किस तरह सचेतनशील किया और कैसे वर्ग संघर्ष में उतारा।

तीस साल पहले दण्डकारण्य की जनता सामंती कबीलशाही, रूढ़ीवादी कबीलाई रीति-रिवाजों, सरकारी वन विभाग के अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस व ठेकेदारों के जुल्म व अत्याचारों से त्रस्त थी। चूल्हा टैक्स, बकरी चराई टैक्स, बैल चराई टैक्स, घर टैक्स, झाड़ी टैक्स आदि अलग-अलग नामों से जनता को लूटा जाता था। श्रम की उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। कबीलाई प्रमुखों का दबाव ज्यादा रहता था। खासकर महिलाओं पर यह ज्यादा होता था। 1980 में हमारी पार्टी के प्रवेश के बाद सबसे पहले बांस कटाई, तेंदुपत्ता तोड़ाई आदि मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी, स्त्री-पुरुषों को बराबर की मजदूरी और श्रम का उचित भुगतान की मांगों को लेकर जनता को जन संगठनों में संगठित किया। कई संघर्ष छेड़कर कामयाबियां हासिल कीं। बेहद अभावों, परेशानियों और तकलीफों से जिंदगी गुजारने वाली जनता को पार्टी के रूप में एक सहारा मिल गया। नक्सलवादियों की लोकप्रियता बढ़ गई। जनता उन्हें 'अपने' मानने लगी। उसके बाद सामाजिक व सांस्कृतिक दमन के खिलाफ तथा महिलाओं की आजादी के लिए विशेष रूप से महिला संगठनों का निर्माण शुरू किया गया। जनता को व्यापक रूप से जन संगठनों में गोलबंद करने और जन संघर्ष शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ।

उसी सिलसिले में पार्टी सदस्यता भी बढ़ती गई और गांवों में पार्टी निर्माण - पहले पार्टी सेल और बाद में ग्राम पार्टी कमेटी - का क्रम शुरू हुआ। जन संगठनों में से डीएकेएमएस के कार्यकारिणी सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाती थीं। मसलन अगर पांच सदस्य होंगे तो उनमें से एक को कमेटी और संगठन के संचालन की जिम्मेदारी, एक सदस्य को ग्राम सुरक्षा दल का प्रभार, एक को जंगल बचाओ कमेटी की जिम्मेदारी, धान बीज के बैंक की जिम्मेदारी एक को और एक सदस्य को बाल संगठन की जिम्मेदारी दी जाती थी। इस तरह दण्डकारण्य संघर्ष के दूसरे दशक में डीएकेएमएस ही एक प्रकार से जन सरकार की तरह काम करता रहा। इस तरह एक अच्छा-खासा अनुभव भी मिल गया। जन मुक्ति छापामार सेना के निर्माण के बाद दुश्मन के दमन-अभियानों का मुकाबला करते हुए कई कामयाबियां हासिल की गईं। वर्ष 2000 से पीएलजीए के तीन बलों - आधार, माध्यमिक और प्रधान - तथा उन्नत फार्मेशनों का निर्माण हुआ। उस समय तक ग्राम राज्य कमेटी के नाम से जन राजसत्ता के संगठनों का निर्माण हो रहा था। उसके बाद क्रांतिकारी जन कमेटी (जनताना सरकार या आर.पी.सी.) के नाम से संगठित रूप से निर्माण काम शुरू हुआ। 500 से लेकर 3,000 की जन संख्या के हिसाब से पंचायत स्तर पर क्रांतिकारी जन कमेटियों का निर्माण किया गया।

आरपीसी का चुनाव ग्राम सभा के जरिए करने का एक जनतांत्रिक तरीका अपनाया गया जिसमें जन-विरोधियों, वर्ग दुश्मनों और क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा दण्डित लोगों को भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। ग्रामसभा में मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र 16 निर्धारित किया गया। चूंकि डीएकेएमएस के अध्यक्षों और रेंज कमेटी अध्यक्षों को सांगठनिक कामकाज का लम्बा अनुभव था, इसलिए पहले पहल उन्हीं लोगों को जनताना सरकार के लिए चुन लिया गया। हालांकि यह अवधारणा जनता तक ले जाने में खामी रही। लम्बे समय से गांवों में सरपंच, सचिव, पटेल, कोतवाल आदि को देख चुकी जनता को 'जनताना सरकार' के लिए चुनने की बात जब आई तो जनता उन्हीं लोगों को चुन लेती थी। तब फिर पार्टी को एक अभियान चलाना पड़ा। जनता में यह प्रचार किया गया कि परम्परागत कबीलाई मुखियाओं की बजाए ऐसे ईमानदार लोगों को चुन लेना चाहिए जो 10-15 बरसों से जन संगठनों और जन संघर्षों का नेतृत्व कर रहे हों। जब जनता के बीच इस बारे में बहस चलाई गई तो जनता ने इसे स्वीकार किया। उसके बाद चुने हुए लोगों में कुछ को हटाकर दूसरों को चुन लिया।

ग्राम सभा में उपस्थित होने वाली तमाम जनता (4-5 गांवों के दायरे से आने वाली जनता) को जनताना सरकार की नीति व कार्यक्रम समझाया जाता है। उसके बाद सरकार कमेटी का चुनाव होता है जो आम तौर पर पैनल को प्रस्ताव के रूप में रखने के बाद आमतौर पर जनता

मौखिक रूप से सहमति या तालियां बजाकर सहमति देती है। कमेटी के चुनाव के बाद वह शाखा कमेटियों में सदस्यों को मनोनीत करती है। उसके बाद कमेटी सदस्य और शाखा कमेटी सदस्य सभी मंच पर आकर जनता का अभिवादन करते हैं। जहां तक रक्षा विभाग की शाखा कमेटी का सवाल है, इसकी घोषणा सभी के सामने नहीं की जाती है। सरकार कमेटी इसे गोपनीय रखती है। आमतौर पर जनताना सरकार में कमेटी सदस्यों की संख्या 9 से 11 तक होती है। 15 तक भी रह सकती है।

शुरू-शुरू में कुछ जगहों पर जनताना सरकार कमेटियों के चुनाव के बाद जन संगठनों को भंग किया गया क्योंकि समझदारी में गड़बड़ी थी। लोग समझ नहीं पाए थे कि जन संगठनों और जनताना सरकार के कार्यभारों में क्या फर्क है। उसके बाद फिर पार्टी की ओर से समझदारी बढ़ाने के बाद इसे सुधारा गया। पार्टी की ओर से इस बाबत शिक्षित करते हुए कई सरकुलर और प्रस्ताव भी बनाकर नीचे तक ले जाया गया।

पंचायत स्तर की कम से कम 8 आरपीसी का जहां निर्माण हुआ वहां पर एआरपीसी (एरिया स्तर की जनताना सरकार) का निर्माण करने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी ग्राम, एरिया और जिला - तीन स्तरों पर जनताना सरकार की इकाइयों का निर्माण किया गया। राज्य स्तर की सरकार की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि माओ ने बताया, क्रांति के लिए जरूरी तीन जादुई हथियारों में पार्टी और जन सेना के अलावा संयुक्त मोर्चा एक है। दण्डकारण्य में सैकड़ों पार्टी, पीएलजीए और जन संगठनों के कार्यकर्ताओं व नेताओं के अलावा सैकड़ों जनता की कुरबानियों की बदौलत आज जनताना सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है।

फरवरी 2008 में दण्डकारण्य स्तर पर हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें जनताना सरकार का मार्गदर्शन करने में अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया। विभिन्न स्तर की जनताना सरकार की इकाइयों और अन्य संगठनों के बीच समन्वय के बारे में इस कार्यशाला में समझदारी बढ़ाई गई।

जहां एक तरफ जनताना सरकार का विकास और विस्तार होने लगा तभी 2005 में शोषक शासक वर्गों ने सलवा जुडूम अभियान शुरू किया ताकि जन सरकार का जड़ से सफाया किया जा सके। लेकिन संगठित जनता ने पीएलजीए की अगुवाई में 'कोया भूमकाल मिलिशिया' का गठन कर इसके खिलाफ संघर्ष किया। हर गांव और हर घर एक बूबी ट्रैप में तब्दील हुआ। जनता की सुरक्षा में ग्राम सुरक्षा दलों के अलावा मिलिशिया प्लाटून और मिलिशिया कम्पनी तक का निर्माण हुआ। और मिलिशिया की सारी जरूरतों, जैसे कि गोलीबारूद, तीर-धनुष, कपड़े, दवाएं आदि की पूर्ति करने के लिए जनतना सरकार ने अपना कोष जुटाया। काम चलाऊ डॉक्टरों की नियुक्ति की। जनता की हर गतिविधि के लिए मिलिशिया ने सुरक्षा पहुंचाई। जनताना सरकार की अगुवाई में जनता ने एक तरफ दुश्मन से लड़ते हुए फसलें उगाईं। शहीद परिवारों की मदद की। इस तरह जनताना सरकार ने शोषक सरकारों द्वारा लादे गए अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ जनता को राजनीतिक रूप से संगठित किया।

इस संघर्ष ने न सिर्फ जनता को संगठित किया, बल्कि पितृसत्ता के बंधनों को ध्वस्त करने का नारा देकर महिलाओं को समान दर्जा दिलवाया। कई महिलाओं ने भी इस दौरान अपने प्राणों की कुरबानी दी।

एक तरफ सलवा जुडूम के दौरान लोगों के घरों को जलाने, सामूहिक हत्याएं और महिलाओं के साथ बलात्कार आदि हमले हो रहे थे, उसके बीचोबीच ही, मिलिशिया की सुरक्षा में बच्चों के लिए स्कूलें चलाई जा रही हैं। इस तरह 30 से ज्यादा स्कूलें पंचायत स्तर पर चलाई जा रही हैं। दुश्मन की नाकेबंदी के चलते अगर चावल नहीं मिलता है तो पेज-पसिया पीकर भी बच्चे जनताना सरकार द्वारा संचालित इन आश्रमशालाओं में पढ़ रहे हैं। बाहर से दवाओं की सप्लाई न होने की स्थिति में जनताना सरकार ने अपने डॉक्टरों को 'जड़ी-बूटियों' के साथ लोगों का इलाज करने का निर्देश दिया। इस दिशा में जनताना सरकार के डॉक्टरों ने सराहनीय ढंग से काम किया और कई लोगों की जानें बचाईं। जंगल बचाओ कमेटियों का काम भी सराहनीय रहा। हाल ही में जारी शोषक सरकार की एक रिपोर्ट में भी यह बात रेखांकित की गई कि जहां नक्सलवादी मौजूद हैं वहां जंगलों का नुकसान कम हुआ है। एक ओर कृषि विभाग और दूसरी ओर जंगल बचाओ कमेटियों के कामकाज से जनताना सरकार की गतिविधियों में प्रगति हुई, वहीं दूसरी ओर इन सभी कामों में जनता की सक्रिय भूमिका बढ़ गई।

साम्राज्यवादियों के दलाल लुटेरे शासक वर्ग आज देश भर में जनता को बड़े पैमाने पर विस्थापित करते हुए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। इन नीतियों का विरोध करने के कारण ही उन्होंने जनता पर युद्ध छेड़ दिया। फिलहाल सेना को उतारकर इस अन्यायपूर्ण युद्ध को और ज्यादा तेज किया जा रहा है। इस युद्ध का विरोध

(शेष पेज 39 में...)

संदेश

दण्डकारण्य आन्दोलन के 30 वर्ष

– कामरेड किशन
सचिव, पूर्वी रीजनल ब्यूरो, भाकपा (माओवादी)

सर्वविदित है कि 1960 के उथल-पुथल भरे दशक में महान माओ के नेतृत्व में ख्रुश्चेव के आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ जो जबरदस्त 'महान बहस' चलाई गई थी, और चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति का संचालन किया गया था, भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी उसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही नेतृत्व की संशोधनवादी लाइन व कार्यशैली के खिलाफ बगावत का बिगुल बज उठा। इसी परिप्रेक्ष्य में कामरेड सी.एम. और कामरेड के. सी. जैसे उत्कृष्ट व प्रतिभावान नेता उभर कर सामने आए।

जनता की राजसत्ता की रक्षा में पीएलजीए

भारत की धरती पर भी कामरेड सी. एम. के नेतृत्व में उसी कोलाहल भरी स्थिति की धारावाहिकता में ही 1967 में, दीर्घ दिन से चला आ रहा संशोधनवाद व संशोध नवादी-संसदवादी रास्ता को पूरी तरह नकारते हुए 'बसंत का बज्रनाद' के बतौर महान नक्सलबाड़ी आन्दोलन की रणभेरी बज उठी। 'संशोधनवाद मुर्दाबाद' और 'मा-ले-मा जिंदाबाद' के नारों से आसमान गूंज उठी। इतिहास के पिछले 40 सालों से भारत के सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी न केवल मा-ले-मा के लाल झंडे को ऊपर उठाये रखे, बल्कि अपने आन्दोलनों के सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों का विश्लेषण व संश्लेषण करते हुए तथा अतीत की भूलों से सबक लेते हुए और उतार-चढ़ाव व कुछ धक्कों को पार करते हुए और साथ ही साथ, 'मौजूदा धोखाधड़ीपूर्ण चुनाव-व्यवस्था का खारिज तथा चुनाव का बायकाट करें' की आवाज को बुलंद करते हुए दीर्घकालीन लोकयुद्ध जारी रखने और उसे आगे बढ़ाने में बहुतेरी शानदार सफलताएं हासिल की हैं। साथ ही, सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के बीच की एकता प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर एक एकताबद्ध पार्टी का गठन करने के पहलू पर भी ऐतिहासिक सफलता मिली। 2004 के 21 सितम्बर में दो ऐतिहासिक धारा यानी सी.पी.आई. (एम.-एल.) व एम.सी.सी.आई. की धारा की मिलन से जो नई व एकताबद्ध पार्टी भाकपा (माओवादी) का उदय हुआ वह बहुतेरी शानदार सफलताओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख घटना है।

इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि 1980 से शुरू कर पिछले 30 वर्षों के घमासान क्रान्तिकारी वर्ग-संघर्ष तथा कृषि-क्रान्तिकारी गुरिल्ला युद्ध के दौरान और शोषक-शासकों के हर प्रकार के जुल्म-अत्याचार व बर्बर 'घेरा डालो व विनाश करो' सैनिक अभियान का शानदार प्रतिरोध करने के दौरान और अनगिनत कामरेडों के अमूल्य प्राणों के न्यौछावर की बदौलत दण्डकारण्य के आसमान पर क्रान्ति का चमकता लाल तारा आज और ज्यादा चमक रहा है। ऐसा कि अमरीकी साम्राज्यवाद के खिदमतगार सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम फासीवादी गुट द्वारा चलाया जा रहा बर्बर सैनिक अभियान 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' उक्त चमक पर थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचा सका है। बल्कि ग्रीन हंट का शानदार व मुंहतोड़ जवाब से शासक गुट चिन्तित व भयभीत है और क्रान्तिकारी जनता उल्लासित है। दण्डकारण्य की वीरभूमि आज जनमुक्ति छापामार सेना के बटालियन व कम्पनी की कूच से गौरवान्वित है और 'हम है लाल सेना, जनमुक्ति गुरिल्ला सेना' की गूंज से मुखरित है। निस्संदेह, छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में, पीएलजीए

को पीएलए में, छापामार जोन को आधार इलाके में बदलने के कार्यभार आज दण्डकारण्य की धरती पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा कि दण्डकारण्य की वीरभूमि आज जनता की जनवादी व्यवस्था का व्यावहारिक स्वरूप 'जनताना सरकार' की स्थापना की घोषणा से गौरवान्वित है।

पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में और खासकर दण्डकारण्य के आन्दोलन में विभिन्न स्तरों पर 'जन सरकार' की स्थापना एक बड़ी व गुणात्मक उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि के लिए दण्डकारण्य की वीर जनता और वीर कामरेडों को उनकी शौर्यपूर्ण व वीरतापूर्ण भूमिका के लिए भारत के मजदूर-किसान व मेहनतकश जनता सहित तमाम प्रगतिशील, व जनवादी ताकतें अवश्य ही क्रान्तिकारी अभिनन्दन व बधाई देती रहेंगी।

हमारे संस्थापक व शिक्षक कामरेड सी.एम. और कामरेड के.सी. द्वारा निर्धारित भारतीय क्रान्ति की बुनियादी लाइन भी किस हद तक सही है, इसका भी भली भांति प्रमाण दे रहा है दण्डकारण्य का क्रान्तिकारी संघर्ष। कामरेड सी.एम. व कामरेड के.सी. के ''अगर जनता के हाथ में हुकूमत या राजनीतिक शासन की क्षमता नहीं है तो कुछ भी नहीं है'', इस उक्ति को कुछ हद तक वास्तविकता में बदल पाया है दण्डकारण्य का क्रान्तिकारी संघर्ष।

क्रान्तिकारी संघर्ष के नक्शे में आज एक अति प्यारा व अग्रणी नाम है - दण्डकारण्य। दण्डकारण्य का मतलब है प्रचलित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह। दण्डकारण्य का मतलब है क्रान्ति। दण्डकारण्य का मतलब है पार्टी, जन सेना व संयुक्त मोर्चा इन तीनों का सही तालमेल कर जनसत्ता की स्थापना। दण्डकारण्य निश्चित रूप से ही भारत की नई जनवादी क्रान्ति में और अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता रहेगा। दण्डकारण्य भविष्य में समाजवाद को लाने के मामले में भी निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका अदा करता रहेगा।

दण्डकारण्य क्रान्तिकारी संघर्ष के तीस वर्षों के अवसर पर तमाम शहीद कामरेडों को लाले लाल, लाल सलाम। नया इतिहास बनाने वाले दण्डकारण्य की वीर जनता को लाल सलाम। दण्डकारण्य के वीर कामरेडों को लाल सलाम। दण्डकारण्य का संघर्ष और नई-नई सफलताएं हासिल करके ही रहेगा। दण्डकारण्य का संघर्ष अंतिम विजय हासिल करके ही रहेगा। रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा व कठिन जरूर है, पर सही लाइन-नीति व कार्यशैली का अनुसरण कर पाने से अंतिम जीत जनता की ही होगी।

30-07-2011

(... पेज 40 का शेष)

संबध है। यह न केवल प्रेरणास्रोत है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है।

आज भारत की जनता माओवादियों को एक विकल्प के रूप में देख रही है। इसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक समस्याओं के समाधान के रूप मे देख रही है। साम्राज्यवादी-सांमतवादी शोषण और उत्पीडन से मुक्ति के रूप मे देख रही है। जातिप्रथा निर्मूलन के लिए, महिलाओं के समान हक के लिए, सांप्रदायिकता के विष का नाश करने के लिए, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं मुक्ति के लिए समाधान के रूप के देख रही है। इस आस और दृष्टिकोण के निर्माण में दंडकारण्य आंदोलन का खासा महत्व है।

महाराष्ट्र की पुर्वी छोर पर माड़ पर्वतों से निकली यह मुक्ति की लालिमा पश्चिम छोर में अरबी सागर तक जन-जन मे फैलाव करने के लिए और दंडकारण्य की नई जनसत्ता की रक्षा करने के लिए, महाराष्ट्र के इलाकों में प्रतिरोध संघर्ष की फौलादी दीवार खड़ी करने महाराष्ट्र के क्रांतिकारी साथी वचनबद्ध हैं।

दंडकारण्य भारत का येनान बनकर उभरे और विकसित होते हुए भारत को नवजनवादी भारत बनाने के लिए क्रांति का अग्रदूत बनकर सारे दमन अभियानों को नेस्तनाबूद करते हुए मजबूती के साथ बढ़ते रहे, यही क्रांतिकारी शुभेच्छा!

फिर एक बार इस आंदोलन में प्राण अर्पण किए तमाम अमर शहीदों का स्मरण करते हुए यहां के नेतृत्व, कतारों, पीएलजीए और जनता को लाल-लाल सलाम पेश करता हूं।

6 दिंसबर 2010

(... पेज 37 का शेष)

करना और इसका मुकाबला करना न सिर्फ दण्डकारण्य वासियों का, बल्कि देश के समूचे शोषित-पीड़ित अवाम का कर्तव्य है। दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड के साथ-साथ देश के कुछ अन्य इलाकों में विकसित हो रही जनता की राजसत्ता आज शोषक सरकारों के लिए चुनौती बन गई है। दूसरी ओर देश के तमाम मेहनकश लोगों तथा जनवादपसंदों के लिए यह एक आशा की किरण बन गई है। जनता की इस उदीयमान राजसत्ता का स्वागत करना तथा उसके बचाव में आगे आना तमाम देशवासियों का कर्तव्य है। आइए, इस नवोदित जन सत्ता पर शोषक सरकारों द्वारा लादे गए बर्बरतापूर्ण व अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। आइए, यह नारा बुलंद करें - जनयुद्ध अपराजेय है! जनताना सरकार अमर है! ★

संदेश

दंडकारण्य आंदोलन के 30 वर्ष के उपलक्ष्य में

- कामरेड सह्याद्री,
सचिव, महाराष्ट्र राज्य कमेटी, भाकपा (माओवादी)

दंडकारण्य के आंदोलन के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर दंडकारण्य की महान जनता, इस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले केंद्रीय कमेटी और खासकर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, सभी स्तरों के नेतृत्व, कतारों, पीएलजीए के तीनों बल, विभिन्न जन संगठनों के नेता और कार्यकर्ता तथा जनताना सरकार के जिम्मेदार साथियों को मैं हार्दिक क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूं।

इस अवसर पर उन प्यारे अमर शहीदों की याद ताजा हो रही है जिन्होंने अपने खून से सिंचकर इस आंदोलन को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। इसमें सबसे पहले शहीद का. पेद्दी शंकर से लेकर अब तक के तमाम शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें लाल-लाल जोहार है।

दंडकारण्य की यह भूमि आदिवासियों की साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की ऐतिहासिक भूमि है। यहां की मिट्टी और आबोहवा वीर बाबूराव सेड़िमेक, गुंडाधूर, गेंदसिंग आदि वीरों की बहादुरी की गवाह है। सौ साल पूर्व 'भूमकाल विद्रोह' ने साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की जो नींव रखी थी उसे आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व मे चल रहे आंदोलन ने बुलंदी पर पहुंचाया है।

जनता की शोषणविहीन नई जनसत्ता का जो सपना नक्सलबाड़ी आंदोलन ने संजोया था, उसे साकार करने का काम दण्डकारण्य के इस महान आंदोलन ने किया है।

तेलंगाना, खासकर आदिलाबाद, निजामाबाद व करीमनगर के किसान-मजदूर वर्गीय जनता के जुझारू संघर्ष और बलिदान से रक्तप्रवाहित होकर यह आंदोलन भारत की शोषित जनता का आशा का 'धृवतारा' बन गया है।

तीन दशक के वर्ग युद्ध के घमासान में यहां की जनता ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, दमन का सामना करते हुए आंदोलन को इस मुकाम पर पहुंचाया है। यहां की आदिवासी जनता ने मानवता को लज्जित करने वाले फासीवादी दमन अभियान 'सलवा जुडूम' को धूल चटाई है। सरकार के विभिन्न अर्धसैनिक बलों और स्पेशल टास्क फोर्स का डटकर मुकाबला करते हुए देश की शोषित जनता में जनयुद्ध के प्रति विश्वास जगाया है।

इस आंदोलन ने जंगल ठेकेदारों, सरकारी अफसरों और गांवों के दंबग लोगों से आदिवासियों की इज्जत और जान-माल की रक्षा की है। रीतिरिवाज के नाम पर आदिवासी समाज में चलने वाले महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए परिवर्तन लाया है। यहां के जल-जंगल-जमीन और मूल्यवान खनिज सम्पत्ति की रक्षा इस आंदोलन ने की है। आज फिर साम्राज्यवादी मुनाफाखोरों की नजर यहां की प्राकृतिक सम्पत्ति पर है। वह बौखलाकर आदमखोर जानवर की तरह अपने ही देश की जनता पर हमले कर रहा है। दंडकारण्य में उदीयमान नई जनसत्ता भारत की साम्राज्यवाद-सांमतवाद के पंजों से मुक्ति दिलाने वाले उगते सूरज के समान है। इसलिए दंडकारण्य की जनता पर हो रहा हमला यह भारत की जनता के सपने को ही मार डालने की साजिश है। अब यह देश भर की जनता का कर्तव्य है कि इस हमले के खिलाफ उठ खड़े हों।

दंडकारण्य की उदीयमान नई जनसत्ता पर्यावरण की रक्षा करते हुए स्वयंसम्पूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माण की ओर कदम बढ़ा रही है। सामूहिक चेतना से लबालब होकर, रूखी-सूखी से गुजारा करते हुए, छालों की परवाह न करते हुए यहां के हजारों हजार हाथ आज व्यापक उपयोगिता मूल्यों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कल लाखों-करोडों जुड़कर मुंबई स्टाक एक्सचेंज और बाजारू मूल्यों को कब्र में दफना देंगे।

दंडकारण्य मे नई जनसत्ता के उदय के साथ ही भारतीय राजनीतिक पटल पर हड़कंप मच गया है। क्रांतिकारियों और प्रतिक्रांतिकारियों का राजनीतिक धृवीकरण हर स्तर पर होने लगा है। इस आंदोलन ने महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े क्षेत्र को सबसे उन्नत विचारों से लैस कर सबसे बड़े महानगर मुंबई तक में रहने वाले बुद्धिजीवी और मजदूर वर्ग को प्रभावित किया है और पूंजीवादी विकास के साथ जनवाद अपने आप स्थापित होता है, इस विचार के खोखलेपन को सरेआम नंगा कर दिया है। लाल झंडा समाजवाद, जनतंत्र के आवरण मे पलने वाले संशोधनवादियों और सुधारवादियों का पर्दाफाश किया है।

इस आंदोलन ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की प्रासंगिकता व दीर्घकालीन जनयुद्ध की रणनीति को प्रभावित किया है। अप्रतिम त्याग और जनता की निस्वार्थ सेवा करते हुए यहां के क्रांतिकारियों ने महिला-पुरुष समानता और उच्चतम मानवीय मूल्यों को व्यवहार में आम बनाया है। इस आंदोलन का महाराष्ट्र की जनता के साथ जीवंत

(शेष पेज 39 में...)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति : **31 अक्टूबर 2010**

महासमुंद जिले में पुलिस की अंधाधुंध गोलीबारी में शहीद हुए नौ कॉमरेडों तथा भिलाई फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कॉमरेड्स नागेश और प्रमीला को लाल सलाम!

सावरगांव (गढ़चिरौली जिला) हत्याकाण्ड के लिए जिम्मेदार आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के हत्यारों को सजा दो!

फर्जी मुठभेड़ों और अंधाधुंध हत्याओं से क्रांतिकारी आंदोलन को रोक नहीं सकते!

'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के तहत आम लोगों और क्रांतिकारियों की निर्मम हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। अगस्त 2009 से अभी तक देखा जाए तो पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों, एसपीओ और कोया कमाण्डो ने अलग-अलग घटनाओं में 170 से ज्यादा लोगों की जानें लीं। इनमें अत्यधिक संख्या निहत्थे व आम आदिवासियों की है। इसके साथ-साथ 'शांति संघर्ष मोर्चा' के नाम से फिर एक बार सलवा जुडूम की तर्ज पर बड़े पैमाने पर गांव-दहन, अंधाधुंध हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटपाट और आतंक का नंगा नाच करने की कोशिशें भी चल रही हैं। सलवा जुडूम इतना बदनाम हो चुका था कि उनकी अपनी अदालतों में भी सरकार को फजीहत झेलनी पड़ रही थी। इसलिए अब उसे एक नए नाम की जरूरत पड़ गई। यानी शराब भी पुरानी है और बोतल भी वही, फर्क इतना है कि बोतल पर लेबल बदला गया है - शांति संघर्ष मोर्चा। हम जनता को आगाह करते हैं कि वह आने वाले खतरों से सावधान रहे और सलवा जुडूम की ही तरह इस 'शांति संघर्ष मोर्चे' का भी एकजुटता से प्रतिकार करे।

इसके अलावा, इस महीने के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी विवरण और स्पष्टीकरण दे रही है।

सावरगांव हत्याकाण्ड (8 अक्टूबर 2010) - राजनांदगांव जिले के मानपुर डिवीजन में पिछले एक साल से आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के बल जनता पर आतंक का तांडव मचाते आ रहे थे। देश की सीमाओं पर रहकर कथित रूप से देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाई गई इस फोर्स को देश के बीचोबीच स्थित आदिवासी इलाकों में उतारकर सरकारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे देश की जनता को ही दुश्मन मानती हैं। मानपुर क्षेत्र में दर्जनों लोगों को पकड़कर यातनाएं देना, झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजना, महिलाओं के साथ बलात्कार आदि कई अपराधों में शामिल इन भाड़े के अर्ध-सैनिक बलों को सबक सिखाने के इरादे से 8 अक्टूबर को हमारी पीएलजीए ने मानपुर (छत्तीसगढ़) व गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) की सीमा पर हमला कर दिया। बारूदी सुरंग के विस्फोट से किए गए इस हमले में आईटीबीपी के तीन जवान मारे गए थे। विस्फोट के बाद हमारे कॉमरेड पीछे हट गए थे। इसके बाद बौखलाए हुए आईटीबीपी के जवानों ने, जो दूसरे वाहनों में सवार थे, घटनास्थल से थोड़ी दूर पर स्थित सावरगांव जोकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की धनोरा तहसील में आता है, की आम जनता पर अपना गुस्सा उतारा। वहां के आश्रम स्कूल में आईटीबीपी के जवानों द्वारा गोले दागे जाने से दो स्कूली बच्चों समेत कुल छह लोग मारे गए, जबकि आठ अन्य बुरी तरह घायल हो गए। एक सोची-समझी साजिश के तहत इस हत्याकाण्ड को अंजाम देकर, फिर इसके लिए हमारी पार्टी को जिम्मेवार ठहराते हुए पुलिस-प्रशासन ने बयान जारी किया कि नक्सलवादियों की तरफ से राकेट का गोला दागे जाने से इन ग्रामीणों की मौत हुई थी। लेकिन जनता को अच्छी तरह मालूम है कि यह दरिंदगी आईटीबीपी के जवानों की थी। हमारी स्पेशल जोनल कमेटी इस हत्याकाण्ड की निंदा करती है और इसके लिए जिम्मेवार आईटीबीपी वालों और उन्हें इस तरह उकसाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने की लोगों से अपील करती है।

महासमुंद मुठभेड़ (9 अक्टूबर 2010) - महासमुंद में क्रांतिकारी संघर्ष के विस्तार के सिलसिले में लोगों से संपर्क कर एक गांव में बैठक ले रहे हमारे एक गुरिल्ला दस्ते पर, पहले से मिली मुखबिरी के आधार पर करीब 500 पुलिस व कमाण्डो बलों ने भारी हमला किया। अपने से 50 गुना से भी ज्यादा संख्या में आए शत्रु बलों का मुकाबला करने के दौरान दो निर्दोष ग्रामीण समेत कुल 9

कॉमरेड शहीद हो गए। हमारे कॉमरेडों के प्रतिरोध में एसटीएफ के दो जवान घायल हो गए। अंधाधुंध गोलीबारी में इन कॉमरेडों की हत्या कर आज रमन सरकार खुशियां मना रही है कि उसने महासमुंद में क्रांतिकारी संघर्ष के विस्तार को रोक दिया। लेकिन इतिहास इसके उलट है। जहां भी क्रांतिकारी संघर्ष का विस्तार हुआ, शहीदों के बलिदानों से ही हुआ। 2 नवम्बर 1980 कॉमरेड पेद्दि शंकर की हत्या से दण्डकारण्य में क्रांति के फैलाव को रोका नहीं जा सका था। 9 अक्टूबर 2010 को महासमुंद में इन 9 कॉमरेडों का बहाया गया खून भी जरूर रंग लाएगा। हमारी स्पेशल जोनल कमेटी इन वीर शहीदों को श्रद्धांजली पेश करती है और उनके अधूरे मकसद को पूरा करने की कसम खाती है।

भिलाई फर्जी मुठभेड़ (15 अक्टूबर 2010) - हमारी पार्टी के उत्तर रीजनल कमेटी सदस्य व उत्तर बस्तर-माड़ संयुक्त डिवीजनल कमेटी के सदस्य कॉमरेड नागेश और पीएलजीए की पलटन-25 की सदस्या कॉमरेड प्रमीला को एक गद्दार की सूचना पर पुलिस ने उठा लिया था। वे दोनों निहत्थे थे। उन्हें बुरी तरह यातनाएं देने के बाद पुलिस ने इन दोनों की ठण्डे दिमाग से हत्या कर भिलाई के जामुल इलाके में लाशें डालकर वहां 'मुठभेड़' होने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। पुलिस ने अपनी झूठी कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए घटनास्थल से दो पिस्तौल समेत कुछ अन्य सामान बरामद होने तथा वहां से एक और नक्सलवादी के भाग जाने का झूठा बयान दिया। आईजी मुकेश गुप्ता, डीजी विश्वरंजन आदि अधिकारियों ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताते हुए, खासकर नक्सलवादियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने में एसआईबी (स्टेट इंटेलिजेन्स ब्यूरो) की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। वास्तव में ये दोनों कॉमरेडों का हमारे शहरी कामकाज से कोई सम्बन्ध नहीं था और भिलाई के पास कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। रमन सरकार ने शहरी क्षेत्र में 'मुठभेड़' के इस फर्जीवाड़े को एक खास मकसद से अंजाम दिया। शहरी जनता को आतंकित करना, उनके अंदर नक्सलवाद के प्रति खौफ पैदा करना और उनमें असुरक्षा का माहौल पैदा करना - यही उसका मकसद था। हमारी स्पेशल जोनल कमेटी इस फर्जी मुठभेड़ की निंदा करती है और रमन सरकार को चेतावनी देती है कि इस तरह की हत्याओं से क्रांतिकारी संघर्ष को रोक पाने के उसके सपने कभी सच नहीं होंगे।

राधेश्याम हमारा आदमी नहीं, पुलिस का मुखबिर है - 21 सितम्बर 2010 को पुलिस ने दावा किया था कि उसने रायपुर के लाखेनगर इलाके से हमारे शहरी नेटवर्क से जुड़े राधेश्याम गिरी नामक कुरियर को गिरफ्तार कर लिया। राधेश्याम रोजी-रोटी कमाने के लिए रायपुर आया हुआ एक आम आदमी था, जो कुछ साल पहले हमारी पार्टी का समर्थक हुआ करता था। दिसम्बर 2007 में सुमित नामक हमारे एक कार्यकर्ता को मानपुर इलाके में पकड़ने के बाद उस समय के राजनांदगांव जिला एसपी वीके चौबे, एएसपी मनीष शर्मा और प्रखर पाण्डे ने उसे अपना दलाल बनाकर हमारे शहरी संगठन को काफी नुकसान पहुंचाया था। उस दौरान राधेश्याम गिरी समेत सम्बलपुर गांव (डौंडी-लोहारा के पास) के कुछ अन्य युवकों को पुलिस ने पैसों का प्रलोभन देकर अपना मुखबिर बना लिया था। इसकी हमें खबर नहीं थी। मृत वीके चौबे की साजिश के अनुसार 2008 के आखिर में राधेश्याम ने मानपुर इलाके में हमारी पार्टी से संपर्क किया था। वह पार्टी के नेतृत्वकारी कॉमरेडों की हत्या की साजिश का हिस्सा बना था। दरअसल राधेश्याम से पुलिस अफसर खुद ही 'नौकरी' करवा रहे थे और बाकायदा वेतन भी दे रहे थे। जिस तरह पुलिस जब उसको खानापूर्ति करनी होती है तो कुछ चोर-बदमाशों को 'पकड़कर' जेल भेजती है, उसी प्रकार उसने अब एक अपने ही मुखबिर को 'नक्सलवादियों का कुरियर' बताकर जेल भेज दिया। इसके पीछे कारण साफ है - उसको दिखाने के लिए नक्सलवादियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने में एक 'सफलता' चाहिए थी। यह इसलिए भी चाहिए थी ताकि शहरों में रहने वाले मजदूरों और अन्य मेहनतकशों व मध्यमवर्गीय जनता को डर के साये में रखा जा सके। उनको यह दिखाया जा सके कि पुलिस के हाथ कितने 'लम्बे' हैं।

हम छत्तीसगढ़ के मजदूर-किसानों और बुद्धिजीवी तबकों, लेखक-पत्रकारों व तमाम मीडियाकर्मियों से अपील करते हैं कि वे रमन सरकार के झूठे व भ्रामक दावों का पर्दाफाश करें। केन्द्र व राज्य सरकारें बर्बर तरीकों में आंदोलन का दमन करने की कोशिशों के साथ-साथ एक जहरीला दुष्प्रचार अभियान भी चला रही हैं जो उसके मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। (हमारे स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड गणेश के मारे जाने का झूठा प्रचार भी इसी का हिस्सा था।) इसकी निंदा करने और क्रांतिकारी आंदोलन पर जारी बर्बर दमन अभियानों के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने का हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं।

गुड्सा उसेण्डी, प्रवक्ता
डीकेएसजेडसी
भाकपा (माओवादी)

ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत जारी सरकारी आतंक व जहरीले दुष्प्रचार की निंदा करो!

जगुरगोण्डा फर्जी मुठभेड़ में मारे गए जन मिलिशिया के शहीदों को लाल सलाम!

'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के तहत दण्डकारण्य के गांवों में सरकारी आतंक का नंगा नाच जारी है। 23 नवम्बर को जगुरगोण्डा के निकट अपने गांव में फसलें काटने वाले किसानों की सुरक्षा में तैनात जन मिलिशिया के 9 कॉमरेडों की निर्मम हत्या कर सीआरपीएफ और राज्य पुलिस बलों ने इसे अपनी बहुत बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित किया। **उइके सन्नू, उइके दूला, करपी सुब्बा, कोरसा सुक्का, कुंजाम जोगा, कोरसा सुधाकर, एमला सागर, हिड़मा और आयतू - ये नौ कॉमरेड अपने गांव की और गांव की जनता की रक्षा करने के लिए जन मिलिशिया में काम कर रहे थे।** ये सभी निहत्थे थे या छिटफुट परम्परागत हथियारों से लैस थे। और ये लोग हमारी पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ता भी नहीं थे और ताड़िमेटला की कार्रवाई से इनका कोई संबन्ध नहीं था, जैसा कि सरकारी दुष्प्रचार जारी है। जबसे बर्बर व फासीवादी सलवा जुडूम अभियान शुरू हुआ था, खास तौर पर तबसे इस तरह लोगों ने गांव-गांव में खुद को मिलिशिया में व्यापक रूप से संगठित कर लिया। यह उनके अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी भी और जायज भी है। इस तरह के निरीह व गरीब आदिवासी युवकों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर सभी को मारकर मुठभेड़ की कहानी गढ़ना और यह कहना कि सीआरपीएफ ने नक्सलवादियों पर बदला लिया, सरकार व पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों के दिवालिएपन का साफ सबूत है। जन मिलिशिया के इन नौ शहीद कॉमरेडों को दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तहेदिल से श्रद्धांजली पेश करती है और उनकी हत्या का बदला लेने का संकल्प दोहराती है।

उसी दिन नारायणपुर जिले के तिरकानार गांव पर सैकड़ों पुलिस व सीआरपीएफ ने हमला कर एक स्कूल को जला दिया। और बस्तर एसपी सुंदरराज ने जगदलपुर में 25 नवम्बर को पत्रकारों को बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़े नक्सलवादी शिविर पर हमला किया था। दरअसल उस गांव में *जनताना सरकार* (जन सरकार) की अगुवाई में एक प्राथमिक स्कूल का संचालन हो रहा था जिसमें करीब 20 बच्चे पढ़ते हैं। यह आश्रमशाला थी जिसमें आसपास के दो-तीन गांवों के बच्चे उसी में रहकर पढ़ाई करते हैं। दो शिक्षक उसमें काम करते हैं जिन्हें जनता ने ही नियुक्त कर रखा है। एक साथ चार-पांच थानों से 500 से ज्यादा संख्या में निकले पुलिस बलों ने इस गांव पर हमला करके पूरे स्कूल को जला दिया। पुलिस के आने की खबर पाकर स्कूल के बच्चे और शिक्षक अन्य ग्रमीणों के साथ मिलकर पहले ही जंगलों में भाग गए थे। तीन ग्रामीणों को पकड़कर उन्हें नक्सलवादी के रूप में चित्रित कर रहे हैं। पूरे स्कूल को और स्कूल में रखे हुए खाने के अनाज समेत सारे सामान को पुलिस व सीआरपीएफ ने जलाकर अपनी दरिंदगी का परिचय दिया।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अक्टूबर 2008 में नारायणपुर जिले के ही कुमुडगुण्डा नामक एक गांव में भी इसी तरह पुलिस ने *जनताना सरकार* द्वारा संचालित स्कूल पर हमला किया था। सुरक्षा बलों को स्कूली भवनों पर से कब्जा हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसकी अवहेलना करते हुए सरकारी सशस्त्र बलों ने हर जगह स्कूली भवनों पर कब्जा जमाकर आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनता द्वारा अपनी पहलकदमी से चलाई जा रही स्कूलों को इस तरह ध्वस्त कर रहे हैं। हम जनता और जनवाद के प्रेमियों से अपील करते हैं कि आदिवासी गांवों पर, उनकी स्कूलों पर, उनकी जिंदगियों पर जो सरकारी हमला हो रहा है, उनके जीने के अधिकार समेत सभी जनवादी अधिकार जिस तरह छीन लिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए स्कूली भवनों को फौरन खाली करवाने और जनताना सरकार द्वारा संचालित स्कूलों पर पुलिस के हमलों को रोकने की मांग करें।। अपनी अस्मिता के लिए तथा कार्पोरेट लूटखसोट की रोकथाम के लिए दण्डकारण्य की जनता द्वारा चलाए जा रहे क्रांतिकारी संघर्ष का समर्थन करें।

26 नवम्बर 2010

जंगल-पहाड़ों को बचाने के लिए पूर्व बस्तर जनता का संघर्ष

नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के अंतर्गत छोटेडोंगर ग्राम पंचायत में आने वाले आमदाईमेट्टा खदान का ठेका सरकार ने नेको जयस्वाल्स कम्पनी को दे रखा है। करीब 30 सालों तक इस पहाड़ के अंदर छिपी लौह खनिज को खोद निकालने की योजना है। इस कम्पनी के द्वारा इस पहाड़ को खोदकर लोहा निकालने की कोशिशें 2007 से ही जारी थीं। इस पहाड़ में खदान खोलने का मतलब छोटेडोंगर, राजपुरा, धनोरा, जमड़ी, मड़मानार, पेरमापाल, वाहकेली, चमेली, तुरुसमेट्टा, मोड़ोहनार, रोहताड़, गौरडंड, बड़गांव आदि गांवों में, जो छोटेडोंगर, मोड़ोहनार और धनोरा पंचायतों में आते हैं, तबाही का न्यौता है। इसके अलावा कई अन्य गांव भी इसके दुष्प्रभाव की जद में आ सकते हैं। स्थानीय जनता इस खदान परियोजना का शुरू से ही विरोध करती आ रही है। नेको (नागपुर इंजनीयरिंग कम्पनी) वही बदमाश कम्पनी है जो कांकेर जिले के चारगांव में भी खदान खोलकर जनता पर कहर ढाने की कोशिश 2003 से कर रही है। जनता के भारी और जुझारू विरोध संघर्ष के कारण वहां पर इस कम्पनी के सारे षड़यंत्र अभी तक नाकाम रहे हैं। चारगांव की तरह इस क्षेत्र में भी नेको कम्पनी के दलालों ने जनता में फूट डालने की कई साजिशें रचीं। लेकिन जनता ने हर साजिश को नाकाम किया। दरअसल आमदाईमेट्टा क्षेत्र की जनता 1990 से ही क्रांतिकारी आंदोलन में संगठित हो चुकी है। अपनी संगठित ताकत के आधार पर ही जनता ने इस प्रतिरोधी संघर्ष को जारी रखा है।

छोटेडोंगर के रामेश्वर मांझी, नोकुल कोर्राम, चमरू मांझी जैसे जन-दुश्मनों और प्रतिक्रियावादियों को इस कम्पनी ने पैसा खिलाकर अपने दलाल बना लिया। इसके अलावा कुछ सरपंचों और परम्परागत गायता-पुजारियों को भी अपने पक्ष कर लिया। इन लोगों के जरिए जनता को अपने पक्ष में जुटाने के लिए इस कम्पनी ने कई पापड़ बेले। लेकिन जनता ने उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। जनता को प्रलोभन देने के इरादे से इस कम्पनी ने आमदाईमेट्टा में मंदिर बनाने के नाम पर दो लाख रुपए देने की पेशकश भी की। इसे भी जनता ने ठुकरा दिया।

2010 के मई महीने में इस कम्पनी के लोगों ने अपने दलालों की मदद से आमदाईमेट्टा में खदान शुरू करने की चुपचाप कोशिशें शुरू कर दीं। पूरे 80 एकड़ में जंगल को काटकर भारी क्षति पहुंचाई। यह सब स्थानीय जनता की जानकारी के बिना ही, लोगों की अनुमति के बिना ही शुरू कर चंद दिनों के अंदर ही इतना नुकसान कर डाला। इसमें वन विभाग की भी मिलीभगत थी। जनता ने इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को दण्डित करने का निश्चय किया। नेको कम्पनी के अधिकारी डीके चौधरी समेत चार लोगों को, वन विभाग के रेंजर और दो गार्डों को और चमरू मांझी को जनता ने गिरफ्तार कर जन अदालत में पेश किया। जन अदालत का आयोजन 19 मई 2010 को हुई थी जिसमें 7 गांवों के 250 लोगों ने भाग लिया। जन अदालत के फैसले के मुताबिक डीके चौधरी, वन विभाग के रेंजर और दलाल चमरू की जनता ने पिटाई कर दी। इन लोगों की एक बोलेरे गाड़ी समेत कुछ मोटार सायकिलों को जनता ने नष्ट कर दिया।

इस तरह आमदाई क्षेत्र की जनता अपनी संगठित ताकत के बल पर शोषक-लुटेरों की साजिशों को नाकाम कर अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा करने में फिलहाल सफल हुई है। हालांकि हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि आज देश भर में कार्पोरेट लूटखसोट का रास्ता साफ करने की मंशा से आपरेशन ग्रीन हंट चलाया जा रहा है। आपरेशन ग्रीन हंट को पूरी तरह हराकर ही हम अपने जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा की गारंटी कर सकते हैं। ★

पाठकों से अपील

अपरिहार्य कारणों से हम 'प्रभात' का नियमित प्रकाशन नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हमें बेहद खेद है। तमाम कोशिशों के बावजूद 2010 का चौथा अंक और 2011 के तीन अंक हम नहीं ला सके। आज दण्डकारण्य का संघर्ष जिस मोड़ पर है और जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में 'प्रभात' के नियमित प्रकाशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। दण्डकारण्य में जारी महान जनयुद्ध में तथा दुश्मन द्वारा किए जा रहे कत्लेआमों में कई कामरेड शहीद हो रहे हैं। शुरू से ही 'प्रभात' की यह परम्परा रही है कि हर शहीद की जीवनी को इसमें प्रकाशित किया जाता रहा है। हालांकि बीच में कई अंक छूट जाने से इस महत्वपूर्ण काम को भी धक्का लगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी शहीदों की जीवनियां हमारे पास उपलब्ध हैं उन सबका संकलन प्रकाशित किया जाए। पाठकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें हमेशा की तरह अपना सहयोग दें। छूटे हुए शहीदों की जीवनियां जरूर लिखकर भेजें। 'प्रभात' के लिए नियमित रूप से संघर्ष की रिपोर्टें लिखकर भेजते रहें।

– सम्पादकमण्डल

'एकीकृत कार्य योजना' से जनता की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं होने वाला!

नक्सल प्रभावित जिलों में 'विकास' के नाम पर केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा बनाई गई 13,742 करोड़ रुपए की 'एकीकृत कार्य योजना' का कल 26 नवम्बर को केन्द्रीय आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अनुमोदन किया था। दो साल तक चलने वाले इस योजना के पहले चरण में 9 नक्सल प्रभावित राज्यों के 60 जिलों के लिए मौजूदा वर्ष 2010-11 के लिए 25 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में प्रत्येक जिले को 30 करोड़ के हिसाब से पैसा आवंटित करते हुए कुल 3,300 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम ने की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट कमेटी ने दो सालों बाद इस योजना की समीक्षा करने का फैसला लिया। शासकों का कहना है कि इन गरीब व आदिवासी जिलों में जहां 50 फीसद से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर 'विकास' करना उनका लक्ष्य है ताकि नक्सलवाद की 'समस्या' का हल किया जा सके। जिन 'बुनियादी सुविधाओं' की बात ये लोग कह रहे हैं उसमें सड़कें सबसे ऊपर हैं और उसके बाद पंचायत भवन, बिजली, स्कूल भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हैं। एक तरफ 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से पिछले एक साल में इन इलाकों में शासकों द्वारा दो लाख से ज्यादा विभिन्न अर्धसैनिक बलों को तैनात कर सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार करते हुए, दूसरी तरफ इन्हीं इलाकों में करोड़ों रुपए का बहाव क्या जनता के हितों में कर रहे हैं? या फिर जनता पर जारी दमनकारी कार्रवाइयों में और ज्यादा तेजी लाने के लिए? इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है। यह घोषणा करते हुए चिदम्बरम ने जोर देकर कहा था कि आगामी मार्च माह तक आवंटित ध न राशि को पूरा खर्च करके 'विकास' दिखाया जाएगा। इस योजना को लागू करने में पुलिस विभाग को भी शामिल करते हुए पुलिस अधीक्षकों को कमेटियों में भागीदार बनाने का फैसला अब तक लागू फासीवादी दमन की नीतियों पर 'विकास' का मुखौटा पहनाने की कोशिश भर है। सड़कों और भवनों का निर्माण क्या 'गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब जनता' के लिए किया जाएगा? या फिर उन सरकारी सशस्त्र बलों की सुविधा के लिए जो जनता के जीने के अधिकार को कुचलते हुए अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब इन इलाकों में कोई भी आदिवासी दे सकता है। एक सच्चाई यह है कि अब तक मौजूद विद्यालयों को सरकारी सशस्त्र बल अपने अड्डों में बदलकर यहां पर शिक्षा के प्रसार के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा खुद ही बन गए हैं। इस बात को छिपाकर करोड़ों रुपयों से शिक्षा की सुविधाएं बनाने का दावा करना धोखा ही है। उल्टी, दस्त जैसी छोटी-छोटी बीमारियों से हर साल सैकड़ों, हजारों की संख्या में बेमौत मर रहे आदिवासियों पर कभी नहीं ध्यान देने वाले शासकों के इस कथन को कि वो इस पैकेज से जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, कोई भी विश्वास नहीं करेगा।

वास्तव में, खासतौर पर पिछले दो महीनों से ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन घोटालों की बात नहीं हुई हो। हजारों करोड़ों का जन धन किस तरह भ्रष्ट राजनेताओं, मंत्रियों, बड़े-बड़े अफसरों, कार्पोरेट मालिकों और नामी मीडिया सम्राटों की जेबों में जा रहा है, देश की जनता साफ तौर पर देख-समझ रही है। माओवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है कहकर बार-बार चिल्लाने वाले शासक और उनका ढोल बजाने वाले ढोंगी बुद्धिजीवी खुद कितने बड़े डकैत हैं, इसे समझने के लिए इतिहास की गहराई में न जाकर कामनवेल्थ गेम्स घोटाला (करीब एक लाख करोड़ रुपए का), 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला (एक लाख छहत्तर करोड़ वाला), आदर्श हाउजिंग सोसाइटी घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला वगैरह कुछ ताजा उदाहरणों पर नजर डालना काफी होगा। कांग्रेस, भाजपा, डीएमके, जनतादल वगैरह सभी शोषक वर्गों की पार्टियां बिना किसी अपवाद के इस अंधाधुंध लूटखसोट में भागीदार बन गईं। इन सभी घोटालों ने इस सड़ी-गली व्यवस्था को जनता की आंखों के सामने नंगा कर दिया है। व्यवस्थीकृत भ्रष्टाचार से ओतप्रोत इस शोषक व्यवस्था को ढहाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इस माओवादी अवधारणा को देश की जनता की स्वीकृति दिन-ब-दिन बढ़ रही है। दरअसल यही शोषक शासक वर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

भ्रष्टाचार की यह ताजातरीन तस्वीर जब लोगों की नजरों में इतनी साफ हो, इस आर्थिक पैकेज के तहत दिए जाने वाले करोड़ों रुपए किनकी जेबों में जाएंगे, इसका

(शेष पेज 49 में...)

जनता की सेवा षड़यंत्र नहीं है! जन पक्षधरता देशद्रोह नहीं हो सकता!!

मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन, वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड नारायण सन्याल और समर्थक पियूष गुहा को देशद्रोह के मामले में आजीवन कारावास; तथा पत्रिका संपादक असित सेनगुप्ता को आठ साल के कारावास की सजाओं का विरोध करो!

24 दिसम्बर को रायपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन, हमारी पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड नारायण सन्याल और व्यापारी पियूष गुहा को फर्जी मामलों में फंसाकर आई.पी.सी., छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून और गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यू.ए.पी.ए.) के तहत आजीवन कारावास की सजा देते हुए फैसला सुनाया। आई.पी.सी. की धारा 124 (देशद्रोह) और 120-ख (षड़यंत्र) के तहत आजीवन कारावास और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून व यू.ए.पी.ए. की कई धाराओं के तहत विभिन्न सजाएं निर्धारित करते हुए बी.पी. वर्मा द्वारा सुनाया गया यह फैसला देश के शासक वर्गों की जन विरोधी व फासीवादी नीतियों का घिनौना उदाहरण है।

हमारी पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड नारायण सन्याल के साथ-साथ पी.यू.सी.एल. के उपाध्यक्ष बिनायक सेन, जो पिछले 30 सालों से जनता की सेवा में निस्वार्थ रूप से समर्पित डॉक्टर तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में सुविख्यात हैं, और कोलकाता के एक व्यापारी पियूष गुहा को आजीवन कारावास की सजा देना देश के शासकों की बेशर्मी भरी करतूत है, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते नहीं थकते हैं। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि डॉक्टर बिनायक सेन को यह सजा सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि वो सरकार की दमनकारी नीतियों और फासीवादी सलवा जुडूम का शुरू से विरोध करते रहे; काला कानून छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून (सी.एस.पी.एस.ए.) के खिलाफ आवाज उठाते रहे; और जायज जन आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे। मई 2007 में जब उन्हें गिरफ्तार कर दो सालों तक जेल में रखा गया था, तब देश भर में तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनवादी तबकों, चिकत्सा जगत् तथा नोबेल लारिएटों की तरफ से बड़े पैमाने पर प्रकट हुए विरोध को भी दरकिनार करते हुए दी गई ये सजाएं देश के फासीवादी शासक गिरोह द्वारा जनवादी, प्रगतिशील और देशभक्तिपूर्ण तबकों को दी जा रही निर्लज्ज और उन्मत्त धमकी है। जन समस्याओं को कानूनी और जनवादी तरीके से उठाना, ईमानदारी से जनता की सेवा करना और सरकारों की जन-विरोधी नीतियों की आलोचना करना - अगर यही देशद्रोह है तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस देश में लागू 'लोकतंत्र' किस ढंग का है और उससे जनता को कितना खतरा है। दुनिया भर में कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी प्रत्रिका - 'ए वर्ल्ड टु विन' का हिंदी संस्करण संभालने वाले असित सेनगुप्ता, जो अवैध गिरफ्तारी के बाद पिछले तीन सालों से जेल में हैं, को भी इसी दिन एक और फैसले में जिला अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायमूर्ति ओ.पी. गुप्ता ने आठ साल की सजा सुनाई, जोकि प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। हाल ही में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, डी.जी.पी. विश्वरंजन, बस्तर आई.जी. लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एस.पी. कल्लूरी के गिरोह ने 'मां दंतेश्वरी आदिवासी स्वाभिमानी मंच' के नाम से पर्चे छापकर जनवादी बुद्धिजीवी हिमांशु कुमार व अरुंधति रॉय के साथ-साथ पत्रकार एन.आर.के. पिल्लै, अनिल शर्मा और यश्वंत राव की हत्या करने की खुलेआम धमकी दी जो उनकी फासीवादी नीतियों का हिस्सा है।

हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व 73 साल के उम्रदराज कॉमरेड नारायण सन्याल को छत्तीसगढ़ की दमनकारी रमन सरकार ने पिछले पांच सालों से जेल की कालकोठरी में बंद कर कई झूठे मुकदमों में फंसाकर रखा है। वो 1968 से शुरू कर पिछले चार दशकों से ज्यादा समय से देश की दबी-कुचली जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेता हैं। उन्हें जेल के भीतर गंभीर बीमारियों के साथ-साथ कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। आतंकी सोनिया-मनमोहन सिंह-चिदम्बरम-रमन सिंह गिरोह जहां एक तरफ क्रांतिकारी नेताओं को षड़यंत्रकारी तरीके से उठा ले जाकर फर्जी मुठभेड़ों में हत्या कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फर्जी मामलों में फंसाकर काले कानूनों के तहत कठोर सजाएं दिलवा रहा है।

छत्तीसगढ़ के विधायकों को माओवादी प्रचार की सीडी भेजने के मामले में विगत 29 जुलाई को सुनाए गए एक फैसले में हमारी पार्टी कार्यकर्ता कॉमरेड मालती उर्फ शांतिप्रिया व मजदूर सुरेंद्र कोसरिया को छत्तीसगढ़ सरकार ने झूठी गवाहियों के आधार पर दस साल की सजा दिलवाई। झारखण्ड के रांची जेल में बंद हमारी पार्टी के एक और पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड अमिताभ बागची और बंगाल राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड कार्तिक को भी एक फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए सरकार ने उम्र कैद की सजा

सुनवाई। आंध्रप्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर को अलिपिरी मामले (आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू पर किए गए हमले के मामले) में झूठी गवाही दिलवाकर कॉमरेड पाण्डूरंगा रेड्डी उर्फ सागर समेत चार लोगों को सात साल की सजा दिलवाई। और भी कई जगहों पर अनगिनत क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और आम जनता को इन शोषक वर्गीय अदालतों ने फांसी से लेकर विभिन्न किस्म की सजाएं सुनाईं। वरिष्ठ व उम्रदराज नेता तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कॉमरेड्स सुशील रॉय व कोबड गांधी के साथ-साथ शोभा, पतितपावन हलदार, प्रमोद मिश्र, विजय, आशुतोष, बलराज, चिंतन, बिमान, बिधान, चंडी सरकार, बालगणेश आदि हजारों कॉमरेडों व लोगों को, सांस्कृतिक संगठन 'झारखण्ड अभेन' के नेता जीतन मराण्डी आदि जन नेताओं को लम्बे समय से जेलों में बंदकर, उनकी जमानत की अर्जियों को नामंजूर करते हुए, उन पर एक के बाद एक फर्जी मामला दर्ज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की जेल में कॉमरेड स्वपनदास को जेल प्रशासन ने चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कर कत्ल कर दिया जोकि यू.ए.पी.ए. के तहत पहली हत्या थी।

हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं तथा श्रमशक्ति को वेदांता जैसी साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल जैसे दलाल पूंजीपतियों के हाथों लुटवाने की ठान लेकर यू.पी.ए. सरकार ने इस मनमानी लूट की राह में बाधा के रूप में खड़े माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया। इसके तहत ही वह अपने प्रचार साधनों के जरिए जहरीली दुष्प्रचार-मुहिम चला रही है। अगस्त 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ बर्बर हमला चलाया जा रहा है जिसके तहत हजारों पुलिस व अध सैनिक बलों को उतारकर, खासकर आदिवासियों का कत्लेआम किया जा रहा है। यह हमला साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में तथा संपूर्ण समर्थन से चल रहा है। हमारे देश को साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के शिकंजे से आजाद कर मजदूर-किसान एकता के आधार पर जनवादी वर्गों की जन सत्ता स्थापित करने के महान लक्ष्य से संघर्षरत हमारी पार्टी को आतंकवादी और देशद्रोही के रूप में चित्रित करने के लिए लुटरे शासक नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। नित नए घोटालों में खुद भागीदार बनकर, जनता के खून-पसीने को चूसकर, लाखों करोड़ों रुपए का जनधन स्विस बैंकों में छिपाने वाले मंत्रियों, राजनेताओं, बड़े पूंजीपतियों और उनके दलालों पर, जो बेखौफ घूमते हैं, देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाता? भोपाल त्रासदी के जिम्मेदारों और दोषियों को बचाने वालों पर षड़यंत्र का मामला क्यों नहीं चलाया जाता? दबी-कुचली जनता की मुक्ति की खातिर संघर्ष करना देशद्रोह कैसे बनता है? जन आंदोलनों के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए अपनी आवाज व कलम उठाने वाले षड़यंत्रकारी कैसे हो सकते हैं?

ये फैसले शासकों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिससे कि वे अपनी जन-विरोधी, देशद्रोहपूर्ण व अनैतिक नव-उदार आर्थिक नीतियों को बेरोकटोक जारी रख सकें। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में देश में फासीवाद और ज्यादा घातक रूप धारण करने वाला है। जो लोग नादानगी से यह विश्वास रखते हैं या इस धोखे में रहते हैं कि इस देश में जो चल रहा है वह लोकतंत्र है, उनकी इन फैसलों से आंखें खुलनी चाहिए। ऊपरी तौर पर देश का शासक गिरोह माओवादी आंदोलन को अपने हमले का निशाना भले ही घोषित कर रहा हो, दरअसल इस फासीवादी हमले के निशाने पर तमाम प्रगतिशील व जनवादी शक्तियां हैं जो देश के हितों तथा जन की भलाई के प्रति समर्पित हैं। अत: हमारी पार्टी तमाम जनता से यह अपील करती है कि इस हमले के खिलाफ एकजुटता से खड़े होकर, दृढ़तापूर्वक लड़कर हरा दिया जाए।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा लागू काला कानून होमलैण्ड सेक्यूरिटी की तर्ज पर ही देश की कॉर्पोरेट-दलाल सरकारें गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून (सीएसपीएसए), मकोका, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (एएफएसपीए) आदि काले कानूनों के तहत जन आंदोलनों और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। मक्का मस्जिद, मालेगांव, अज़्मेर शरीफ आदि बम विस्फोटों में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें लेने वाले भगवा आतंकवादियों को तथा एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला आदि अनगिनत मामलों में लिप्त घोटालेबाजों और राजनीतिक दगाबाजों को आज तक किसी भी अदालत ने कोई सजा नहीं सुनाई। यही आदलतें क्रांतिकारियों, जन आंदोलन के नेताओं, जनवादियों, कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों से जुड़े कार्यकर्ताओं को उपरोक्त काले कानूनों के तहत सजाएं सुना रही हैं।

आइए, इन सजाओं का खण्डन करें। इनकी और देश के जेलों में बंद तमाम राजनीतिक बंदियों, क्रांतिकारियों व संघर्षशील जनता की नि:शर्त रिहाई की मांग करें।

24 दिसम्बर 2010

(... आखिरी पन्ने का शेष)

में... हर क्षेत्र में साम्राज्यवादियों की घुसपैठ बढ़ गई है। देश के सामंती व दलाल पूंजीपति शासकों ने उनके इशारों पर नाचते हुए देश की अत्यधिक आबादी को गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बीमारी, बेरोजगारी, महंगाई, भेदभाव, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न वगैरह अंतहीन समस्याओं के भंवर में झोंक दिया। विकास के लम्बे-चौड़े आंकड़े पेश करने वाले शासकों ने पिछले 63 सालों में 77 प्रतिशत जनता को 20 रुपए से भी कम आमदनी से जीने पर मजबूर कर दिया। वहीं टाटा, जिंदल, एस्सार, अंबानी जैसे 100 अरबपतियों के पास इतनी सम्पत्तियां जमा हो गईं जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत के बराबर है। विकास के नाम पर बने बड़े बांधों, खदानों, भारी उद्योगों और अभयारण्यों के लिए अब तक देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघरबार कर दिया गया। इनमें 40 प्रतिशत आदिवासी हैं जबकि देश की आबादी का वे सिर्फ 8 प्रतिशत ही हैं। तथाकथित 'विकास' परियोजनाओं की मार सबसे ज्यादा सहनी पड़ रही है आदिवासियों को, दलितों को और अन्य गरीब तबकों को। शहरों में मजदूरों की हालत और भी खराब है। आज भी उन्हें 18वीं सदी की कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। 10 से 16 घण्टों तक काम करवाने का प्रचलन आज आम होता जा रहा है। न्यूनतम वेतन कानून कागजों के अंदर ही दबकर रह जाता है। मुसलमानों व ईसाइयों पर हिंदू फासीवादी धर्मोन्मादियों के हमलों व हत्याकाण्डों से वे असुरक्षा में जीने को मजबूर हैं। कश्मीर व पूर्वोत्तर के इलाकों की जनता पर भारतीय विस्तारवादी शासकों के सैन्य बलों द्वारा अमानवीय दमन का सिलसिला जारी है।

इन हालात का जहां भी विरोध हुआ या इसके खिलाफ आवाज उठी तो बस, राज्य टूट पड़ता है लाठियों और गोलियों के साथ। राज्य की तमाम दमनकारी मशीनें - यानी पुलिस, अर्ध सैनिक व सैन्य बल मेहनतकश मजदूर-किसानों, मध्यमवर्ग के कर्मचारियों, महिलाओं, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर हिंसा, आतंक व बर्बरता बरत रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में सुविख्यात माओवादी कथन - 'अगर जन सेना नहीं है तो जनता के पास कुछ नहीं है' उसूली तौर पर ही नहीं, बल्कि अमली तौर पर भी वास्तविकता में बदल गया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुई भारत की नई जनवादी क्रांति की, खासकर महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह के बाद से देश के व्यापक इलाकों में जारी कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध की धारावाहिकता में ही यह सेना - जन मुक्ति गुरिल्ला सेना (पीएलजीए) - की स्थापना हुई जिसकी अब 10वीं सालगिरह है। देश में सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंककर मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर छोटे व मध्यम पूंजीपतियों से युक्त संयुक्त मोर्चे का शासन कायम करना इस जनसेना का राजनीतिक कर्तव्य है।

आइए, यह देखें कि इस सेना के सहारे दण्डकारण्य की जनता ने क्या-क्या हासिल किया -

1) गांव और इलाका स्तर पर लुटेरे वर्गों की सत्ता को ध्वस्त कर जनता की राजसत्ता कायम कर ली गई। *जनताना सरकार* की ये संस्थाएं बुनियादी रूप से ही सही, जनता के चौमुखी विकास की पहलकदमी लेकर काम कर रही हैं।

2) तीन लाख एकड़ से ज्यादा वन भूमि और सामंती वर्गों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया जिसकी बदौलत आज दण्डकारण्य के संघर्ष इलाकों में भूमिहीन किसान कोई नहीं रह गया।

3) पुलिस, वन विभाग, राजस्व विभाग, खदान माफिया, लकड़ी माफिया, सूदखोर, तेंदुपत्ता ठेकेदार, पेपरमिल प्रबंधन - इन सभी के जुल्म, लूटखसोट, महिलाओं का यौन शोषण आदि पर रोक लगा दी गई।

4) दण्डकारण्य में छिपी हुई अपार प्राकृतिक संपदाओं को लूटने की टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, टेक्सास पावर कार्पोरेशन, वेदांता जैसी 'देशी' व विदेशी कार्पोरेट कम्पनियों की कोशिशों को नाकाम किया गया।

5) 'विकास' के नाम पर आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन करने वाली सरकार की ढोंगी नीतियों का विरोध व प्रतिरोध किया गया जिससे पल्लामाड़ से लेकर सूर्जागढ़ तक कई जगहों पर खदान माफिया को उलटे पांव भागना पड़ा।

6) जनता पर शोषण व लूटखसोट जारी रखने के लिए तैनात दमनकारी व अत्याचारी पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों को सैकड़ों की संख्या में सफाया कर उनसे करीब 575 अत्याधुनिक हथियार छीन लिए गए ताकि जनता को हथियारबंद किया जा सके। मुरकीनार, उरपलमेट्टा, रानीबोदली, कोरकोट्टी, लाहेरी, कोंगेरा, खासकर ऐतिहासिक ताड़िमेट्ला आदि हमले गुरिल्ला युद्ध के विकासक्रम को दर्शाते हैं। जनता के कई बहादुर बेटों व बेटियों ने अपनी शहादत से इतिहास में खास स्थान प्राप्त किया।

7) केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 2005 में सलवा जुडूम के नाम से

विनाशकारी व प्रति-क्रांतिकारी अभियान चलाया था। इसमें पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों व एसपीओं ने एक हजार से ज्यादा आदिवासियों की हत्या कर, सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर, 600 से ज्यादा गांवों को कब्रगाहों में बदलकर, हजारों लोगों को ढोंगी राहत शिविरों में घसीट दिया। फिर भी जनता नहीं झुकी। हर कदम पर प्रतिरोध का झण्डा बुलंद कर बस्तर की जनता ने इसी सेना की अगुवाई में सलवा जुडूम को हराकर इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया।

लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं...

देश की तमाम प्राकृतिक संपदाओं की अंधाधुंध कार्पोरेट लूट के रास्ते में रोड़ा बने माओवादी आंदोलन का उन्मूलन करने की मंशा से लुटेरे शासक वर्गों ने साम्राज्यवादियों की शह पर ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से एक भारी व पाशविक देशव्यापी हमला छेड़ दिया है जो दरअसल 'जनता के खिलाफ युद्ध' है। इसे हर हाल में पराजित करना है और इसके लिए पीएलजीए को हर मायने में ताकतवर बनाना होगा। शासकों की भ्रामक व झूठे विकास की योजनाओं को ठुकराकर 'आत्मनिर्भरता' पर आधारित जन अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। इसके बचाव व सुचारू संचालन के लिए नौजवानों को पीएलजीए में बड़ी तादाद में भर्ती होना होगा। दण्डकारण्य में मौजूद अपार प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करने कई बड़े व विदेशी पूंजीपतियों की कम्पनियों ने पूरा जोर लगाए रखा है। इससे यहां की जनता का बड़े पैमाने पर विस्थापन होने का खतरा है। इसके खिलाफ जारी लड़ाई में पीएलजीए को अगुवा भूमिका निभानी होगी ताकि जनता के अस्तित्व को बचाया जा सके।

जन मुक्ति छापामार सेना की 10वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर हम जनवादी बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों, मीडियाकर्मियों, छात्र-नौजवानों, अध्यापकों और मजदूर-किसानों से अपील करते हैं कि वे दण्डकारण्य जनता के संघर्ष के समर्थन में मजबूती से खड़े रहें तथा लुटेरों के फासीवादी आक्रमण - ऑपरेशन ग्रीन हंट का विरोध करें। ★

(... पेज 45 का शेष)

अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वास्तव में यह घोषणा करते समय शासकों को डर लगना चाहिए था कि आज की परिस्थिति में ऐसे आर्थिक पैकेजों से जनता का विकास होने की बात करने से लोग हंस पड़ेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया, जिन्होंने इस एकीकृत कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की थी, और चिदम्बरम जिन्होंने इसे स्वीकृति दी, साम्राज्यवादी कार्पोरेट संस्थाओं की पूरी वफादारी से सेवा कर चुके हैं। इस शासक गिरोह की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह अपनी उम्र का आधा से ज्यादा हिस्सा साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं की सेवा में गुजार चुके हैं। ऐसे में यह समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं से किनके हित पूरे होने वाले हैं। सरकारें एक तरफ देश के आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूटखसोट का रास्ता साफ करते हुए कॉर्पोरेट कम्पनियों के साथ दसियों करोड़ों रुपए के एमओयू पर दस्तखत कर रही हैं जिससे आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। दूसरी ओर, उन समझौतों का जनता के सामने खुलासा करने और उन्हें रद्द करने की मांग, जो देश की जनता और जनवादियों की तरफ से उठाई जा रही है, को अनसुना करते हुए 'विकास' की रट लगाना हास्यास्पद है।

हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) इस जन विरोधी 'एकीकृत कार्य योजना' का कड़ा विरोध करती है। हम मानते हैं कि यह केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से लागू फासीवादी दमन अभियान का ही हिस्सा है और उसमें सहायता करने वाली है। यह कहना कि इससे पिछड़े इलाकों का विकास होगा, बहुत बड़ा ढोंग है। अगर इन व्यापक वन इलाकों में आदिवासियों और शोषित जनता के विकास के प्रति जरा भी ईमानदारी है तो सरकारों को उन्हें जल-जंगल-जमीन पर अधिकार देना चाहिए; बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपतियों की कम्पनियों के साथ किए गए एमओयू को रद्द कर देना चाहिए; भारी बांधों, खदानों, अभयारण्यों, भारी-भरकम स्टील प्लांटों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के चलते लाखों लोगों को विस्थापित करने वाली सारी योजनाओं को वापस लेना चाहिए; आदिवासियों के नरसंहारों से चलाए जा रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट को फौरन बंद कर देना चाहिए।

हमारी इस मौके पर यह भी मांग है कि कामनवेल्थ गेम्स, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श हाउजिंग सोसाइटी घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला आदि में लिप्त राजनेताओं, मंत्रियों व कॉर्पोरेट घरानों के मालिकों को; और मालेगांव, अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद आदि बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकी नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ★

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल मिलिटरी कमिशन

ऑपरेशन ग्रीन हंट को हराने के संकल्प से जनयुद्ध को तेज करो!

'जल-जंगल-जमीन पर जनता का अधिकार हो' के नारे से

प्राकृतिक सम्पदाओं की कार्पोरेट लूटखसोट के खिलाफ एकजुटता से संघर्ष करो!!

जन मुक्ति छापामार सेना की दसवीं वर्षगांठ क्रांतिकारी उत्साह के साथ मनाओ!!

हमारी पार्टी - भाकपा (माओवादी) के संस्थापक नेता कॉमरेड्स चारू मजुमदार और कन्नाई चटर्जी के सपनों को साकार करते हुए, वीर शहीद कॉमरेड्स श्याम, महेश और मुरली के बलिदान की पहली बरसी के दिन, 2 दिसम्बर 2000 को, हमारे देश में पहली बार दबे-कुचले लोगों की एक सेना का जन्म हुआ। भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में काम करने वाली इस जन सेना का नाम है जन मुक्ति छापामार सेना, यानी पीएलजीए। हमारे भारत में शोषण, उत्पीड़न, जुल्म, अत्याचार, अन्याय और पराए शासन के खिलाफ विभिन्न जन समुदायों और तबकों की जनता सदियों से संघर्ष करती रही। पहले ब्रितानी उपनिवेशवादियों के खिलाफ और 1947 के बाद सामंती-दलाल पूंजीवादी शासक वर्गों के खिलाफ भी अनगिनत विद्रोह हुए और हजारों वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। हमारी यह जन सेना उन सभी संघर्षों की विरासत की धारावाहिकता में ही पैदा हुई जिसकी अब 10वीं वर्षगांठ है।

कामरेड श्याम

कामरेड महेश

कामरेड मुरली

हमारी पार्टी की अगुवाई में दण्डकारण्य में क्रांतिकारी संघर्ष को शुरू हुए अभी 30 बरस पूरे हो चुके हैं। पीएलजीए की स्थापना से पहले यहां गुरिल्ला दस्ते और कार्यकर्ता ही सांगठनिक और फौजी दोनों कार्यभारों को पूरा करते थे। पीएलजीए की स्थापना के बाद से कमिशन, कमानों और गुरिल्ला फॉर्मेशनों का गठन हुआ। क्रांतिकारी जनयुद्ध को सुनियोजित तरीके से विकसित करते हुए विभिन्न कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों का संचालन कर दुश्मन के कई दमनात्मक अभियानों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। वर्ष 2000 के बाद दण्डकारण्य में माओवादी जनयुद्ध ने जिस रफ्तार से प्रगति की और जनताना सरकार के रूप में जनता की राजनीतिक हुकूमत का जो विकास हुआ, उसमें पीएलजीए ने अहम भूमिका निभाई।

अपनी मेहनत से खाने के अनाज से लेकर देश की तमाम सम्पदाओं का सृजन करके भी पेट भर खाने के लिए, तन भर कपड़े के लिए और सिर छुपाने के लिए छत के लिए तरसने वालों की सेना है यह। इस सेना की जब 10वीं बरसी होने वाली है तो यह निश्चित रूप से देश के 90 प्रतिशत मेहनतकशों और उनके शुभचिंतकों के लिए खुशी का अवसर है। आखिर मजदूर-किसानों की इस सेना का औचित्य क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए भारत के कम से कम पिछले 63 साल के इतिहास पर नजर डालनी होगी। हमारा प्यारा भारत जो करीब 200 सालों तक अंग्रेजों के शासन में लूटखसोट का शिकार था, पिछले 63 सालों से एक अजीबोगरीब व झूठे लोकतंत्र का चोला ओढ़ा हुआ है। स्वतंत्रता के नाम पर, जैसे कि भगतसिंह ने काफी पहले ही आगाह किया था, हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से देसी लुटेरों के हाथों में आ गई। टाटा, बिड़ला जैसे दलाल पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली और साम्राज्यवाद से सांठगांठ करने वाली कांग्रेस ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। शोषण, उत्पीड़न, जुल्म, अन्याय कुछ नहीं बदले। बस, उनके स्वरूप में बदलाव हुआ। साम्राज्यवादियों का प्रत्यक्ष शासन तो समाप्त हुआ, लेकिन परोक्ष रूप से उनकी लूटखसोट और दखलंदाजी बेतहाशा बढ़ गई। हमारे देश की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक जीवन में, कृषि, संस्कृति व जल-जंगल-जमीन

(शेष पेज 48 में...)

पीएलजीए (जन मुक्ति छापामार सेना) की 10वीं वर्षगांठ जिंदाबाद!